₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

अप्रैल 2026

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.- BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PS.-35

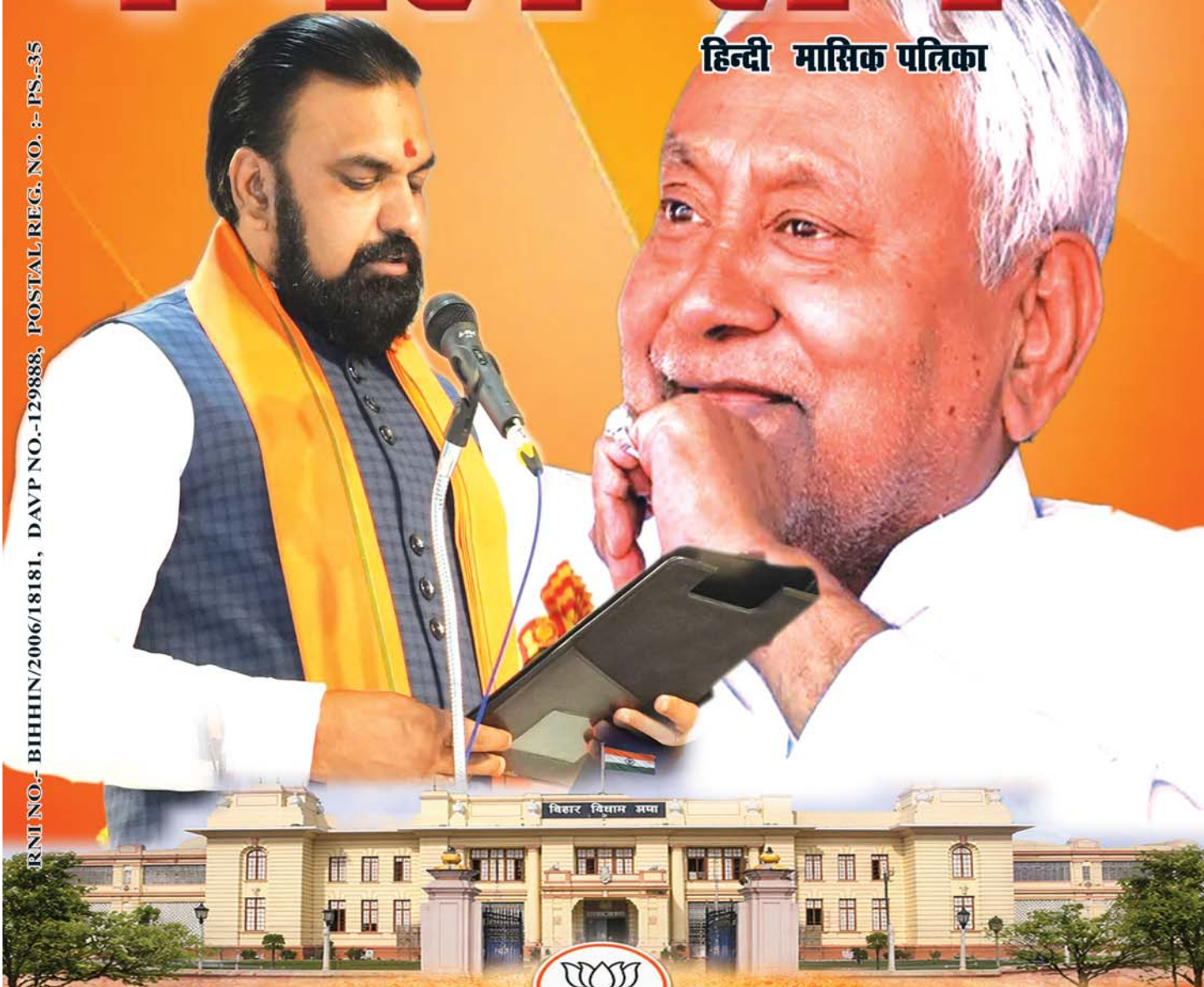

बिहार भाजपा में सम्राट उदय

जन-जन की आवाज है केवल सच

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

www.kewalsach.com

www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,
कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

समृद्ध बिहार

खुशहाल बिहार

बिहार उन्नति, समृद्धि एवं विकास के पथ पर निरंतर बढ़ते रहे

इन्ही शुभकामनाओं के साथ

बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बनने पर श्री सम्राट चौधरी जी को एवं

उपमुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी एवं श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव जी को

श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट

की ओर से हार्दिक बधाई।

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House
No.-28/14, Road No.-14,
kankarbagh, Patna- 8000 20
(Bihar) Mob.-09431073769
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave,
Second Floor, Flat No. 2B,
Near-firing range,
Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha,
A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla
Shastri Nagar, New Delhi - 110052
Mob.- 09868700991,
09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue,
Near- md. Ali Park,
Kolkata- 700073
(West Bengal)
Mob.- 09433567880
09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

योजना खा गई खजाना

सत्ता पर स्थायी रूप से विराजमान रहने के लिए सरकारी खजाना को खाली कर देना आज के राजनेताओं के लिए छोटी बात बनती जा रही है। 2024 के झारखंड राज्य के विधानसभा चुनाव में मोदी एवं शाह को चुनावी अखाड़े में परास्त करने एवं दोबारा सरकार बनाने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने ''**मईया योजना**'' की शुरूआत करके 1000/-रू. बांटना शुरू कर दिया और चुनाव भी जीत लिया लेकिन सरकार के गठन के बाद झारखंड प्रदेश का सरकारी खजाना खाली हो गया है जिसकी वजह से प्रदेश का विकास बाधित हो रहा है और कई महत्वकांक्षी योजना फंड के अभाव में प्रभावित हो रही है। कुछ ऐसा ही हाल है बिहार का जहां मोदी एवं नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार से विपक्ष को उखाड़ने के लिए प्रति महिला 10000/-रू. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बांट दिया और प्रलयकारी जीत दर्ज करके विपक्ष को उखाड़ ही दिया लेकिन आज बिहार का भी खजाना खाली है। भले ही खजाना खाली है पर सत्ता प्राप्त कर लेने का गुमान आज भी कायम है और स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और वेतन के सिवा विकास की गति धीमी हो गई है। योजना जनहित के कल्याण के लिए खजाने के हिसाब से बनना चाहिए न कि सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए बने अन्यथा आमजनों का टैक्स का पैसा राजनेताओं पर खर्च होता रहेगा।

— — — — — —

ब्रजेश मिश्र, संपादक
8340360961, 9431073769

सत्ता में लगातार बने रहने के लिए झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन ने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने ''**झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना**'' शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य भर की महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार बनाने में कामयाब तो हो गये लेकिन सरकारी खजाना खाली हो गया। मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना में सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने दिए जाऐंगे तो दूसरी तरफ अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की राशि मिलेगी। सरकार यह पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी। सरकार बनाने में कामयाबी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिल गयी लेकिन सरकार का खजाना खाली हो गया। सरकार का काम जनबुनियादी समस्याओं को समाप्त कर जन-सारोकार को सामाजिक दृष्टिकोण से सहायता पहुंचाना है लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए विपक्ष को चुनावी पटखनी देने के लिए किसी भी प्रकार का घोषणा या योजना शुरू करके बेरोजगार युवाओं को बुनियादी खर्चों के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। लड़कों को 1500 रुपये प्रति माह और लड़कियों को 2500 रुपये प्रति माह मिलते हैं, जिससे आर्थिक तनाव कम होता है। यह योजना युवाओं, विशेषकर महिला लाभार्थियों के बीच वित्तीय आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करती है। सरकार सामाजिक दायित्वों का ख्याल रखने के लिए विधवाओं को सुरक्षा के मद्देनजर कुछ राज्य या विशेष सरकारी योजनाएं कल्याण या पुनर्वास कार्यक्रमों के तहत विधवाओं को रू० 30,000/- की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। इसके लिए आमतौर पर विशिष्ट शर्तों को पूरा करना और आधिकारिक राज्य पोर्टल या कार्यालयों के माध्यम से आवेदन करना आवश्यक होता है। सरकार जितना दावा करती है उसको पूरा सही समय पर करने लगे तो सच में देश के भीतर रामराज की स्थापना हो जायेगी। लड़कियों के लिए सरकारी योजनाएं उनकी शिक्षा, आत्मनिर्भरता और बेहतर जीवन सुनिश्चित करती हैं। 2005 से 2025 तक लगातार सरकार में रहने के बाद भी नीतीश कुमार को लगा कि कहीं विपक्ष के माई-बहन योजना चुनाव में मुद्दा बन गया तो उनकी साख मिट्टी में मिल जायेगी। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से पूछा जाता था कि आप कैसे इसका भुगतान करेंगे लेकिन विपक्ष का समुचित जवाब नहीं मिलने और प्रशांत किशोर के जनसुराज के बढ़ते दवाब ने नीतीश कुमार को ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ा। बिहार सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल '**मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना**' को मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के हर परिवार से एक महिला को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिससे वह अपनी पसंद का उद्यम शुरू कर सके। 29 अगस्त 2025 को अनुमोदित बिहार सरकार की यह पहल, महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री मोदी 26 सितंबर 2025 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री बिहार भर की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित किया, जिसकी कुल राशि 7,500 करोड़ रुपये है। इसी वजह से बिहार सरकार का खजाना खाली है और केन्द्र से सहायता की उम्मीद लगाकर बठी है। विपक्ष के द्वारा माई-बहन योजना के तहत 2500/-प्रतिमाह देने का वादा किया जा रहा था क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार इसी प्रकार की योजना की वजह से दोबारा सत्ता में आई थी। मुख्यमंत्री राजश्री योजना राजस्थान सरकार द्वारा बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक सरकारी योजना है। इस योजना के तहत, जन्म से लेकर शिक्षा तक विभिन्न चरणों में रू०50,000/- तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बिहार भारत के सबसे तेजी से विकासशील राज्यों में से एक है। गठबंधन की सरकार को 2025 में विजयी बनाने के लिए सरकार पर वित्तीय बोझ को बढ़ा लिया गया है लेकिन 2025-2026 वर्ष के लिए बिहार की जीडीपी वृद्धि दर 22% रहने का अनुमान है। बिहार मुख्य रूप से सेवा आधारित राज्य है, हालांकि कृषि और उद्योग का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार सरकार का खजाना खाली है और केन्द्र की सरकार पर पूर्णरूपेण आश्रित है। सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दल जनता से बड़े वादे कर लेती है और कुछ विशेष योजना बनाकर उन्हें पैसे भी प्रदान कर देती है लेकिन सरकार के गठन के बाद वहीं योजना सरकार के लिए गले का फांस बन जाये तो अपने विचारों से समझौता करना ही पड़ता है। बिहार एवं झारखंड दोनों राज्यों का खजाना खाली रहने की वजह से विकास का कार्य बाधित है तथा कई महीने से वेतन पर भी अफरा-तफरी मचा हुआ है। राजनीति का पत्तन इस कदर हावि होता जा रहा है कि सत्ता पाने के लिए अपराध एवं भ्रष्टाचार से भी हांथ मिलाना पड़ जाये। गठबंधन की राजनीति का बढ़ता वर्चस्व सरकारी व्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है और सरकारी खजाना को खाली किया जा रहा है।

मार्च 2026

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
द्वारा:- ब्रजेश मिश्र
पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल
kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

गृहयुद्ध

ब्रजेश जी,

आपका संपादकीय सच में आमलोगों के जगाने के लिए काफी उपयुक्त होता है। मार्च 2026 अंक का संपादकीय ''भरोसा कल-आज और कल'' में भारतीय राजनीति पर सटीक व्यंग्यात्मक ढ़ंग से पाठकों के बीच रखा है। वैसे तो आजादी के बाद ही राजनीति में भरोसा का मतलब आत्महत्या ही होता है लेकिन 2014 के बाद गिरगिट भी उतना रंग नहीं बदलती जितने राजनेता बदलते हैं। सही मायने में आलेख का मतलब ही होता है लोगों को जागरूक करना और सही का सही और गलत को गलत कहना।

✦प्रेमसागर पाण्डेय, मौर्य बिहार कॉलोनी,पटना

महिला दिवस

ब्रजेश जी,

''महिलाओं की भागीदारी से ही सशक्त होगा राष्ट्र'' खबर में केवल सच पत्रिका ने मार्च 2026 के अंक में महिलाओं को समर्पित किया है। विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रतिभा का लोहा मनवा रही भारतीय महिलाएं वास्तव में सम्मान की हकदार हैं। डॉ० ब्रहानंद राजपूत की इस खबर ने महिलाओं के सकारात्मक प्रयास को सही ढंग से पाठकों के समक्ष रखा है जो बधाई योग्य है। राजनीति एवं भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली पत्रिका केवल सच रंगीन पृष्ठों में प्रकाशित होना चाहिए।

✦हरप्रीत सिंह, सिटी चौक, करोलबाग, दिल्ली

विरासत

मिश्रा जी,

केवल सच, पत्रिका के मार्च 2026 अंक में अमित कुमार का आवरण कथा ''**बिहार की राजनीति में विरासत बचाने का जंग!**'' में लालू यादव एवं नीतीश कुमार को अपने बेटे के कैरियर को लेकर चल रही उठापटक में नीतीश कुमार का बेटा पूर्णरूपेण राजनीति में परिपक्व नहीं दिखते जबकि लालू यादव ने अपने पुत्र तेजस्वी यादव को रामविलास पासवान ने अपने पुत्र चिराग पासवान को सेट करा दिया परन्तु निशांत का राजनीतिक कैरियर आज भी पेचिदा है। बिहार की राजनीति पर बहुत ही बेहतरीन खबर को पूरी गंभीरता से लिखा गया है जो पठनीय एवं सोचनीय लगा।

✦ दिवाकर वर्मा, टावर चौक, नवादा

गठजोड़

मिश्रा जी,

भ्रष्टाचार पर दबंग पत्रकारिता का परिचय लगातार आपकी पत्रिका दे रही है। केवल सच पत्रिका के मार्च 2006 अंक में बिहार में उच्च शिक्षा के काला सच को पिछले कई महीनों से प्रकाशिक करके राजभवन? शिक्षा विभाग और कुलपति का सारा चिट्ठा को सार्वजनिक करके सरकार की नीति को कठघरे में खड़ा कर दिया है। शशि रंजन सिंह एवं राजीव शुक्ला की संयुक्त खबर ''शिक्षा माफिया और राजभवन का गठजोड़'' में आपने पूरी सच्चाई को प्रमाण के साथ पाठकों के बीच रख दिया है की किस प्रकार राजभवन और शिक्षा विभाग बच्चों के भविष्य का गला घोट रहा है। ऐसी खबरों को प्राथमिकता से प्रकाशित करें।

✦ मोहित सिंह, घंटा घर, भागलपुर

2025

संपादक जी,

लंबे समय के बाद आपकी राजनीतिक खबर को पढ़ने को मिला। मार्च 2026 अंक में आपकी खबर ''**2025 नीतीश कुमार फिनिश**'' में बिहार की राजनीति पर केन्द्र का बढ़ता दबदबा के साथ नीतीश कुमार के दो दशक की सक्रिय राजनीति को भाजपा ने चुटकी में मसल दिया। पिछले 21 वर्षो से बिहार की गद्दी पर विराजमान नीतीश कुमार को एक झटके में उखाड़कर फेकने का कार्य के कूटनीति को बहुत ही सूझ-बूझ से लिखा है और इसके कारणों की भी जमकर चर्चा किया है। सच में भाजपा अपने मिशन में कामयाब हो चुकी है।

✦ राकेश सिंह, विजय नगर, कंकड़बाग, पटना

एक पर एक

संपादक जी,

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2026 पर संजीव कुमार झा की खबर ''पश्चिम बंगाल इतिहास दोहरायेगा या बदलाव लायेगा'' में हकीकत से रूबरू कराता है वहीं यूपी के भीतर चल रही राजनीति पर संजय सक्सेना की खबर ''बीजेपी से नाराज ब्राह्मणों पर सभी दलों का दांव'' में यूजीसी सहित अन्य मुद्दे पर सटीक समीक्षात्मक बातों को प्रामणि तथ्य के साथ लिखा है। दिल्ली से संजय सिन्हा की खबर ''यूजीसी के नये नियम से खंडित हुई मोदी की लोकप्रियता'' में सारी सच्चाई को रखा गया है। यह अंक वास्तव में संग्रहनीय है।

✦ कौशल राय, जी.बी. रोड, गया बिहार

अन्दर के पन्नों में

30

36

74

78

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 20 | अंक:- 239 | माह:- अप्रैल 2026 | मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

श्रद्धेय गोपाल मिश्र

श्रद्धेय सुषमा मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका (एडमिन) 7782053204

सुरजीत तिवारी 9431222619

निलेन्दु कुमार झा 9431810505, 8210878854

सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917

डॉ० शशि कुमार 9507773579

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350

अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

उप-संपादक

प्रसुन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186

ब्रजेश सहाय 7488696914

ललन कुमार 7979909054, 9334813587

राजनीतिक संपादक

सुमित रंजन पाण्डेय 7992210078

संतोष कुमार यादव 8210487516

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565

काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829

कुमार अनिकेत 9431914317

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485

चीफ क्राइम ब्यूरो

सैयद मो० अकील 9905101976, 8521711976

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०):- श्रीधर पाण्डेय 9470709185

(म०):-

(ग्रा०) :- मुकेश कुमार 9473038020

बाढ़ :-

भोजपुर :- गुड्डू कुमार सिंह 8789291547

बक्सर :- बिन्ध्याचल सिंह 8935909034

कैमूर :-

रोहतास :-

:-

गया (श०) :-

(ग्रा०) :-

औरंगाबाद :-

जहानाबाद :- नवीन कुमार रौशन 9934039939

अरवल :- संतोष कुमार मिश्रा 9934248543

नालन्दा :-

:-

नवादा :- अमित कुमार 9162664468

:-

मुंगेर :-

लखीसराय :-

शेखपुरा :-

बेगूसराय :-

:-

खगड़िया :-

समस्तीपुर :-

जमुई :- अजय कुमार 09430030594

वैशाली :-

:-

छपरा :-

सिवान :-

:-

गोपालगंज :-

:-

मुजफ्फरपुर :-

:-

सीतामढ़ी :-

शिवहर :-

बेतिया :- रवि रंजन मिश्रा 9801447649

बगहा :-

मोतिहारी :- संजीव रंजन तिवारी 9430915909

दरभंगा :-

:-

मधुबनी :-

:- प्रशांत कुमार गुप्ता 6299028442

सहरसा :-

मधेपुरा :-

सुपौल :-

किशनगंज :-

:-

अररिया :- अब्दुल कय्यूम 9934276870

पूर्णिया :-

कटिहार :-

भागलपुर, :-

(ग्रा०):- रवि पाण्डेय 7033040570

नवगछिया :-

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर,
नई दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 7903856569, 6203723995

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या.- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☞ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☞ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ **सभी पद अवैतनिक हैं।**

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- State Bank of India
IFSC Code :- SBIN0003564
PAN No. :- AAJFK0065A

प्रधान संपादक

.....

.....

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

.....

झारखण्ड सहायक संपादक

अभिजीत दीप 7004274675, 9430192929
ब्रजेश मिश्र 7654122344, 7979769647
अनंत मोहन यादव 9546624444, 7909076894

उप संपादक

अजय कुमार 6203723995, 8409103023

.....

संयुक्त संपादक

.....

विशेष प्रतिनिधि

भारती मिश्रा 8210023343, 8863893672

.....

.....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची :- अभिषेक मिश्र 7903856569
:- ओम प्रकाश 9708005900
साहेबगंज :-
खूँटी :-
जमशेदपुर :- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता 9304824724
हजारीबाग :-
जामताड़ा :-
दुमका :-
देवघर :-
धनबाद :-
बोकारो :-
रामगढ़ :-
चाईबासा :-
कोडरमा :-
गिरीडीह :-
चतरा :- धीरज कुमार 9939149331
लातेहार :-
गोड्डा :-
गुमला :-
पलामू :-
गढ़वा :-
पाकुड़ :-
सरायकेला :-
सिमडेगा :-
लोहरदगा :-

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी

'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

व्यवसायी

पटना, बिहार

7360955555

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सूमन सौरभ	9471492480, 7004952447
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417
रजनीश कांत झा	9430962922, 7488204140

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670

झारखंड राज्य प्रमंडल ब्यूरो		
राँची	गुड्डी साव	6299470142
हजारीबाग		
पलामू		
दुमका		
चाइईबासा		

कभी लालू के थे दुलारे, कम उम्र में ही बना दिये गये थे मंत्री! वक्त बदली, पारी बदली; मोदी के हुए दिवाने। पिता शकुनी के मोदी विरोधी होने के बावजूद कमल खिलाने को हुए आतुर तो कभी नीतीश से खीज खाये सिर पर बांध ली थी पगड़ी। वक्त बदला, सत्ता आयी और मिला इतना सम्मान। देखते रह गये पुराने भाजपायी, सम्राट ने संभाल ली बिहार की कमान। जी हाँ! भाजपा ने पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाया और दाव खेला सम्राट चौधरी पर। शाह-मोदी के दुलारे सम्राट पर जिम्मा मिशन 2029 और 2030 का। क्या भरोसे पर उतर पायेंगे सम्राट? यह सच है कि बिहार की राजनीति, जाति पर ही आधारित है और ऐसे में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना इस बात का प्रमाण है कि इनकी जाति का बिहार में स्थान दूसरे नंबर पर है। बीते चुनावों पर नजर दौड़ायें तो देखेंगे कि कुशवाहा वोटरों का झुकाव भाजपा के प्रति बढ़ा है और चूकि सम्राट चौधरी उन नेताओं में शुमार रखने वाले शकुनी चौधरी के बेटे हैं जिनका प्रभाव अपनी जाति पर हमेशा से रहा है। राज्यसभा जाने की स्वयं इच्छा की बात कहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की कुर्सी 20 वर्षों बाद आखिर खाली कर दी या करवाई गयी, मंथन जारी है! उन्होंने राज्यसभा सदस्य का शपथ भी ले लिया किन्तु सभी के जेहन में यह सवाल है कि सुशासन बाबू से कुर्सी कुमार की उपाधि पा चुके नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी के लिए पाला बदलते देखा गया है पर, ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उस बिहार की कमान सहयोगी भाजपा को दे दी, जिसे 20 वर्षों में विकास को गति दी और जंगलराज का खात्मा किया। ये अलग बात है कि सम्राट कैबिनेट में नीतीश के दो चहेते चेहरे विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव उपमुख्यमंत्री पद पर जेडीयू से बने हो। सीएम सस्पेंस के बीच आनन-फानन में बेटे निशांत को जेडीयू की सदस्यता दिलायी गयी। माना जाने लगा कि सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम तो निशांत जरूर बनेंगे। किन्तु निशांत का मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री ना बनना निशांत के निजी फैसले हो सकते है या यूं कहे कि नीतीश कुमार के राजनीति का हिस्सा। बेदाग छवि के साथ 20 वर्षों से अधिक समय तक सीएम रहने के बावजूद नीतीश कुमार खुद पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगने दिया और अब जब समय आया तब भी इससे बच निकले। हालांकि कल तक जो सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार पर हमला करते आये वह सरकार में डिप्टी सीएम बनकर नीतीश कुमार के काफी नजदीक हो गए और चहेते भी, तभी तो विधायक दल के नेता चुने जाने पर नीतीश ने हांथ पकड़कर सभी से सम्राट के लिए तालियां तक बजवा दी। बहरहाल, भाजपा भीतरखाने में सम्राट के सीएम बनने से खुशी कम, गम ज्यादा है। मीडिया द्वारा भाजपा के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कई भाजपाइयों ने उन्हें भाजपा का नहीं, एनडीए का सीएम होने का बयान तक दे डाला। ऐसा हो भी क्यों ना, जब वर्षों खून-पसीने की मेहनत से बिहार में भाजपा को अस्तित्व में लाने का काम जो पुराने भाजपायियों ने किया, उसे उनका इनाम इस अंदाज में मिलेगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। सूत्रों की माने तो ये पूरी पटकथा आज नहीं लिखी गई, ये वर्षों पुरानी है और ये पटकथा भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने लिखी थी, जिसके मुख्य किरदार में सम्राट चौधरी फिट बैठ गये। दिवंगत सुशील मोदी, जिन्होंने सम्राट चौधरी को भाजपा में लाया, उन्हे बिहार से बाहर कर दिल्ली (राज्यसभा) भेज दिया गया था और आज नीतीश कुमार दिल्ली (राज्यसभा) के हो गये। विरोध सिर्फ भाजपा में ही नहीं बल्कि जेडीयू में भी बना हुआ है। जेडीयू को कुर्मी जाति की पार्टी कही जाती है किन्तु मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पदों पर एक भी कुर्मी जाति का नहीं, तो मान लिया जाये कि भविष्य की सत्ता में जेडीयू नहीं होगी! नीतीश ने बिहार छोड़ दिया और निशांत अभी राजनीति में बच्चे हैं, जिनका अनुभव वो लेना शुरू किया है। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के लगभग साढ़े बीस वर्षों के शासन को देखा है और अब सम्राट युग के उदय के ये साढ़े चार वर्ष देखेगी। फिलहाल मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट काम पर लग गये हैं और अधिकारियों के साथ बैठके जारी है। सीएम कुर्सी की अदला-बदली पर प्रस्तुत है, संयुक्त संपादक **अमित कुमार** की समीक्षात्मक रिपोर्ट :-

बिहार के लिए 15 अप्रैल 2026 का दिन ऐतिहासिक रहा। बिहार में अब से 'सम्राट' युग की शुरुआत हो चुकी है, और नीतीश युग का अंत। यह पहला मौका है जब बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बना है। सम्राट चौधरी अब बिहार की नई सरकार का नेतृत्व करेंगे और वो होंगे बिहार के मुख्मयंत्री। सम्राट चौधरी को पटना स्थित लोकभवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। सम्राट चौधरी के अलावा जेडीयू के विजय चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लोकभवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने विजय चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव को भी उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के नेता जेपी नड्डा, भीखूभाई दलसानिया और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार भी मौजूद थे। लोजपा (रामविलास) पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान भी इस शपथ समारोह के गवाह बने। साथ ही इस शपथ समारोह में सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी और उनके घर के कुछ अन्य सदस्य भी मौजदू थे। नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले सम्राट चौधरी पटना के राजवंशी नगर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर भी गए थे। हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद सम्राट चौधरी सीधे लोकभवन पहुंचे। यहां मौजूद नेताओं का सम्राट चौधरी ने अभिवादन किया और फिर राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले सम्राट चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पूर्व भाई सम्राट चौधरी जी से मुलाकात कर उन्हें एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बिहार विकास, सुशासन और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। बिहार के सियासत में सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने लोकभवन में भाजपा नेता सम्राट चौधरी को 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। इसके बाद बिहार सरकार में मंत्री के पद पर कार्य कर रहे एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी जदयू के वरिष्ठ नेता बिजेंद्र यादव और विजय चौधरी को राज्यपाल ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। बता दें कि जदयू कोटे से बिहार के दो डिप्टी सीएम रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही राज्य में सम्राट सरकार का दौर शुरू हो गया। बिहार के इतिहास में पहली बार जदयू कोटे से दो उपमुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ओबीसी समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी कुशवाहा यानी कोइरी समाज से ताल्लुक रखते हैं। अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए का दामन छोड़ा था, तब बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया था। उस वक्त सम्राट चौधरी ने भी नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने तक सिर पर मुरेठा (पगड़ी) बांधे रखने का संकल्प लिया था। सम्राट चौधरी दो बार परबत्ता से विधायक रहे, दो बार विधान परिषद के सदस्य रहे, कई विधायकी और प्रशासनिक क्षेत्र में काम का अनुभव और दो बार के डिप्टी सीएम पर रहे। 2024 में डिप्टी सीएम के साथ-साथ वित्त मंत्री बनाए गए। पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 89 सीटें जीतीं और एक बार

बिहार के 24वें मुख्यमंत्री का शपथ लेते सम्राट चौधरी

शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नेतागण

विजय कुमार चौधरी

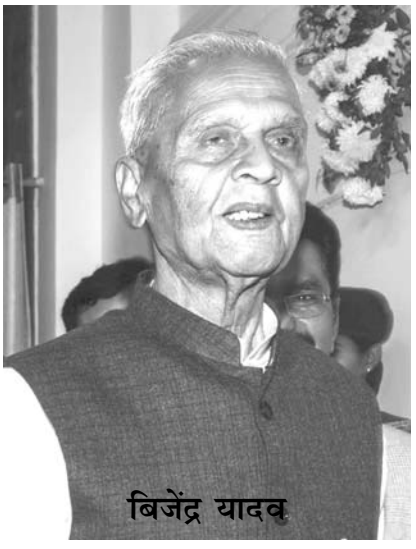

बिजेंद्र यादव

नीतीश कुमार

फिर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थीं। इसके बाद से ही राज्य में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरो पर थी। बहरहाल नीतीश की राज्यसभा सांसद के रूप में केंद्र की राजनीति में एंट्री ने सम्राट के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया।

गौरतलब है कि डिप्टी सीएम बनाये जाने के बाद विजय चौधरी ने कहा कि हमलोगों ने नीतीश कुमार के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है। भविष्य में भी नीतीश कुमार की कार्यशैली पर भी हमलोग काम करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाने की बात कही है। इसलिए कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम बिजेंद्र यादव के साथ मिलकर बेहतर काम करेंगे। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मैं नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यह जिम्मेदारी मिलना उनका मुझ पर विश्वास का परिणाम है। बिहार की नई सरकार नीतीश कुमार जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर काम करेगी। उनका काम करने का तरीका अद्भुत था और हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। नए मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हम नीतीश कुमार जी द्वारा शुरू की गई योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। डिप्टी सीएम बनने के बाद विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जनता दल (यूनाइटेड) नेता विजय कुमार चौधरी ने बिहार के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर कहा, " मैंने जो आज शपथ ली है, इसके लिए मैं नीतीश कुमार के प्रति आभार प्रकट करता हूं। ये उन्हीं के विश्वास का नतीजा है कि मुझे ये जिम्मेदारी मिली है... जो उनके (नीतीश कुमार) रास्ते हैं, उनकी नीतियां हैं, उनके तरीके हैं, उनके कार्यक्रम है, उनके तरीके हैं, उनकी कार्यशैली है उसी पर चलने का काम हम करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि अब तक नीतीश कुमार का जो मॉडल था उसमें भाजपा भी थी। अभी तुलना वाली कोई बात नहीं है। बिहार के मॉडल में नीतीश कुमार भी हैं, भाजपा भी है और अन्य तीन दल भी हैं... नीतीश कुमार कोई दूसरा नहीं हो सकता। नीतीश कुमार की जो सोच है, उनके काम करने का तरीका अद्भुत है। हमने उनके साथ बहुत कुछ सीखा है और उसी आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। यही बात हमारे नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कही है कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए जो रास्ता, जो नीतियां व कार्यक्रम बनाए हैं, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे इसलिए न कहीं कोई कंफ्यूजन है और न समझदारी का अभाव है। ज्ञात हो कि बिहार की सियासत में जब भी धैर्य, सौम्यता और सधे हुए राजनीतिक अनुभव की बात होती है, तो एक नाम सबसे ऊपर आता है-विजय कुमार चौधरी। समस्तीपुर की धरती से आने वाले विजय चौधरी आज उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर अपने राजनीतिक जीवन के एक नए और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले 21 वर्षों से जदयू में नीतीश कुमार के छाया बनकर रहने वाले विजय चौधरी ने अपनी काबिलियत के दम पर बैंक की नौकरी से लेकर डिप्टी सीएम तक का सफर तय किया है। राजनीति में आने से पहले विजय चौधरी एक मेधावी छात्र थे और उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बतौर पीओ दो साल तक नौकरी भी की। लेकिन 1982 में पिता के आकस्मिक निधन ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने बैंक की सुरक्षित नौकरी छोड़ी और पिता की विरासत संभालने के लिए चुनावी मैदान में उतर गए। 1982 के उपचुनाव में दलसिंहसराय से जीतकर उन्होंने अपनी पहली राजनीतिक पारी की शुरुआत की। विजय चौधरी ने अपना राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू किया और 1985 व 1990 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के करीबियों में गिने जाने वाले चौधरी विधानसभा में कांग्रेस के उपसचेतक भी रहे। हालांकि, 1995 और 2000 के चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 2005 में उन्होंने जदयू का दामन थामा और नीतीश कुमार के साथ हो गए। तब से पिछले 21 सालों में उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और नीतीश कुमार ने भी हमेशा विजय चौधरी के शांत स्वभाव और प्रशासनिक पकड़ पर भरोसा किया है। वही वरिष्ठ नेता बिजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल के रहने वाले हैं। कोसी क्षेत्र को जदयू के गढ़ के रूप में स्थापित करने में बिजेंद्र यादव का बड़ा योगदान है। वह सुपौल सदर विधानसभा से लगातार 9 बार के विधायक हैं। दरअसल, कोसी इलाके में बिजेंद्र प्रसाद यादव राजनीति की धुरी माने जाते हैं। साल 1990 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की, तब से लेकर आज तक लगातार सुपौल सदर सीट को इन्होंने जदयू का सीट बना दिया। बिजेंद्र यादव जदयू के अंदर बन रही किसी भी रणनीति में बड़ा दखल रखते हैं। पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार के ये करीबी हैं। इसी का नतीजा रहा कि इन्हें उपमुख्यमंत्री की कुर्सी से नवाजा गया। करीब-करीब बिहार सरकार के सभी मंत्रालयों को बिजेंद्र प्रसाद यादव लीड कर चुके हैं।

विदित हो कि, सीएम सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि आज बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर सम्राट चौधरी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। वही प्रधानमंत्री ने सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

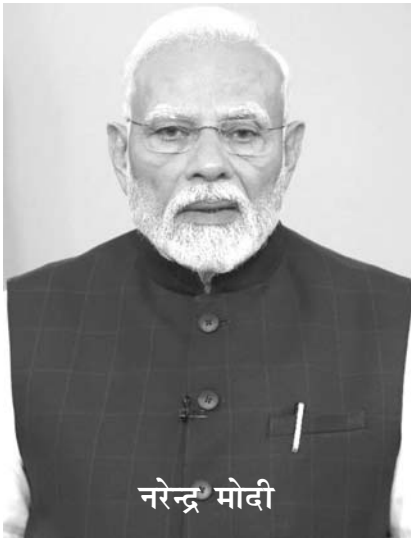
नरेन्द्र मोदी

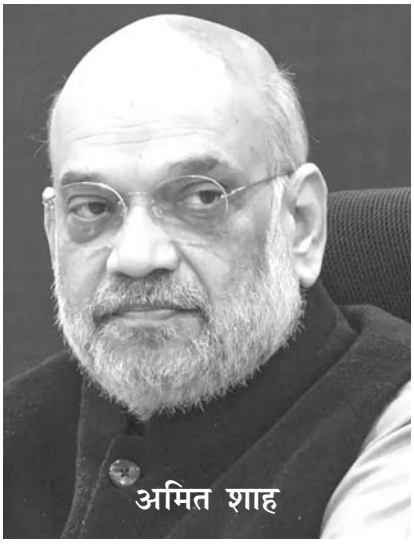
अमित शाह

नीतिन नवीन

ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा; "बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर सम्राट चौधरी जी को बहुत-बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं! उनकी ऊर्जा, जनसेवा के प्रति समर्पण और जमीनी अनुभव राज्य के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके कुशल नेतृत्व में जनता-जनार्दन की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए बिहार चौतरफा विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। "बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले विजय कुमार चौधरी जी और बिजेंद्र प्रसाद यादव जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं! मुझे पूरा भरोसा है कि इनका जमीनी अनुभव और जनहित को लेकर प्रतिबद्धता बिहार के विकास को नई दिशा और गति देगी। इसके साथ ही राज्य सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण के नित-नए मानक स्थापित करेगा। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आपके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए जिस संकल्प भावना के साथ बिहार की जनता की दिन-रात सेवा कर रहा था, मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में उसे और भी गति मिलेगी। साथ ही, एक सुरक्षित एवं विकसित बिहार के निर्माण की दिशा में एनडीए की डबल इंजन सरकार और अधिक ऊर्जा के साथ कार्य करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सम्राट चौधरी जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित भारत-विकसित बिहार' के संकल्प को सिद्ध करने हेतु आप पूर्णत: समर्पित भाव से कार्य करेंगे, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है।

बहरहाल, बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हो गई है। नई सरकार के गठन के साथ ही बिहार में बुलडोजर एक्शन पर चर्चा होने लगी है। सम्राट के शपथ लेते ही समर्थक उन्हें 'बुलडोजर बाबा' कहने लग गए हैं। पटना स्थित लोकभवन के बाहर सम्राट क

सामने बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे भी लगे। सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि क्या नए सीएम सम्राट बिहार में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 'योगी मॉडल' लागू करेंगे? पूर्ववर्ती नीतीश सरकार में गृह विभाग संभालने वाले सम्राट चौधरी अपराधियों को चुनौती देते हुए उनका गयाजी में पिंडदान करने, उन्हें नेपाल और पाताल भेजने जैसी चेतावनियां देते रहे हैं। अब राज्य में एनडीए की पूरी सरकार की कमान उनके हाथ में आ गई है, तो कानून व्यवस्था पर बड़ा ऐक्शन होने की संभावना जताई जा रही है। लगभग दो दशक से बिहार की सत्ता में शामिल भाजपा ने पहली बार राज्य में अपना सीएम बनाया है। अब तक एनडीए सरकार का नेतृत्व जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ही करते रहे हैं। नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद अब भाजपा को सरकार का नेतृत्व करने का मौका मिला है। नीतीश सरकार में नंबर दो की पॉजिशन में रहे सम्राट चौधरी पर ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताया और उन्हें राज्य की कमान सौंपी। सम्राट, पूर्व सीएम नीतीश कुमार के भी पसंदीदा रहे हैं। अब जब बिहार में भाजपा का सीएम बन गया है, तो राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले अपराधियों के खिलाफ ऐक्शन तेज होने की चर्चा जोरों पर है। नवंबर 2025 में जब सम्राट गृह मंत्री बने थे, उसके बाद से बिहार पुलिस और जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही हैं। कुख्यात अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। आए दिन पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं। हालांकि, फिर भी लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे अपराध सरकार के लिए चुनौती बने हुए हैं। बीते 4 महीने में राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार ने सख्ती दिखाई है। राजधानी पटना से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक में अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ शहर-शहर बुलडोजर चल रहे हैं। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद इस ऐक्शन में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नेपाल और बंगाल की सीमा से सटे बिहार के जिलों में अवैध कब्जा हटाने के लिए ऐक्शन प्लान बना चुके हैं। दिगर बात है कि भाजपा नेता सम्राट

कुणाल

रोहिणी आचार्या

तेजस्वी यादव

चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर विपक्ष भी बुलडोजर वाली बात करने लगा है। वाम दल सीपीआई माले ने आरोप लगाया कि भाजपा बिहार को बुलडोजर राज की प्रयोगशाला बनाना चाहती है। माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि भाजपा को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि बिहार उसकी इस तानाशाही परियोजना को स्वीकार कर लेगा। यह वही धरती है, जिसने सत्ता के अहंकार को बार-बार चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर पूरी ताकत से भाजपा की तानाशाही नीतियों का मुकाबला करने का आह्वान भी किया। सनद् रहे कि बिहार की सत्ता बदलते ही बयानों के तीर चलने शुरू हो गए हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर जोरदार तंज कसा है। रोहिणी ने एक सरकारी विज्ञापन का पोस्टर साझा करते हुए इसे 'घोर बेइज्जती' करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि नई व्यवस्था में नीतीश कुमार को हाशिए पर धकेलने की शुरुआत हो चुकी है। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में लिखा कि अभी इस्तीफा दिए 24 घंटे भी नहीं हुए और नीतीश कुमार को पोस्टर और विज्ञापनों से गायब कर दिया गया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस्तीफे से पहले तक नीतीश कुमार के 'बिदकने' का डर था, इसलिए उन्हें यह कहकर ताड़ पर चढ़ाया जा रहा था कि बिहार उनकी ही छत्रछाया में चलेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली जमात को अब उनकी तस्वीर से भी परहेज होने लगा है। रोहिणी ने नीतीश कुमार की वर्तमान स्थिति की तुलना 'कैच-22' सिचुएशन से की, जिसका अर्थ है एक ऐसी कठिन परिस्थिति जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो। उन्होंने एक पुरानी कहावत का जिक्र करते हुए लिखा, 'दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम'। रोहिणी का तंज साफ था कि नीतीश कुमार ने भरोसे के साथ सत्ता सौंप दी है लेकिन अब उन्हें न तो वह पुराना सम्मान मिलेगा और न ही सत्ता में वैसी पकड़, जैसी पहले हुआ करती थी। इससे पहले भी रोहिणी आचार्या ने नई सरकार के गठन होने पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने अपने पिछले ट्वीट में भाजपा पर तंज कसते हुए कहा था कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक 'घुमंतू' ही मिला है। उनके इस बयान

का सीधा इशारा सम्राट चौधरी की ओर था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि "अपनी स्थापना के 46 साल बाद भी बिहार में बीजेपी नेतृत्व की इतनी गंभीर कमी और सूखे से जूझ रही है कि न तो वह अपने दम पर सरकार बना पाई है, न ही किसी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे की घोषणा कर पाई है और न ही व्यापक जनमानस और मान्यता प्राप्त नेता को तैयार कर पाई।" उनके इस ट्वीट के बाद सियासत का बाजार गर्म है।

गौरतलब है कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक औपचारिक बयान जारी कर नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई दी, लेकिन इस बधाई संदेश में तंज और तीखे सवालों की भरमार रही। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को उनके द्वारा ली गई उस पुरानी प्रतिज्ञा की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने की बात कही थी। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कटाक्ष करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी जी को अंततः नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने पर बहुत-बहुत बधाई। उन्होंने सम्राट चौधरी को जनता द्वारा नहीं, बल्कि परिस्थितियों द्वारा 'चयनित' मुख्यमंत्री बताते हुए उनके नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। तेजस्वी का यह बयान उस समय आया है जब बिहार में भाजपा पहली बार अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने में सफल रही है। बधाई देने के साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार की जमीनी हकीकत का हवाला देते हुए नई सरकार को आइना दिखाया। उन्होंने कहा, आशा है कि नए माननीय मुख्यमंत्री जी इस कड़वे, अप्रिय एवं कठोर तथ्य से पूर्ण रूप से अवगत होंगे कि 21 वर्षों के एनडीए शासन के बावजूद बिहार विकास के लगभग सभी मानकों पर देश के अन्य राज्यों से काफी पीछे है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीति आयोग के मानकों और सतत विकास के सूचकांकों में बिहार आज भी राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। तेजस्वी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था और ध्वस्त हो चुकी विधि -व्यवस्था आज बिहार की पहचान बन गई है। उन्होंने नए मुख्यमंत्री से सवाल किया कि आखिर कब बिहार में आय और निवेश के नए रास्ते

राज्यसभा का शपथ ग्रहण करते नीतीश कुमार

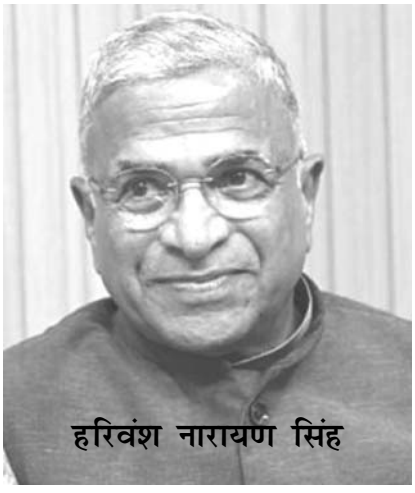
हरिवंश नारायण सिंह

खुलेंगे? नौकरी और रोजगार के लिए युवाओं का पलायन कब रुकेगा? और गरीबी और पलायन जैसे अभिशाप से राज्य को कब मुक्ति मिलेगी? उन्होंने उम्मीद जताई कि नए मुख्यमंत्री केवल उत्सव मनाने के बजाय इन गंभीर समस्याओं के समाधान पर ध्यान देंगे।

विदित हो कि बिहार के तत्कालिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को पहली बार राज्यसभा सांसद बन गए। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ दिलाई। बता दें कि नीतीश कुमार 16 मार्च को बिहार से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। 30 मार्च को उन्होंने बिहार विधान परिषद के एमएलसी के पद से इस्तीफा दे दिया था। वही बता दें कि नीतीश कुमार के साथ ही राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह एक बार फिर राज्यसभा सांसद बन गए हैं। इस बार जब उन्हें जदयू ने उच्च सदन नहीं भेजा तो राष्ट्रपति द्रौपद मुर्मू ने मनोनित कर दिया। गृह मंत्रालय की ओर से प्रकाशित गजट के अनुसार, एक सांसद का कार्यकाल खत्म होने से खाली हुई सीट पर राष्ट्रपति ने उन्हें मनोनीत किया है। उनका यह कार्यकाल 2032 तक चलेगा। राज्यसभा सांसद के रूप में हरिवंश का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो गया था। जदयू ने अप्रैल 2014 में पहली बार उन्हें बिहार से राज्यसभा में भेजा था। वे 9 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उप सभापति पद के लिए पहली बार निर्वाचित हुए थे। इससे बाद वे 14 सितंबर 2020 को दूसरी बार राज्यसभा के उप सभापति निर्वाचित हुए।

खैर, बात नीतीश कुमार की

कि जाये तो वह केंद्रीय राजनीति से जुड़ाव बहुत पुराना है। 1989 में पहली बार सांसद बनने से लेकर 2004 तक उन्होंने दिल्ली के सत्ता के गलियारों में कई महत्वपूर्ण पदों को संभाला। केंद्रीय राजनीति में नीतीश कुमार की यात्रा दिसंबर 1989 में शुरू हुई। बाढ़ संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद वे पहली बार लोकसभा में पहुंचे। उनकी क्षमताओं को पहचानते हुए, तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उन्हें कृषि और सहकारिता राज्य मंत्री नियुक्त किया। हालांकि, यह कार्यकाल छोटा रहा और नवंबर 1990 में सरकार गिरने के साथ ही समाप्त हो गया। नीतीश कुमार का कद सही मायने में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौरान बढ़ा। 1998 में उन्हें रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी दौरान 1999 में पश्चिम बंगाल के गैसल में एक भयानक रेल दुर्घटना हुई। इस त्रासदी की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राजनीति में नैतिकता का यह उदाहरण आज भी मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान नीतीश कुमार ने अलग-अलग समय पर कई अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों की कमान भी संभाली। 1998 और 1999 के बीच उन्होंने भूतल परिवहन मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाला। इसके बाद नवंबर 1999 से मार्च 2000 तक और फिर मई 2000 से

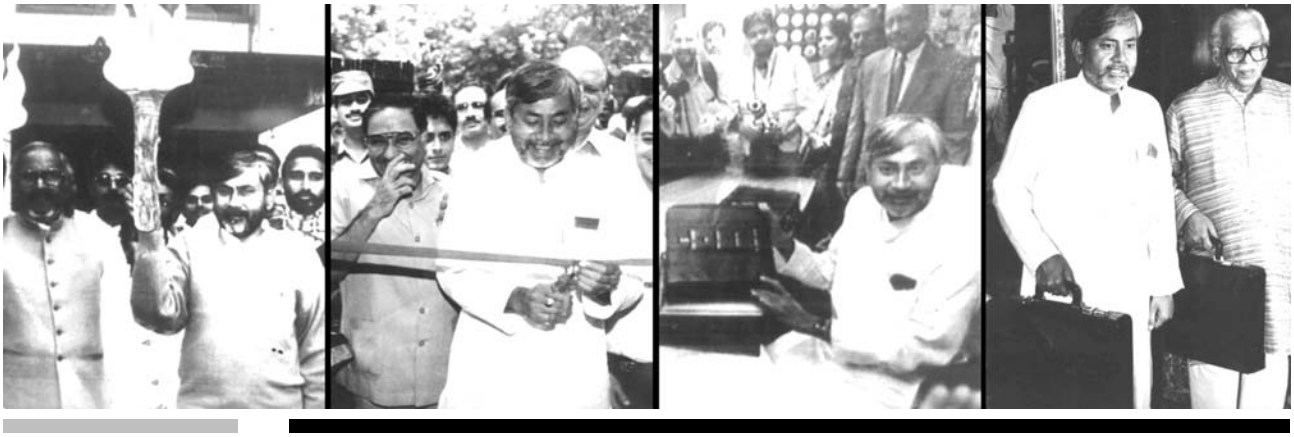

जुलाई 2001 तक उन्होंने देश के कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। इस भूमिका में उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई दूरगामी नीतिगत निर्णय लिए। साल 2001 में नीतीश कुमार एक बार फिर रेल मंत्री बने और मई 2004 तक इस पद पर बने रहे। रेल मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को भारतीय रेलवे के लिए स्वर्ण युग से कम नहीं माना जाता है। नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने आईआरसीटीसी की शुरुआत की और इस तरह उस ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली की नींव रखी, जिसका उपयोग हम आज करते हैं। इसके अलावा, रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उन्होंने 17,000 करोड़ रुपये का एक विशेष सुरक्षा कोष स्थापित किया। इतना ही नहीं टिकट बुकिंग में तत्काल कोटा और कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली को उन्होंने ही मजबूती दी और अब राज्य सभा में शपथ लेकर नीतीश कुमार अपने नाम एक दुर्लभ रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया। नीतीश कुमार उन नेताओं में शामिल हो गये, जिन्होंने भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर चारों विधायी सदनों लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने का गौरव हासिल कर लिया है।

हालांकि, नीतीश कुमार ने राज्य सभा सदस्य के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ले ली, लेकिन पटना में जेडीयू मुख्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर ने पूरे राज्य का सियासी पारा बढ़ा दिया था। इस पोस्टर में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को न केवल नीतीश के सपनों का उत्तराधिकारी, बल्कि फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार बताया गया है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने पर छात्र जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण पटेल द्वारा जेडीयू कार्यालय के बाहर यह पोस्टर लगाया गया था। पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा था, 'नीतीश सेवक, मांगे निशांत। हे जनेश्वर बिहार छोड़कर हम बिहारवासियों को मत कीजिए अनाथ। पूछता है आज पूरा बिहार, आप जैसा कौन देगा सुरक्षा गारंटी और पूरा साथ।' पोस्टर के निचले हिस्से में नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करते हुए लिखा गया था, 'निशांत निश्चय, नीतीश जी का मिशन अधूरा, निशांत कुमार ही करेंगे पूरा, मिशन विकसित बिहार 2040।' पोस्टर में ऊपर नीतीश कुमार की फोटो लगा था और नीचे निशांत कुमार की तस्वीर थी। निशांत की तस्वीर के साथ लिखा था 'फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार।' बता दें कि नीतीश कुमार ने हमेशा से बिहार के लिए लॉन्ग-टर्म विजन रखा है, चाहे वह 'सात निश्चय' हो या 'जल-जीवन-हरियाली।' अब इन पोस्टरों के जरिए 'मिशन विकसित बिहार 2040' का नारा बुलंद किया गया। इसके साथ ही जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का एक पोस्टर चर्चा में आ गया, जिसे उन्होंने अपने सरकारी आवास के बाहर लगाया था। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके बेटे निशांत कुमार की तस्वीर लगाई गई थी। इसमें लिखा था-'मजबूत विरासत, भविष्य दमदार, निशांत कुमार हैं तैयार'। पोस्टर को लेकर सवाल पूछे जाने पर नीरज कुमार ने कहा कि दोनों के नाम में 'एनआई' समान है और यह विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में निशांत कुमार को लेकर सकारात्मक माहौल है और 'जय निशांत, तय निशांत' जैसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 'तीर' (जदयू का चुनाव चिह्न) बिहार की तकदीर बदल चुका है और अब इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नई पीढ़ी को मिल रही है।

बहरहाल, जिस राज्य में बिना विधायक बने पिता ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया। जहां विरासत को संभालने के नाम पर एक भाई उप मुख्यमंत्री तो दूसरा भाई स्वास्थ्य मंत्री बन गया। जहां एक ही परिवार में बहू विधायक, बेटा विधायक, समधन विधायक बनी। जिस राज्य में चाचा सांसद, भतीजा सांसद, बेटा भी सांसद बना। उसी राज्य में जाते-जाते भी नीतीश कुमार ने राजनीति में नई इबादत लिख डाली। याद कीजिए जब यह तय हुआ कि अब नीतीश कुमार पटना छोड़कर दिल्ली जाएंगे। सबसे ज्यादा चर्चा किस नाम को लेकर हुआ था? वह नाम था नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का। निशांत को आनन-फानन में पार्टी की

बेटे निशांत के साथ नीतीश कुमार

जदयू की सदस्यता लेते निशांत कुमार

सदस्यता दिलाई गई। बिहार से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा जोरों पर थी कि अब निशांत ही नीतीश के आधिकारिक तौर पर उत्तराधिकारी बनने जा रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि निशांत कुमार बिहार के राजनीतिक सीन से बिल्कुल गायब हो गए। पहले सरकार से, फिर शपथ ग्रहण समारोह से निशांत कुमार दूर हुए तो सबके जहन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर निशांत कुमार ने अचानक से दूरी क्यों बनाई। सरकार के गठन से पहले चर्चा थी कि वह डिप्टी सीएम बनेंगे। अंत तक उनको मनाने की कोशिश हुई, लेकिन वे सरकार से दूर ही रहे। इतना ही नहीं 15 अप्रैल 2026 को शपथ ग्रहण समारोह में भी वह नहीं पहुंचे। अब बिहार में नई सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू के दो डिप्टी सीएम भी शपथ ले चुके हैं। लेकिन निशांत कुमार सरकार में शामिल नहीं हुए हैं। क्या निशांत कुमार का यह निजी फैसला है या फिर नीतीश कुमार के राजनीति का कोई हिस्सा? सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार भी नहीं चाहते थे कि निशांत तुरंत सरकार में शामिल हों। सूत्रों ने यह भी बताया कि नीतीश अपने पुत्र निशांत को पहले पार्टी में पैठ बनाने के पक्ष में थे। निशांत ने पार्टी में शामिल होकर कार्यकर्ताओं से मिलना-जुलना भी शुरू कर दिया। सूत्रों ने बताया कि जल्द ही निशांत अब बिहार के दौरे पर निकल सकते हैं। राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक शिष्य रहे नीतीश कुमार खुद पर परिवारवाद के आरोप से भी बचना चाह रहे थे। ऐसे में पार्टी में पुत्र निशांत के शामिल होने के वक्त भी वो जेडीयू दफ्तर में नहीं थे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत को पार्टी में शामिल कराया था। नीतीश ने राज्य में इक्कीस साल बेदाग राजनीति की है। ऐसे में वो नहीं चाहते हैं कि उन पर परिवारवाद का ठप्पा लगे। इसलिए माना जा रहा है कि निशांत भी किसी जल्दबाजी के पक्ष में नहीं हैं।

लब्बोलुआब है कि बिहार में सम्राट युग के उदय से पहले सीएम कौन का मंथन बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ था और इससे भी ज्यादा सस्पेंस नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे को लेकर बना हुआ था किन्तु राज्यसभा सदस्य के शपथ के बाद दिल्ली से पटना पहुंचकर बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार हाल ही में निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए हैं और शपथ भी ले चुके हैं। इस्तीफे के बाद किए गए एक ट्वीट में नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली जैसे क्षेत्रों में समाज के हर वर्ग के लिए काम किया, खासकर महिलाओं और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि नई सरकार इन जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाएगी और उसे उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। 75 वर्षीय जेडीयू प्रमुख, जो अक्सर राजनीतिक पाला बदलने के लिए भी जाने जाते हैं, ने अपना इस्तीफा राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैय्यद अता हुसैन को लोक भवन में सौंपा। इससे उनके 20 साल से अधिक के लंबे कार्यकाल का अंत हो गया। उनके नेतृत्व में बिहार देश के तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल हुआ। उनकी पार्टी जेडीयू फिलहाल भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। यह इस्तीफा बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के

सम्राट चौधरी

पांच महीने बाद आया है। इसमें जेडीयू का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा था। वही नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बैठक आहुत की गई थी और विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया। भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम की घोषणा की। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि ये मेरे लिए जीवन में भाजपा ने मुझे जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूं एक राजनीतिक तौर से मैं करीब 30 साल से काम कर रहा हूं लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं था मैं इस पार्टी में जब पीएम मोदी के विचारों से इस पार्टी के साथ जुड़ा, 2015 के चुनाव से लगातार मैं भाजपा के लिए काम करता रहा हूं और जिस तरह से कभी पार्टी के प्रदेश में पदाधिकारी के तौर पर विधानमंडल दल में, विधानपरिषद के नेता के तौर पर और संगठन में काम करने का जो सर्वोच्च पद है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि आज मैं पीएम मोदी, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, शिवराज सिंह चौहान जी के जो विचारधारा है, भाजपा की जो विचारधारा है भारत को सबसे पहले, सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का उस काम को हम लगातार करते रहेंगे, इतना जरूर विश्वास दिलाते हैं। नीतीश कुमार ने बहुत कुछ सिखाया है...नीतीश कुमार ने जिस तरह से समृद्ध बिहार का सपना देखा है हम सब मिलकर बिहार और देश को समृद्ध बनाने का काम करेंगे।

बहरहाल, नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार की हर वह जनता जो बिहार के विकास के लिए संकल्पित नीतीश कुमार के 20 वर्षों से अधिक के कार्यवधि को देखा, वह नेता नहीं मानो एक परिवार का सदस्य बन चुका था। जेडीयू कार्यकर्ता के साथ ही उनके वरिष्ठ नेताओं के आंखों में नीतीश कुमार के विदाई को लेकर आंसु झलकते देखे गये। भावविहोर वो चेहरे बयां करते हैं, वो नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने ने 2005 से पहले की बिगड़ी कानून व्यवस्था, जर्जर सड़क, ध्वस्त बिजली-पानी, जर्जर स्वास्थ्य एवं शिक्षा को बदलकर प्रदेश में सुशासन और विकास दिया, वह आज बिहार छोड़कर जा रहे हैं किन्तु नीतीश कुमार ने उन्हें आश्वस्त किया है की, मेरा ज्यादा समय बिहार में बीतेगा। बावजूद नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद उनके बेटे निशांत कुमार के पटना के वीरचंद पटेल स्थित जेडीयू कार्यालय आने पर हलचल होती है। ऐसा लगता है कि बढ़ रही गर्मी के बीच जेडीयू कार्यकर्ताओं को निशांत कुमार एक राहत की तरह दिखते हैं, लेकिन फिर भी वो उनमें दूसरा नीतीश नहीं देख पाते। गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने सत्ता संभालने के बाद राज्य की स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया था। इस श्वेत पत्र में राज्य की स्थिति के बारे में लिखा था, विकास के सभी सूचकांकों में बिहार की स्थिति सभी बड़े राज्यों में सबसे खराब है। सत्ता संभालने के बाद नीतीश सरकार के सामने कानून-व्यवस्था के साथ ही सड़क-बिजली जैसे बुनियादी ढ़ांचे पर काम करने की चुनौतियां थीं। कुर्मी जाति से आने वाले नीतीश कुमार को अगर बिहार में लंबे समय तक सत्ता में टिके रहना था तो उन्हें बिहार की जातीय राजनीति में अपने लिए 'वोट इंजीनियरिंग' भी करनी थी। नीतीश ने इसके लिए महिलाओं और अति पिछड़ों को चुना। नीतीश कुमार ने महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण और दूसरी तरफ पंचायत और स्थानीय निकाय में ईबीसी हिंदू और मुसलमानों को 20 फीसदी आरक्षण दिया। ऐसा करते ही उन्हें अपनी ही जाति के लोगों से आलोचना का सामना करना पड़ा, जिनके मुताबिक ईबीसी और अन्य वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी बलि दी गई। लेकिन नीतीश तो लोहिया के उन शब्दों को गांठ बांध चुके थे कि औरत किसी भी जाति की हो, वो पिछड़ी ही है। बाद में नीतीश सरकार ने साल 2007 में महादलित आयोग बनाया। नीतीश कुमार के लव-कुश (कुर्मी-कोइरी) समीकरण को देखें तो इनकी आबादी तकरीबन सात फीसदी है, लेकिन अपनी वोट इंजीनियरिंग की मदद से नीतीश के पास 20 फीसदी वोट माने जाते हैं। जब नीतीश कुमार सरकार में आए तो उनकी दो योजनाओं को बदलते बिहार के रूप में देखा गया। वो थीं- यूनिफॉर्म और साइकिल योजना। ग्रामीण इलाकों में साइकिल से जाती स्कूल यूनिफॉर्म पहनी लड़कियों को लोगों ने बदलते बिहार के तौर पर देखा। दरअसल ये तस्वीर दो मोर्चे पर काम कर रही

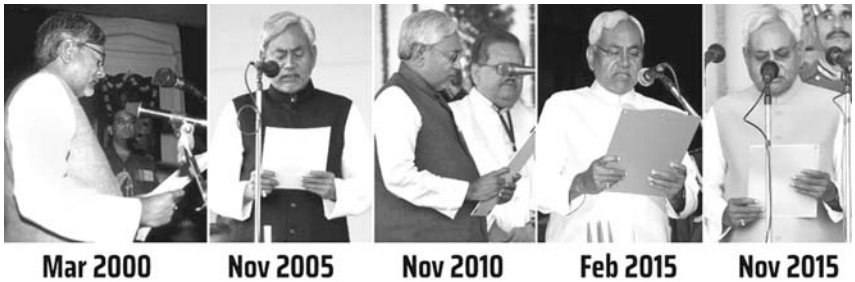

Mar 2000 Nov 2005 Nov 2010 Feb 2015 Nov 2015

Jul 2017 Nov 2020 Aug 2022 Jan 2024 Nov 2025

थी। एक तरफ ये समाजवादी नीतीश का वेलफेयर स्टेट होने का प्रमाण था तो दूसरी तरफ सार्वजनिक जगहों पर बच्चियों का यूं आना कानून-व्यवस्था में सुधार का संकेत था, लेकिन बाद में नीतीश सरकार पर ये आरोप भी लगे कि योजनाओं को प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारने के बजाए प्रचार पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। बता दें कि नीतीश कुमार के कार्यकाल के सात-आठ साल शानदार थे। उनकी अफसरों की टीम अच्छी थी। महिलाओं के लिए सरकार ने अच्छे कदम भी उठाए, लेकिन बाद में सब कुछ स्थिर हो गया। ऐसा लगा नीतीश कुमार अपने किए काम पर खुद ही मंत्रमुग्ध होते रहे। बाद के दिनों में उन्होंने दिखावे पर काम किया। यानी वो काम जिसका प्रचार हो। उसमें टिकाऊपन कितना है, ये सरकार की चिंता नहीं रही। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने से पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस तो हुआ लेकिन क्या ये महिलाएं विधायक और मंत्री बनीं? आम महिलाओं के लिए भी जो काम किया गया वो उनकी पारंपरिक भूमिका को ही मजबूत करने वाले थे। यानी औरत को रोजगार से जोड़ना है तो सिलाई मशीन बंटवा दो, पापड़-बड़ी का प्रशिक्षण करवा दो। साल 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले जब जीविका दीदीयों को दस हजार रुपये की राशि रोजगार शुरू करने के लिए बांटी गई तब जेडीयू के अंदर से ही नीतीश कुमार की राजनीति में आए बदलाव

पर सवाल उठ रहे थे।

उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार अपने शासनकाल में बार-बार दोहराते रहे कि वो 'थ्री सी' से कभी समझौता नहीं करेंगे। थ्री सी यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। नीतीश कुमार ने सीएम पद संभालने के बाद पुलिस का राज चाहते थे, कानून का राज चाहते थे। आर्म्स एक्ट, स्पीडी ट्रायल के साथ-साथ गवाही पर बहुत काम भी हुआ। बाद में सैप का गठन किया गया और पुलिस जांच का आधुनिकीकरण भी हुआ। इन सब ने पुलिस की इमेज को बदला, लेकिन बाद के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने नीतीश सरकार की किरकिरी की। इनमें से एक घटना साल 2015 में घटी, जब मोकामा विधायक अनंत सिंह के पटना स्थित आवास पर एक नेशनल टीवी चैनल के पत्रकार को बंधक बना लिया गया। इसी तरह रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के बाद उनकी शव यात्रा, उनके समर्थकों ने पटना शहर के प्रमुख स्थानों से होते हुए निकाली। उस दिन पटना शहर का दिल कहे जाने वाले डाकबंगला चौराहा समेत अन्य प्रमुख स्थानों पर बड़े पैमाने पर आगजनी और हिंसा हुई थी। उस दिन पटना की हालत देखकर लगता था कि ये राज्य दोबारा 90 के दशक की जातीय हिंसा मे चला जाएगा, अच्छी बात ये रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनके शासन में औरंगाबाद, छपरा, बिहारशरीफ में दंगे हुए। भ्रष्टाचार का आलम ये है कि बिना दिए कोई फाइल नहीं सरकती। नीतीश कुमार की जो पकड़ शासन व्यवस्था पर पहले कभी रही, वो ढीली होती गई। नीतीश कुमार ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने अपनी सरकार को जवाबदेह बनाने की कोशिश की। तय समय पर प्रभावी ढंग से जनता का काम सुचारू ढंग से निपटे, इसे करने के लिए जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम शुरू हुआ। जानकारी कॉल सेंटर, आपकी सरकार आपके द्वार, बिहार लोक सेवा अधिकार जैसे कार्यक्रम बहुत उत्साह से शुरू हुए, लेकिन बाद में ये धीरे-धीरे धराशायी होते गए। जानकारी कॉल सेंटर, सूचना के अधिकार से जुड़ा कॉल सेंटर है जो साल 2007 में शुरू हुआ था। बहुत जोर-शोर से शुरू हुआ जानकारी कॉल सेंटर बंद हो गया। एक-एक अपील की सुनवाई में कई

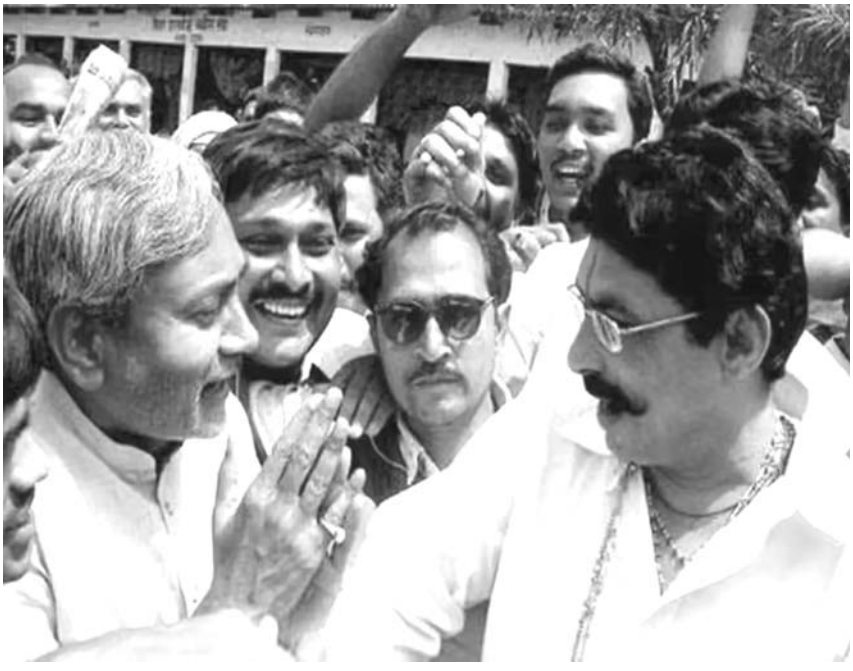

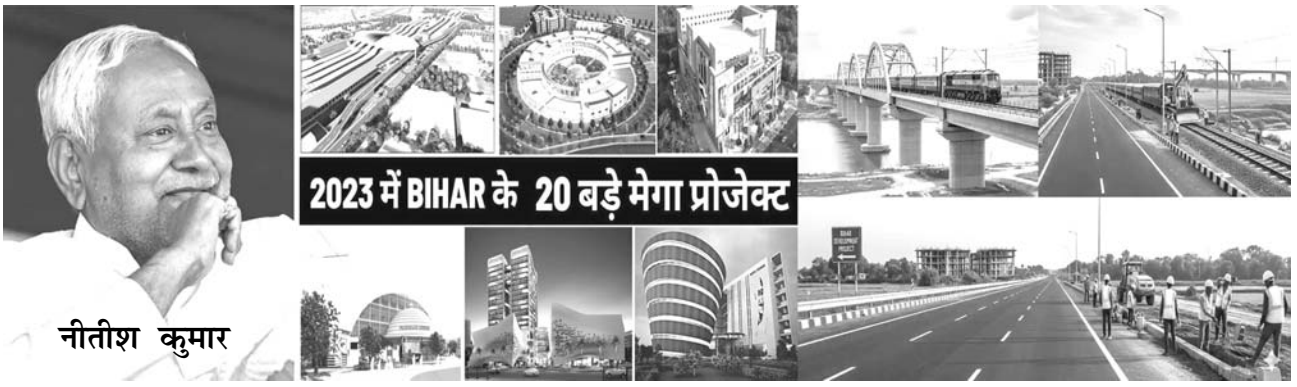

साल लग जाते हैं जबकि आरटीआई टाइम बाउंड है। जवाबदेही खत्म हो गई है और आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या, उन्हें डराना धमकाना और झूठे केस में फंसाना आम बात हो गई है। हालांकि सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया लेकिन अगर अच्छे टीचर या डॉक्टर नहीं हैं तो इसका कोई फायदा नहीं। दूसरा ये कि नीतीश कुमार ने भी पीपीपी मॉडल पर ही काम करना शुरू कर दिया, जिसने पूरे सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल दिया है। ये सब नीतीश के शुरुआती दौर से अलग था। साल 2006 में जारी श्वेत पत्र के मुताबिक बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत उस वक्त महज 60 किलोवाट प्रति घंटा थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक 2011-12 में प्रति व्यक्ति खपत 134 किलोवाट प्रति घंटा हुई जो 2025-26 में बढ़कर 374 किलोवाट हो गई। ग्रामीण सड़कों की बात करें तो साल 2005-06 में जो महज 835 किलोमीटर बनी थी, वो अब 1,19,067 किलोमीटर बन गई। गांव और शहर में सड़कों का जाल बिछा। पुल-पुलिया, फ्लाईओवर के निर्माण में गति आई। हालांकि ये अब भी नीतीश कुमार के उस दावे से दूर है, जिसमें वो कहते हैं कि बिहार के किसी भी कोने से पटना महज पांच घंटे में पहुंच जाएंगे। नीतीश सरकार भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, रोजगार और उद्योग के मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। भूमि सुधार को लेकर नीतीश सरकार ने डी. बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। वहीं कॉमन स्कूल सिस्टम को लेकर मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में कमीशन बना था, लेकिन वो ये दोनों रिपोर्ट लागू नहीं करवा पाए। उनकी सरकार में प्राइवेट संस्थान खुले और पब्लिक इंस्टीट्यूशन बर्बाद होते रहे। सरकार आने के बाद जिस तरह से पंचायत के स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई उसने शिक्षा की गुणवत्ता को बहुत कमजोर किया। बिहार सरकार असल में ठेकेदारों की सरकार बन गई है। आप जो फ्लाईओवर शहर में देखते हैं वो अपर मिडिल क्लास की जरूरतों को पूरा करती है। हाशिए पर जो बिहारी समाज है उसके लिए क्या है? सरकार कागजों में जिस ग्रोथ के बारे में कहती है

वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की है। उद्योग, रोजगार, पलायन के मुद्दे पर सरकार असफल रही है, जबकि ये बिहार के सबसे जरूरी मुद्दे हैं। सारे विकास सूचकांकों में अब भी हम सबसे नीचे हैं। वही साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को बंपर जीत मिली थी। इसे 243 में 206 सीट मिली थी, जिसमें अकेले जेडीयू को 115 और मुख्य विपक्षी दल आरजेडी को महज 22 सीटें मिलीं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के उभार को लेकर असहज नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़कर साल 2015 का विधानसभा चुनाव आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर लड़ा। साल 2015 में बिहारियों के डीएनए सैंपल दिल्ली भेजकर नीतीश ने अपना विरोध जताया था। बाद में वो फिर साल 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन में आए। साल 2022 में नीतीश कुमार ने फिर से आरजेडी-कांग्रेस के साथ गठबंधन किया लेकिन 2024 में यह गठबंधन तोड़ दिया, तब से उनकी पार्टी जेडीयू और बीजेपी साथ हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश बार-बार ये दोहराते रहे कि उन्होंने आरजेडी के साथ जाकर दो बार गलती की है, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। कभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ने वाले नीतीश अब विशेष पैकेज पर मान गए हैं। कभी बिहार दिवस का भव्य आयोजन करके 'बिहारियत' और बिहारी होने को 'गर्व' से जोड़ने वाले नीतीश अब कमजोर पड़ चुके हैं। जब नीतीश ने बिहार का शासन संभाला था तब उनकी उम्र 54 साल थी, अब वो 75 पार कर चुके हैं।

बहरहाल, बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या बीजेपी के पास अपना कोई बड़ा नेता नहीं था जो उसे बाहर से आए सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा? यह सवाल जितना सीधा है, उसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। दरअसल, बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं है, बल्कि कमी एक ऐसे ऑलराउंडर चेहरे की थी जो जाति का गणित भी बिठा सके और पूरे बिहार में जिसकी पहचान भी

हो। कुल मिलाकर बात इतनी सी थी कि पार्टी को एक ऐसा चेहरा चाहिए था, जो लालू और तेजस्वी के वोट बैंक में सेंध लगा सके। सम्राट चौधरी इस मामले में फिट बैठे। बिहार में बिना जाति के राजनीति नहीं चलती। बीजेपी के पास नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह और विजय कुमार सिन्हा जैसे बड़े नाम तो हैं, लेकिन सबकी अपनी-अपनी कुछ सीमाएं हैं। कोई एक इलाके तक सिमटा है, तो किसी की छवि इतनी कड़क है कि हर वर्ग उनसे नहीं जुड़ पाता। मंगल पांडे जैसे नेता प्रशासन चलाने में तो माहिर हैं, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो सड़क पर उतरकर विपक्ष को सीधी टक्कर दे सके। बस यहीं पर सम्राट चौधरी बाजी मार ले गए। सम्राट चौधरी को कमान सौंपना बीजेपी की एक सोची-समझी चाल है। वह कुशवाहा समाज से आते हैं, जो बिहार में पिछड़ों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी को पता है कि अगर उसे बिहार में अपने दम पर सत्ता लानी है, तो उसे गैर-यादव पिछड़ों को अपने पाले में लाना ही होगा। 2020 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन फिर भी वह नीतीश कुमार के पीछे रही। अब सम्राट चौधरी के जरिए पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह अब किसी के भरोसे नहीं, बल्कि खुद लीड करना चाहती है। सम्राट चौधरी की ताजपोशी के पीछे सबसे बड़ा कारण उनका लड़ाकू अंदाज है। आज की राजनीति में सिर्फ चुपचाप काम करने से बात नहीं बनती, आपको विरोधियों की आंखों में आंखें डालकर बात करनी पड़ती है। तेजस्वी यादव के आक्रामक हमलों का जवाब देने के लिए बीजेपी को एक ऐसा ही फाइटर चाहिए था। सम्राट चौधरी न सिर्फ अपनी बात मजबूती से रखते हैं, बल्कि उनकी मौजूदगी जमीन पर भी दिखती है। वह एक ऐसे नेता हैं जो हर गुट को साथ लेकर चल सकते हैं और पार्टी के अंदरूनी झगड़ों को भी खत्म करने की ताकत रखते हैं। एक और अहम बात यह है कि बीजेपी अब 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। ऐसे में पार्टी को एक ऐसा नया चेहरा चाहिए था जो लोगों के मन में बैठी पुरानी नाराजगी को दूर कर सके और नए वोटर्स को जोड़ सके। सम्राट चौधरी को आगे करके बीजेपी ने यह दांव इसलिए खेला है ताकि वह बिहार में दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनने के बजाय अब खुद नंबर वन की भूमिका में आ सके। पार्टी के अंदरूनी हालात भी देखें तो किसी पुराने दिग्गज को प्रमोट करने पर आपसी खींचतान का डर था। सम्राट चौधरी इस मामले में एक न्यूट्रल चॉइस साबित हुए। उनके आने से पार्टी के कैडर में एक नई ऊर्जा दिखी है। कुल मिलाकर, बीजेपी ने यह दिखा दिया है कि वह जीत के लिए बड़े प्रयोग करने से नहीं हिचकिचाती। सम्राट चौधरी का सीएम बनना सिर्फ एक पद का बदलाव नहीं है, बल्कि बिहार में बीजेपी के एक नए युग की शुरुआत है, जहां वह पूरी तरह से कमान अपने हाथ में लेना चाहती है।

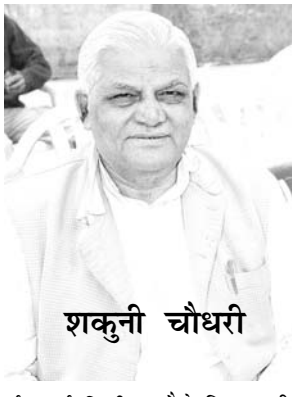

शकुनी चौधरी

गौरतलब है कि पूर्व मंत्री पिता शकुनी चौधरी के साथ आरजेडी में लंबी पारी खेलने वाले सम्राट चौधरी कुछ समय के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में रहे। फिर जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में गए। 2018 में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें भाजपा में लाने वाले पार्टी के दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी थे। उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय थे। सम्राट को नित्यानंद की टीम में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी। साल 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी तो सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री बनाए गए। जब 2021 में एनडीए गठबंधन टूट गया तो सम्राट चौधरी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई। सदन में उन्होंने विरोधी दल के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी। जनहित के मुद्दे पर सम्राट चौधरी ने सरकार को कई बार असहज किया। विपक्षी नेता के तौर पर सम्राट चौधरी के तेवर को देखते हुए उन्हें मार्च 2023 में सांसद संजय जायसवाल के स्थान पर बिहार भाजपा की कमान सौंपी गई। एक बात और रही की पिता शकुनी चौधरी नरेन्द्र मोदी के धुर विरोधी रहे, तो बेटे सम्राट को बीजेपी ने बिहार की कमान कैसे सौंपी दी। जो काम सुशील मोदी के दौर में नहीं हुआ, वो सम्राट ने कैसे किया? नीतीश ने खुद ताली बजाकर कुर्सी सौंपी। जो बिना पगड़ी बांधे सीएम पद की शपथ लेते हैं तो लोगों को इनका पुराना बयान याद आ जाता है। जब इन्होंने कहा था नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने पर ही पगड़ी खोलूंगा। हालांकि नीतीश जब आरजेडी छोड़कर एनडीए में आए थे, तभी सम्राट ने अयोध्या में स्नान कर

अयोध्या में स्नान कर पगड़ी हटाते सम्राट चौधरी

नित्यानंद राय

पगड़ी उतार दी थी। लेकिन आज लगता है प्रण पूरी तरह से पूरा हुआ है, जैसा की तेजस्वी भी कह रहे हैं। क्योंकि बीजेपी लंबे वक्त से बिहार में अपना सीएम बनाना चाहती थी। पर यहां पेच ये फंसा कि तेजस्वी यादव इन्हें सलेक्टेड सीएम बता रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी पहले आरजेडी में हुआ करते थे और नित्यानंद राय ने इन्हें बीजेपी ज्वॉइन करवाया था। मुंगेर के रहने वाले सम्राट चौधरी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने शुरुआती पढ़ाई मदरसे से पूरी की थी क्योंकि वहां सरकारी स्कूल बहुत दूर था। ये बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व वाली लाइन पर नहीं बल्कि लालू यादव के सियासी समीकरण पर चलने वाले नेता थे। आज भी सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी मोदी के धुर विरोधी माने जाते हैं, जिनका एक बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, 'मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, तमाम वर्गों से कहना चाहता हूं आपकी ताकत खाली नरेन्द्र मोदी के अगेंस्ट हो जाए। नरेन्द्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही दफन कर देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे। ये विश्वास दिलाते हैं।' फिर सवाल ये उठ रहा है कि सम्राट चौधरी ने सारी बातों के होते हुए भी बाजी कैसे मार ली। क्योंकि बिहार बीजेपी के पास चेहरों की कमी तो नहीं है। वहां उन नेताओं की लंबी फेहरिस्त है, जिन्होंने पार्टी को दशकों तक अपने पसीने से सींचा है। आपको याद होगा एक समय था जब नित्यानंद राय को बिहार भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था और वे मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार भी थे। लेकिन तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस सम्राट को पार्टी में लाया गया है, वे इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि खुद नित्यानंद राय और अन्य वरिष्ठ नेताओं के लिए बड़ी चुनौती बन जाएंगे। राजीव प्रताप रूढ़ी का प्रशासनिक अनुभव, मंगल पांडेय की सांगठनिक पकड़, प्रेम कुमार की वरिष्ठता और विजय सिन्हा का विधानसभा का अनुभव ये सब सम्राट चौधरी के उदय के सामने फीके पड़ते नजर आए। यहां तक कि पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी इस रेस में पीछे छूट गई, तो सवाल उठता है बीजेपी ने सम्राट चौधरी में क्या देखा जो नित्यानंद राय, मंगल पांडेय, विजय सिन्हा, राजीव प्रताप रूढ़ी, प्रेम कुमार और रेणु देवी जैसे नेताओं में नहीं दिखा। जानकार कहते हैं कि सम्राट चौधरी ने अपने राजनीतिक कौशल और पार्टी के कास्ट कार्ड के सटीक समीकरण से न केवल विपक्षी दलों को बल्कि अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं को मात दे दिया। उनके आक्रामक अंदाज के आगे सब फीके पड़ गए। इन्होंने हाई कमांड के हर आदेश को फॉलो किया। जब नीतीश ने गठबंधन तोड़ा तो सम्राट ने उन्हें भी खूब कोसा और जब नीतीश वापस आए तो आरजेडी पर सम्राट खूब हमलावर रहे। यही वजह रही कि जब इनके नाम का ऐलान हुआ तो नीतीश कुमार ने खुद इन्हें ताली बजाकर कुर्सी सौंपी। क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस लव-कुश समीकरण यानी कुर्मी-कोइरी जाति के सहारे बिहार में राज किया, उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सम्राट के पास है। क्योंकि नीतीश कुर्मी जाति से थे जबकि सम्राट कोइरी जाति से आते हैं। अगर नीतीश बेटे को कुर्सी सौंपते तो परिवारवाद का आरोप लगता। इसीलिए सम्राट के नाम पर संघ की पूरी तरह से सहमति न बनने के बावजूद भी बीजेपी ने सम्राट को चुना और बिहार में चर्चा होने लगी कि सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए क्या दूसरे हिमंता बिस्वा सरमा साबित होंगे। क्योंकि हिमंता भी कभी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। लेकिन कांग्रेस से नाराजगी के बाद वो बीजेपी में आए तो पार्टी ने उन्हें सीएम बनाकर बड़ा दांव खेल दिया था और सम्राट के साथ भी अब यही हुआ है।

विदित हो कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का पहला मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी के प्रमोशन में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष और पूर्व सीएम नीतीश कुमार का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण है। सम्राट के पिता शकुनी चौधरी अपने जमाने के कद्दावर नेता हैं और जब नीतीश ने समता पार्टी बनाई थी, तब वो उनके साथ 'लव-कुश' समीकरण के सूत्रधार थे। शकुनी, नीतीश के पुराने साथी हैं। कभी नीतीश को हटाकर ही मुरेठा खोलने की बात करने वाले सम्राट पर नीतीश का भरोसा कोई 2024 में डिप्टी सीएम बनने के बाद नहीं पैदा हुआ है। सम्राट ने यह भरोसा 12 साल पहले 2014 में ही लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को तोड़कर हासिल किया था, तब नीतीश भाजपा से गठबंधन तोड़कर अकेले थे। राजद को तोड़ने के बाद सम्राट, नीतीश के साथ हेलिकॉप्टर से उड़कर परबत्ता गए थे, जो उनकी विधानसभा सीट थी। नीतीश ने नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाने के विरोध में 2013 में बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया था। उस समय कांग्रेस, लेफ्ट और कुछ निर्दलीय की मदद से नीतीश ने सदन में बहुमत साबित किया था, लेकिन नंबर का तनाव बना रहता था। ऐसे माहौल में लोकसभा चुनाव से पहले लालू यादव

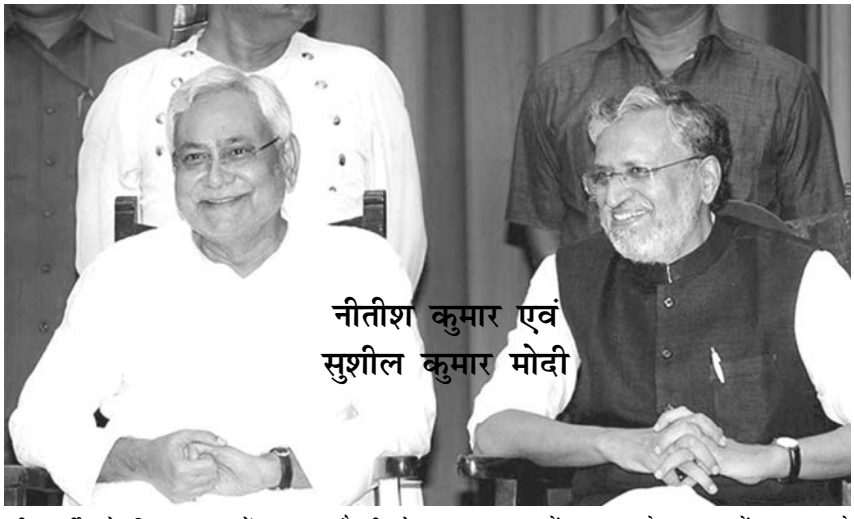

नीतीश कुमार एवं
सुशील कुमार मोदी

की पार्टी के विधानसभा में सम्राट चौधरी ने राजद के 22 में से 13 विधायकों को तोड़कर सदन में अलग मान्यता मांग ली थी। बाद में 6 विधायक यह बोलकर पलट गए कि उनका दस्तखत फर्जी है या कुछ और बोलकर साइन कराया। सम्राट तब समय परबत्ता विधायक थे और सीएम के हेलिकॉप्टर में सवार होकर अपने इलाके में नीतीश को लेकर गए थे। 57 साल के सम्राट चौधरी का राजनीतिक करियर कई दलों से होते हुए भाजपा में पहुंचने के बाद ही परवान चढ़ा है। उनके पिता शकुनी चौधरी भी कांग्रेस से समता पार्टी होते हुए राजद, जदयू और हम में रहे। सम्राट का सफर राजद से शुरू होकर जदयू और हम से होते हुए भाजपा तक पहुंचा। राजद की राबड़ी देवी सरकार में जब वो पहली बार मंत्री बने तो भाजपा के सुशील मोदी ने उनकी उम्र पर सवाल उठाया तो राज्यपाल ने उनको हटा दिया था। बाद में वो राजद के टिकट पर परबत्ता सीट से दो बार जीते। 2014 में राजद छोड़ने के बाद सम्राट और शकुनी जदयू में शामिल हो गए। लेकिन, 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश और लालू ने हाथ मिलाया तो वो जीतनराम मांझी के साथ हम में चले गए। विधानसभा चुनाव में हम की शर्मनाक हार हुई। खुद शकुनी चौधरी तारापुर से हार गए। शकुनी ने हम का प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ा और राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा तक कर दी। कुछ समय राजनीतिक माहौल और संभावना तलाशने के बाद सम्राट चौधरी भाजपा के संग हो गए। रोचक बात यह है कि समय बदला तो वही सुशील मोदी, सम्राट को भाजपा में लेकर आए। भाजपा में 2017 में शामिल हुए सम्राट ने तेजी से अपनी जगह बनाई और रफ्तार के साथ तरक्की की है। भाजपा को सम्राट के तौर पर एक आक्रामक ओबीसी चेहरा मिला, जिसे पार्टी ने कुशवाहा वोट बैंक को साधने के मकसद से आगे बढ़ाया। सम्राट को जल्द ही प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष का पद मिल गया। बाद में भाजपा ने 2020 में सम्राट को विधान पार्षद बनाया। नीतीश सरकार में सम्राट को पहली बार भाजपा ने पंचायती राज मंत्री बनवाया। उसके बाद सम्राट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज की तारीख में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के पसंदीदा पिछड़े नेता सम्राट चौधरी को जब 2022 में भाजपा ने विधान परिषद में नेता विपक्ष बनाया तो उनके आक्रामक राजनीतिक तेवर ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को प्रभावित किया। फिर वो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बना दिए गए। नीतीश 2024 में जब महागठबंधन से लौटे तो सम्राट को पहली बार भाजपा विधायक दल का नेता और डिप्टी सीएम बनाया गया। लगभग दो साल में सम्राट ने राजनीतिक लगन और कौशल से अपने पदनाम के आगे लगा डिप्टी हटाकर बतौर सीएम बिहार की बागडोर थाम ली है।

बहरहाल, बिहार में सम्राट चौधरी ही क्यों? क्या है इसके पीछे की कहानी? दरअसल सम्राट चौधरी मूल भाजपाई नहीं हैं। फिर भी बिहार भाजपा में अमित शाह के सबसे दुलारे हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जब अमित शाह के ऊपर एक ही साथ गुजरात में कई केस चल रहा था तो वे बिहार आकर सुशील मोदी से मदद मांगी थी। लेकिन सुशील मोदी अमित शाह से साफ कह दिया था कि हम इस तरह के केस में कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अमित शाह निराश होकर बिहार से चले गए थे। गृह मंत्री अमित शाह को तड़ीपार कहकर पुकारा जाता था। लेकिन जब 2014 में मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री बने तो अचानक अमित शाह सुर्खियों में आए और मोदी के नाक के बाल बन गए। अमित शाह का बिहार में सबसे बड़ा दुश्मन सुशील मोदी और नीतीश कुमार थे। वे समय का इंतजार कर रहे थे कि कब मौका आएगा कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार को ठिकाना लगाया जाए। 2020 विधानसभा चुनाव में फिर से एनडीए को सरकार बनाने का मौका मिला। लेकिन इस मंत्रिमंडल में यह फैसला लिया गया कि सुशील मोदी बिहार में अब नीतीश कुमार के साथ उपमुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। बिहार में नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी हिट हो गयी थी और विकास के बेहतरीन काम हो रहे थे। सम्राट चौधरी पहले राजद, फिर जदयू और बाद में हम पार्टी से होते हुए भाजपा में प्रवेश करते हैं। कुछ ही वर्षों के अंदर सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष, नेता विरोधी दल और उपमुख्यमंत्री पद से नवाजा गया और अमित शाह के बदौलत बिहार भाजपा में सबसे ताकतवर नेता बन गए। उन्होंने सुशील मोदी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका जमकर अपमान किया और इतने बड़े नेता को कोई अहमियत नहीं दी। सुशील मोदी जो भाजपा को बिहार में खड़ा किया था, उनका कद तो छोटा किया ही गया, वे दो तीन वर्षों तक पार्टी में रहकर अपमान सहते रहे। जब सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का विरोध करना था तो वे नीतीश कुमार को क्या-क्या नहीं कहा और उन्हें हटाने के लिए सर पर मुरैठा बांधकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने के लिए बयानबाजी करते रहे।

सम्राट चौधरी एवं अमित शाह

फिर नीतीश कुमार जब महागठबंधन छोड़ भाजपा के साथ बिहार में सरकार बनाई तो सम्राट चौधरी को उपमुख्यमंत्री बनाया गया। वे भाजपा के अंदर हर फैसला लेते रहे और ऑरीजनल भाजपाई साईड होते चले गए। अब सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार के साथ गलबहियां मिलाकर उनका गुणगान करने लगे। सम्राट चौधरी को न कभी आरएसएस से कोई मतलब रहा, न भाजपा की नीति सिद्धांत से। बस वे अपने आका अमित शाह के इशारे पर काम करते रहे। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद जब फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने लड़कर नीतीश कुमार से गृह विभाग ले लिया। अब सरकार में नीतीश कुमार का इकबाल नहीं, सम्राट चौधरी का इकबाल काम करने लगा। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि सरकार का हर फैसला मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं सम्राट चौधरी के कार्यालय से होने लगा था। नीतीश कुमार बेवस और लाचार दिखने लगे। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के साथ साया की तरह रहने लगे और मुख्यमंत्री के पक्ष में कसीदा गढ़ने में सबसे आगे बने रहे। जदयू और भाजपा दोनों दलों के कुछ बड़े नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चारों तरफ से इस तरह घेर लिया गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने का निर्णय ले लिया। यह निर्णय स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नहीं है। बताया जा रहा है कि यह चक्रव्यूह कोई और नहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बनाया जिसका अक्षरश: पालन सम्राट चौधरी करते रहे और अमित शाह के मिशन को कामयाब करके दिखा दिया। इतना ही नहीं बिहार में जदयू, भाजपा से बड़ी पार्टी न बन जाए, नीतीश कुमार के इस मिशन को भी ध्वस्त कर देने में सफल रहे। लोग बताते हैं कि अमित शाह के इस मिशन में जदयू के भी कुछ नेता सम्राट को साथ देते रहे हैं। यह भी सच है कि भाजपा के अंदर सम्राट चौधरी का बहुत विरोध है। लेकिन एक कहावत है कि सैयां भेल कोतवाल तो डर काहे का। जब भाजपा के चाणक्य का हाथ सर पर हो तो बाकी किसका डर? सम्राट चौधरी इस समय नीतीश कुमार और अमित शाह दोनों के सबसे पसंदीदा बन गए हैं।

गौरतलब है कि सम्राट, विजय और विजेंद्र की टिकड़ी बीजेपी-जेडीयू ने यूं ही नहीं बनाई। आखिरकार बिहार के कुर्सी का खेल खत्म हुआ। नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी बीजेपी के कोटे से मुख्यमंत्री बने। जिन्हें राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जबकि जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया। विजय सिन्हा अब पूर्व डिप्टी सीएम हो चुके हैं, इसका उन्हें मलाल भी है किन्तु कुछ कर नहीं सकते। अभी मंत्रियों का शपथ होना बाकी है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि सम्राट विजय और बिजेंद्र की टिकड़ी पर जेडीयू बीजेपी ने भरोसा क्यों जताया? आखिर यह रणनीति क्या है? तो इसे समझने के लिए इनका बैकग्राउंड देखना होगा। कोयरी जात से आने वाले सम्राट चौधरी, मोदी शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं। भूमिहार जात से आने वाले विजय चौधरी नीतीश के भरोसेमंद कहे जाते हैं। जबकि बिजेंद्र यादव की यादव वोट बैंक पर पकड़ अच्छी मानी जाती है। जिसका सीधा सा मतलब यह है कि बीजेपी ने नीतीश के लव-कुश समीकरण, लालू के यादव नीति और यूजीसी से हुए सवर्णों की नाराजगी के मुद्दे को एक साथ साधने की कोशिश की है। इसके अलावा बिहार की जनता जो नीतीश राज की तारीफ करती है, उसे वही सुकून दिलवाने के लिए सम्राट चौधरी ने कुर्सी संभालते ही काम शुरू कर दिया है। वह शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचते हैं। जहां जरूरी फाइलों की समीक्षा करने के बाद मुख्य सचिव समेत अलग-अलग विभाग के सचिवों के साथ बैठक करते हैं। सम्राट चौधरी की पहली मीटिंग यह बता रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था से लेकर रोजगार तक के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पर सम्राट के सामने चुनौती सिर्फ बिहार को आगे बढ़ाने की नहीं बल्कि चुनौती इस बात की भी है कि कैसे वो हाईकमान के भरोसे को सही साबित करते हैं। क्योंकि आरजेडी और जेडीयू से बीजेपी में वह आए, उसके बाद सत्ता के शिखर पर पहुंच गए। जबकि लंबे वक्त से बीजेपी से जुड़े नेता अपनी बारी का इंतजार करते रह गए। हालांकि सम्राट ऐसे इकलौते नेता नहीं हैं। बल्कि बीजेपी ने ऐसे सात उदाहरण पहले भी पेश किए

हैं। उदाहरण देखे तो जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक पहले कांग्रेस में थे, फिर बसपा के ब्राह्मण चेहरा बने। 2017 में बीजेपी में शामिल हुए और डिप्टी सीएम बन गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता रहे अर्जुन मुंडा जब बीजेपी में आए तो वह वहां के सीएम भी बने और बाद में उन्हें केंद्रीय मंत्री तक की कुर्सी मिली। कर्नाटक में कुछ साल पहले येदियुरप्पा की जगह लेने वाले बसवराज बोम्मई पहले जनता दल और जेडीयू में रहे। उसके बाद बीजेपी में आए थे। त्रिपुरा में बिप्लव देव को रिप्लेस करने वाले मणिक साहा पहले कांग्रेस में रहे। लेकिन बीजेपी में जैसे ही आए उन्हें सीएम तक की कुर्सी मिल गई। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी अपनी सियासी पारी कांग्रेस से शुरू की थी। लेकिन बीजेपी में आए तो इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह का बैकग्राउंड ना तो बीजेपी से रहा और ना ही संघ से। वो अलग पार्टी से थे। बावजूद उसके बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा भी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी में आए उनका कद बढ़ता चला गया। यानी कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेता बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बड़े पदों तक पहुंच गए। हालांकि सम्राट चौधरी किस हालात में बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि शपथ ग्रहण समारोह ऐसा लगा जैसे कोई औपचारिकता निभाई जा रही हो। ना उत्साह, ना ऊर्जा, ना वो राजनीतिक चमक-दमक थी। शपथ ग्रहण में ना नरेंद्र मोदी दिखे, ना अमित शाह। बीजेपी के बड़े चेहरे गायब रहे। किसी भी राज्य का कोई मुख्यमंत्री तक शामिल नहीं हुआ। मंच सजा था, लेकिन माहौल जैसे मातम का लग रहा हो। अब जरा दिल्ली को याद कीजिए, जब दिल्ली में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री को शपथ

दिलाया था, तो वो सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं था, वो एक शक्ति प्रदर्शन था। पूरा केंद्रीय नेतृत्व मौजूद, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, भव्य मंच, बड़ी भीड़ थी। दिल्ली में जश्न था। बिहार में जैसे मजबूरी थी, जबकि बीजेपी के लिए आज का दिन सबसे बड़ा होना चाहिए। हिंदी पट्टी का एकमात्र राज्य बिहार था, जहां बीजेपी अपना सीएम नहीं बना पा रही थी। कई दशक से बीजेपी इस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही थी। क्यों? क्योंकि ये जीत नहीं, समझौता ज्यादा लग रही है। नीतीश की जिद्द ने सम्राट चौधरी के लिए यह रास्ता बनाया, बीजेपी ने हां किया। लेकिन दिल से नहीं, दबाव में। अंदर की बात तो यही है कि आरएसएस-बीजेपी के कार्यकर्ता खुश कम, उलझन में ज्यादा हैं।

जिन्होंने सालों तक नारे लगाए, जमीन पर पसीना बहाया, वो आज पूछ रहे हैं, "क्या यही वो दिन था जिसका इंतजार था?

बहरहाल, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली तो नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब पांच महीने के बाद सीएम पद से उनका मोहभंग हो गया और फिर से सांसदी करने के लिए राज्यसभा का रास्ता अपनाया है। नीतीश कुमार ने जहां से आकर बिहार की सत्ता अपने हाथ में ली थी, अब फिर से वहीं लौट गये। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद तय हो गया है कि बिहार में दो दशकों से चला आ रहा 'सुशासन बाबू' का युग समाप्त होने की दिशा में है। नीतीश का दिल्ली जाना केवल एक नेता का सियासी पलायन नहीं है, बल्कि बिहार की उस राजनीति का अंत है, जहां एक क्षेत्रीय दल बड़े दलों की सियासत को अपने तरह से तय करता रहा है। अंत में विकास पुरूष नीतीश कुमार जी, जिन्होंने बिहार के विकास में सर्वस्व न्यौछावर किया उन्हें राज्यसभा सदस्य बनने पर एवं बिहार के विकास को चहुंमुखी दिशा देने तथा विधि -व्यवस्था को दुरूस्त करने का संकल्प लेकर बिहार में पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी जी के साथ नये सरकार के नये उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी एवं बिजेंद्र यादव जी को केवल सच पत्रिका शुभकामना प्रेषित करती है।●

पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान-2026 संपन्न

● संजय सिन्हा

भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ता और संगठनात्मक विकास के लिए आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेगा प्रशिक्षण अभियान 2026 के तहत, दिल्ली भाजपा ने 4 अप्रैल 2026 से इस सप्ताहांत 61 मंडलों में 24 घंटे के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए, जिसमें सभी महिला पुरुष कार्यकर्ता ने भाग लिया जो कुल सात सेशन में सफल बनाया गया पहले दिन 6 सेशन हूए जबकि दूसरे दिन बचे सिर्फ एक सेशन को सफल बनाई गई, इस एक दिवसीय भाजपा कार्यशाला में सक्रिय कार्यकर्ताओं को हरेक पहलुओं की जानकारी दी गई एवं विचारधारा आधारित राजनीति को आगे बढ़ाया एवं बताया कि भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी पहली राजनीतिक दल है। जो 'राष्ट्र प्रथम' की अवधारणा से प्रेरित हमारी पाटी का अधिष्ठान सिद्धांतों में है. न किसी परिवार या वंश, जाति अथवा मजहब में है। जो राष्ट्र प्रथम पार्टी दूसरा एवं अंत में स्वयं को रखने की भावना से हम अनुप्राणित हैं।

राष्ट्र को जोड़ने वाला सूत्र है- भारत के सांस्कृतिक मूल्य, हमारी निष्ठाएं और भारत के परम वैभव को प्राप्त करने का संकल्प और यह आत्मविश्वास भी कि अपने पुरुषार्थ से हम इन्हें प्राप्त करेंगे।

☞ **सांस्कृतिक राष्ट्रवाद :-** हमारे सिद्धांत की अभिव्यक्ति 'भारत माता की जय' उद्घोष से होती है। यह उद्घोष हमारे सिद्धांत का बीजभूत आधार है। भारत (भूमि), माता (संस्कृति) तथा जय (जनाकांक्षा) को व्यक्त करते हैं। हम मानते हैं श्भू, जन एवं संस्कृति के योग से राष्ट्र उत्पन्न होते हैं। इसीलिये राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्रसेवा हमारे कार्य का आधार है। राष्ट्र का अधिष्ठान संस्कृति में ही होता है। भारतीय संस्कृति 'भूमि' को माता व 'जन' को संतान के रूप में देखती है। हमारे देश की राष्ट्र चेतना के विस्तार का विवरण प्राचीन काल से ही वेदों से लेकर पौराणिक, मध्यकालीन एवं स्वतंत्रता आंदोलन के ग्रंथों एवं साहित्यों में मिलते हैं। अथर्ववेद के पृथ्वीसूक्त में 63 श्लोकों की एक मालिका है, जिसमें इस धरती के साथ हमारा संबंध क्या है, इसका पूर्ण विवरण है। माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्या! अर्थात् पृथ्वी मां का स्वरूप है और मानव उसका पुत्र। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मर्म-'भारत माता की जय' है। राष्ट्र हमारे अतीत से भी जुड़ा हुआ है और वर्तमान भी है। हमारी समृद्ध स्मृतियों की धरोहर है और सह अस्तित्व और जीवंत विरासत के मूल्यों का गौरवशाली प्रवाह है जो समृद्ध, सशक्त एवं सुदृढ़ भविष्य की ओर प्रेरित है।

☞ **एकात्म मानवदर्शन :-** भारतीय संस्कृति के मूल दर्शन को व्यक्त करने वाला समग्र विचार जो भारतीय जनसंघ ने 1965 में विजयवाड़ा में 'एकात्म मानववाद' के रूप में स्वीकार किया तथा पुनः भाजपा ने 1985 की राष्ट्रीय परिषद् में इसे अपना मूलभूत सिद्धांत स्वीकार किया। भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी भारत को प्राचीन एवं सनातन राष्ट्र मानती है। पश्चिम की राष्ट्र-राज्य परिकल्पना से पुरानी कल्पना भारत के 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की है। भारतीय संस्कृति की एक गौरवसम्पन्न ज्ञान-परम्परा है। हमें इसी ज्ञान-परम्परा में भारत का भविष्य खोजना चाहिए। अतः मौलिक भारतीय चिंतन के आधार पर विकल्प देने के लिए दीनदयाल जी ने सिद्धांत और नीति के रूप में 'एकात्म मानववाद' प्रस्तुत किया, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल दर्शन बना है। यह विचार व्यक्ति बनाम समाज नहीं वरन् व्यक्ति और समाज की एकात्मता का विचार है। यह मानव बनाम प्रकृति नहीं वरन् मानव के साथ प्रकृति की एकात्मता का विचार है। भौतिक बनाम अध्यात्मिक नहीं वरन् इनकी एकात्मता का विचार है। एकात्म मानवदर्शन में व्यक्ति के समग्र सुख की कल्पना

की गई है। इसमें शरीर, मन, बुद्धि एवं आत्मा के समन्वय और एकात्मता का विचार है तथा हर विषय को समग्रता में देखा गया है। व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि तथा परमेष्ठी से एकात्म हुआ मानव ही विराट पुरुष है। इसके पुरुषार्थ चतुर्यामी हैं, 'धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष' ये पुरुषार्थ मानव की परिस्थिति निरपेक्ष आवश्यकताएं हैं, इनकी सम्पूर्ति करना समाज व्यवस्था का काम है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास' यह अवधारणा का प्रकटीकरण है।

❖ **पंच निष्ठाएं :-** पंच निष्ठाओं के सैद्धांतिक आधार पर भारतीय जनता पाटी का निर्माण हुआ। भाजपा ने अपने प्रथम अधिवेशन के सैद्धांतिक रूप में 'पंच निष्ठाओं' की घोषणा की :-

☞ **राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता :-** हम सदैव याद रखते हैं। 'भारत माता की जय' और 'वन्दे मातरम्'। हम राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता के पुजारी हैं। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए हमने निरंतर संघर्ष किया है। 'जहां हुये बलिदान मुखर्जी- वह कश्मीर हमारा है'। इसका उदाहरण हैं धारा-370 का निरस्तीकरण, हमारी संकल्प-शक्ति को दर्शाता है।

☞ **लोकतंत्र :-** भाजपा सभी को साथ लाने के स्वभाव से कार्य करती है। प्रत्येक स्तर पर टोली का गठन एवं टोली में निर्णय पाटी में लोकतांत्रिक पद्धति के उदाहरण हैं। बूथ समिति से संसदीय बोर्ड तक संगठन आंतरिक लोकतंत्र का एक अनुपम उदाहरण है। आपातकाल के दौरान देश का लोकतंत्र बचाने में पार्टी का योगदान अविस्मरणीय है।

☞ **शोषणमुक्त एवं समतायुक्त समाज की स्थापना :-** स्वदेशी का उपयोग, स्वदेशी का प्रचार-प्रोत्साहन, रोजगार देने वाले उद्यम करे, क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रयोगों को प्रोत्साहन, कार्य-विस्तार में समाज के सभी लोगों का साथ, कार्य-संचालन में वंचित वर्ग को प्रोत्साहन, घर एवं कार्यालयों में समाज के सभी वर्गों के महापुरुषों के चित्र, भाषणों में वंचित वर्ग के महापुरुषों के उदाहरण, जयंती मनाना।

☞ **'सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता' अर्थात् सर्वधर्म-समभाव :-** मजहब, पंथ के आधार पर वोटबैंक तथा तुष्टीकरण की राजनीति का भाजपा विरोध करती है तथा सभी धर्म-पंथ को समान भाव से देखते दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने विश्वास नगर मंडल में सत्र को संबोधित किया, जबकि विभिन्न वरिष्ठ नेताओं और राज्य पदाधिकारियों ने कई मंडलों में अलग-अलग संगठनात्मक सत्रों को संबोधित किया।

कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सचदेवा ने एक बयान में कहा कि भाजपा भारत की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो कार्यकर्ता

निर्माण को गंभीरता से लेती है। उन्होंने आगे कहा कि नियमित प्रशिक्षण अभियानों के माध्यम से, पार्टी न केवल मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को अपने राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक एजेंडे के बारे में शिक्षित कर रही है, बल्कि केंद्र और दिल्ली में सरकारों के राष्ट्र निर्माण एजेंडे के बारे में भी जानकारी दे रही है, जिसके बाद वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी जानकारी दी जाती है। हुए भेदभाव रहित शासन तथा सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता के आधार पर जिसमें 'सबके लिए न्याय' हो, वैसा राष्ट्र निर्माण के लिए भाजपा कृतसंकल्पित है।

☞ **मूल्य-आधारित राजनीति और आर्थिक एवं राजनीतिक विकेंद्रीकरण :-** पारदर्शी व्यवहार, संयमित शब्दावली, कार्यक्रम संचालन, संग्रह आदि में पारदर्शिता, देशभर में प्रामाणिकता के उदाहरण भाजपा के कार्यकर्ताओं की पहचान है। आर्थिक एवं राजनैतिक विकेंद्रीकरण के प्रति आस्था।

चांदनी चौक के अंतर्गत आने वाले मंडल अध्यक्ष दीपक गुप्ता, निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल, महामंत्री जितेंद्र मरोड़ीया एवं लक्की कुमार, पूर्व मंडल अध्यक्षों में चरण सेठी,विशमबर वशिष्ठ,वरिष्ठ उपाध्यक्ष राहुल सिंह एवं अन्य महिला पदाधिकारी ने एक आर्दश कार्यशाला का आयोजन कियाद्य शायद ये पहलीबार कोई 24 घंटे की कार्यशाला लगी थी जिसमें अन्य विषय जैसे- पार्टी का ईतिहास एवं विकास, कार्य विस्तार की हमारी दृष्टि, संगठन की कार्यपद्धति, भारत सरकार की उपलब्धियां एवं क्रियान्वयन, सोशलमीडिया एआई नमो एप सरल एप, बूथ प्रबंधन एवं मन की बात टिफिन बैठक बूथ स्तरीय कार्यक्रम, रात्री अनौपचारिक कार्यक्रम, सरल एप एवं मंडल प्रशिक्षण व पंजिकरण और अंत में क्विज आदि। प्रदेश अध्यक्ष बिरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भाजपा एक वैचारिक पार्टी है और निरंतर प्रशिक्षण और संवाद के कारण इसके कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण और संगठन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देते हैं और इसलिए किसी भी समय पार्टी बदलने के लिए तैयार रहते हैं।

दिल्ली भाजपा के महासचिव और सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि 7 मार्च से 14 अप्रैल तक हर सप्ताहांत चलाए जा रहे अभियान के तहत 225 मंडलों में रात्रि शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशिक्षण अभियान 12 अप्रैल तक सभी मंडलों में पूरा हो जाएगा। दिल्ली इकाई के अध्यक्ष के अलावा, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, मेगा ट्रेनिंग टीम के राष्ट्रीय सह-प्रभारी राजकुमार शर्मा, दिल्ली अभियान प्रमुख कमलजीत सहरावत, सह-प्रभारी सुमित भासिन, सांसद योगेंद्र चंदोलिया और रामवीर सिंह बिधूड़ी सहित कई प्रमुख वक्ताओं ने इस सप्ताहांत सत्रों को संबोधित किया। अन्य प्रमुख वक्ताओं में प्रदेश महासचिव विष्णु मित्तल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, दिल्ली मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, पंकज सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, प्रदेश मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर, प्रदेश पदाधिकारी योगिता सिंह, अंकित सिंह बख्शी, सुनीता कांगड़ा, सोना कुमारी, सारिका जैन, शुभेंदु शेखर अवस्थी, विधायक कुलवंत राणा, शिखा रॉय और अनिल गोयल शामिल थे।●

महिला आरक्षण के समर्थन में
योगी का पैदल मार्च

● **संजय सक्सेना (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)**

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़क पर गजब नजारा देखने को मिला जब प्रदेश की योगी सरकार पैदल मार्च करते हुए नजर आई। भारतीय राजनीति में आमतौर पर विरोध का अधिकार विपक्ष के हिस्से में आता है। सरकारें फैसले लेती हैं और विपक्ष सड़कों पर उतरकर उनका विरोध करता है। लेकिन राजधानी लखनऊ में जो दृश्य देखने को मिला, उसने इस परंपरा को उलट दिया। सत्ता पक्ष खुद सड़क पर उतरा और निशाने पर विपक्ष रहा। महिला आरक्षण के मुद्दे पर निकली 'जन आक्रोश महिला पदयात्रा' ने साफ संकेत दे दिया कि आने वाले समय में यह मुद्दा सिर्फ संसद या विधानसभाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सड़कों से लेकर गांव-गांव तक राजनीतिक बहस का केंद्र बनेगा। राजधानी की सड़कों पर उस समय असामान्य हलचल दिखाई दी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हजारों महिलाएं और पार्टी कार्यकर्ता पैदल मार्च करते नजर आए। यह पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास से शुरू होकर विधानसभा तक पहुंची। करीब दो किलोमीटर लंबे इस मार्च में प्रशासनिक अनुमान के मुताबिक 15 हजार से अधिक महिलाओं की भागीदारी दर्ज की गई। तेज धूप और गर्म हवाओं के बावजूद महिलाओं की मौजूदगी ने इसे सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम से कहीं ज्यादा बड़ा शक्ति प्रदर्शन बना दिया।

इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि संसद में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक को लेकर बने गतिरोध से जुड़ी है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण देने के उद्देश्य से लाया गया।

संशोधन विधेयक बहुमत के बावजूद आवश्यक दो-तिहाई समर्थन हासिल नहीं कर सका। उपलब्ध संसदीय आंकड़ों के अनुसार इस विधेयक के पक्ष में लगभग 298 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 230 सांसदों ने विरोध किया। लेकिन संवैधानिक संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत पूरा नहीं होने से यह विधेयक पारित नहीं हो पाया। इसी घटनाक्रम के बाद सत्ता पक्ष ने इसे महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच ले जाने की रणनीति अपनाई। लखनऊ में निकली इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री के साथ दोनों उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के अलावा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सिर पर गमछा बांधे मुख्यमंत्री का पैदल चलना एक प्रतीकात्मक संदेश की तरह देखा गया। इससे यह संकेत देने की कोशिश रही कि सरकार इस मुद्दे को लेकर केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि इसे जन आंदोलन का स्वरूप देना चाहती है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। पिछले एक दशक में कई राज्यों के चुनावों में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर या कई जगहों पर उससे अधिक रही है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या करोड़ों में है और कई विधानसभा क्षेत्रों में उनकी भूमिका निर्णायक साबित होती रही है। ऐसे में महिला आरक्षण का मुद्दा सीधे तौर पर चुनावी गणित

को प्रभावित कर सकता है। पदयात्रा के दौरान नेताओं के भाषणों में विपक्षी दलों पर तीखे हमले देखने को मिले। पंकज चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ दल वोट बैंक की राजनीति के कारण महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर पीछे हट गए। उनका कहना था कि राजनीतिक समीकरणों के चलते महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी की गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि जो दल महिलाओं के अधिकारों के सवाल पर विरोध करते हैं, वे आधी आबादी के हितों के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। इस पूरे आयोजन का एक अहम पहलू यह भी रहा कि इसे केवल एक दिन के कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखने की बात कही गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिया कि इस आक्रोश को बूथ स्तर तक अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में ब्लॉक, मंडल और जिला स्तर पर इसी तरह के कार्यक्रमों की श्रृंखला देखने को मिल सकती है। यह रणनीति सीधे तौर पर संगठनात्मक मजबूती और जनसंपर्क दोनों को साधने की दिशा में उठाया गया कदम मानी जा रही है। महिला आरक्षण को 'आधी आबादी का अधिकार' बनाकर पेश करने की योजना भी इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी मुद्दे को व्यापक समर्थन दिलाने के लिए उसे भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर स्थापित करना जरूरी होता है। महिला आरक्षण के साथ 'आधी आबादी' का नारा जोड़कर इसे अधिकार और सम्मान के सवाल के रूप में पेश करने की कोशिश दिखाई दे रही है। इस पदयात्रा का एक सामाजिक पक्ष भी है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को लेकर लगातार प्रचार किया जाता रहा है। उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण, मातृत्व सहायता और आवास योजनाओं जैसे कार्यक्रमों का सीधा संबंध महिलाओं से जोड़ा गया है। अब महिला आरक्षण के मुद्दे को इन योजनाओं के साथ जोड़कर एक व्यापक सामाजिक संदेश देने की रणनीति बनती दिख रही है। इससे यह धारणा बनाने की कोशिश है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई स्तरों पर एक साथ काम किया जा रहा है। विपक्ष के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर विरोध या समर्थन की राजनीति जनता के बीच सीधी प्रतिक्रिया पैदा करती है। यदि सत्ता पक्ष इसे लगातार जन आंदोलन का रूप देता है, तो विपक्ष को भी अपनी रणनीति स्पष्ट करनी पड़ेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में इस मुद्दे पर बयानबाजी और कार्यक्रमों की संख्या बढ़ सकती है।

लखनऊ की इस पदयात्रा ने यह भी दिखाया कि राजनीति अब केवल संसद और विधानसभाओं की बहस तक सीमित नहीं रह गई है। अब हर बड़ा मुद्दा सड़क पर उतरकर जनता के बीच ले जाया जा रहा है। इससे एक तरफ राजनीतिक सक्रियता बढ़ती है, तो दूसरी तरफ जनमत को प्रभावित करने का नया तरीका भी सामने आता है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर निकली यह पदयात्रा इसी नई राजनीतिक शैली का उदाहरण मानी जा रही है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 15 हजार से अधिक महिलाओं की मौजूदगी किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए बड़ा संकेत होती है। यह संख्या केवल संगठनात्मक ताकत ही नहीं दिखाती, बल्कि यह भी बताती है कि किसी मुद्दे को लेकर किस स्तर तक लोगों को जोड़ा जा सकता है। यदि इसी तरह की भागीदारी अन्य जिलों में भी देखने को मिलती है, तो यह अभियान लंबे समय तक प्रभाव डाल सकता है। अंततः इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महिला आरक्षण अब केवल विधायी प्रक्रिया का विषय नहीं रह गया है। यह एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है, जिसके जरिए सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। लखनऊ की सड़कों पर उतरा यह आक्रोश आने वाले दिनों में किस दिशा में जाएगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि 'आधी आबादी' का सवाल अब राजनीति के केंद्र में मजबूती से स्थापित हो चुका है।●

आधी आबादी की योगी कैबिनेट में बढ़ेगी हिस्सेदारी!

● **अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)**

चुनावी साल में उत्तर प्रदेश की सियासत में राजनैतिक हलचल तेज होती जा रही है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की घड़ी सिर पर आ रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की ताकत को मजबूत करने के लिए कैबिनेट विस्तार की तैयारी में जुटे हैं। खास बात यह है कि इस विस्तार का केंद्र बिंदु महिला वोटरों को खुश करना हो सकता है। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के गिरने के बाद भाजपा ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विरोधी दलों पर महिला विरोधी होने का ऐसा तंज कसा है कि पूरा माहौल बन गया है। इसी माहौल का फायदा उठाते हुए योगी सरकार कैबिनेट में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर मतदाताओं का दिल जीतने की कोशिश कर सकती है। न केवल महिलाएं, बल्कि ब्राह्मण, पिछड़ी जाति और दलित वोटरों को भी रिझाने के लिए इन वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व देकर सियासी समीकरण सा जा सकते हैं। यह कदम चुनावी साल में सत्ताधारी दल की चतुराई का नमूना पेश करेगा।

राज्य की राजनीति हमेशा से जाति, धर्म और लिंग आधारित समीकरणों पर टिकी रही है। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर जोर दिया, लेकिन अब चुनावी दबाव में सामाजिक समावेश को प्राथमिकता मिल रही है। वर्तमान कैबिनेट में महिलाओं की संख्या सीमित है। बेबी रानी मौर्य और स्वाति सिंह जैसी कुछ नेता हैं, लेकिन कुल मिलाकर प्रतिनिधित्व कमजोर पड़ता है। अगर कैबिनेट का विस्तार होता है, तो डॉ. प्रोमिला कटियार या गोरखपुर की रवीना कुरेल जैसी सक्रिय महिला नेताओं को जगह मिल सकती है। पश्चिमी इलाके से मेरठ की राजकुमारी दीया या सहारनपुर की उषा सिद्धू भी दावेदार हो सकती हैं। इनमें से कई विधायक या सांसद हैं, जो जमीनी मुद्दों पर मुखर रही हैं। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भाजपा ने जो प्रचार किया, उसके जवाब में यह कदम महिलाओं को संदेश देगा कि हमारी सरकार उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने महिला आरक्षण बिल को लेकर जो शोर मचाया, वह अब विधानसभा स्तर पर फल दे सकता है। कांग्रेस

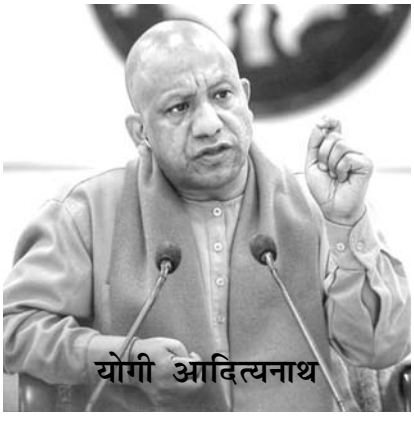
योगी आदित्यनाथ

राहुल गांधी

अखिलेश यादव

और समाजवादी पार्टी पर लगाए गए महिला विरोधी ठप्पे ने विपक्ष को रक्षात्मक बना दिया है। योगी सरकार इसी मौके को भुनाने के लिए कैबिनेट में कम से कम चार-पांच नई महिला मंत्रियों को शामिल कर सकती है। इससे ग्रामीण महिलाओं से लेकर शहरी मतदाताओं तक संदेश जाएगा कि भाजपा महिलाओं के हितों की रक्षा करेगी। उदाहरण के तौर पर, बुनकर बाहुल्य इलाकों से पिछड़ी जाति की महिलाओं को जगह देकर दोहरी रणनीति अपनाई जा सकती है। अवध क्षेत्र की लक्ष्मी चौधरी या बुंदेलखंड की सुनीता सिद्धू जैसी नेता इस फॉर्मूले में फिट बैठती हैं। कैबिनेट विस्तार से न केवल संख्या बढ़ेगी, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों और जातियों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित होगा। यह चुनावी लाभ के साथ-साथ सामाजिक संतुलन भी लाएगा। लेकिन महिला वोटरों को खुश करने की रणनीति केवल संख्या पर टिकी नहीं रहेगी। इन महिला मंत्रियों को महत्वपूर्ण विभाग सौंपे जाएंगे, जैसे महिला कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या ग्रामीण विकास। इससे साबित होगा कि यह प्रतीकात्मक कदम नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का माध्यम है। योगी सरकार पहले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुद्दलक्ष्मी योजना और पिंक बस जैसी योजनाओं से महिलाओं का विश्वास जीत चुकी है। कैबिनेट विस्तार इन प्रयासों को मजबूती देगा। विपक्षी समाजवादी पार्टी पर पिता-पुत्र की सियासत का आरोप लगाकर भाजपा महिलाओं को भावनात्मक रूप से जोड़ रही है। अखिलेश यादव सरकार के समय महिलाओं के प्रति उदासीनता के उदाहरणों को बार-बार उछाला जा रहा है। ऐसे में योगी का यह दांव विपक्ष को कटघरे में ला खड़ा करेगा।

अब बात ब्राह्मण, पिछड़ी जाति और दलित वोटरों की। उत्तर प्रदेश में ये वर्ग भाजपा की कोर वोट बैंक हैं, लेकिन हालिया लोकसभा परिणामों ने सतर्क कर दिया है। ब्राह्मण समाज में असंतोष की खबरें आ रही हैं। वर्तमान कैबिनेट में ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व कम है। कैबिनट विस्तार में प्रयागराज के नंद गोपाल गुप्त नंदी या कानपुर के सत्यदेव पचौरी जैसे वरिष्ठ ब्राह्मण नेताओं को जगह देकर इस गैप को भरा जा सकता है। ये नेता पार्टी के पुराने सिपाही हैं और जमीनी पकड़ रखते हैं। ब्राह्मण वोटरों को यह संदेश जाएगा कि उनकी उपेक्षा नहीं हो रही। इसी तरह पिछड़ी जाति के लिए निषाद, कुशवाहा और मौर्य समुदायों से प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। आजमगढ़ के शाह आलम या बहराइच के अनिल राजभर जैसे नाम चर्चा में हैं। ये वर्ग भाजपा के लिए गढ़ों में निर्णायक साबित होते हैं। दलित वोटरों को रिझाने की चुनौती सबसे बड़ी है। बसपा की कमजोरी का फायदा उठाते हुए भाजपा ने पहले ही कई दलित नेताओं को तरजीह दी है। लेकिन कैबिनेट में आनंद स्वरूप शर्मा या बाबू सिंह कुशवाहा जैसे चेहरे

जोड़कर बैंक को मजबूत किया जा सकता है। जालौन या झांसी जैसे दलित बाहुल्य क्षेत्रों से महिला दलित नेता को शामिल करना दोहरा लाभ देगा। योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व नीति ने इन वर्गों को एकजुट किया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जातिगत आकांक्षाएं भड़क रही हैं। कैबिनेट विस्तार इन्हें शांत करने का हथियार बनेगा। कुल मिलाकर 18 से 24 सदस्यों का विस्तार हो सकता है, जिसमें आठ-दस नए चेहरे महिलाओं, ब्राह्मणों, पिछड़ों और दलितों से होंगे। यह रणनीति चुनावी साल की देरी का फायदा उठाएगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट विस्तार से नए मंत्रियों को जमीनी मुद्दों पर सक्रिय होने का मौका मिलेगा। वे विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जनसभाओं में उतरेंगे और वोटरों से सीधा संवाद करेंगे। भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व भी इसकी हामी भर चुकी है। जेपी नड्डा और अमित शाह की राय में सामाजिक समावेश ही उत्तर प्रदेश फतह का राज है। विपक्षी एकता के बावजूद भाजपा का वोट शेयर मजबूत रहेगा। समाजवादी पार्टी की महापंचायतें और कांग्रेस की कोशिशें बेअसर साबित हो सकती हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की यह चाल लंबे समय तक असरदार रहेगी। 2017 और 2022 के चुनावों में भाजपा ने इसी तरह जातिगत संतुलन साधा था। अब महिला वोटरों को केंद्र में रखकर नया अध्याय लिखा जा रहा है। राज्य की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी महिलाओं की है और उनका झुकाव भाजपा की ओर बढ़ा है। कैबिनेट विस्तार इसी ट्रेंड को पक्का करेगा। ब्राह्मणों का ब्राह्मण वोट, पिछड़ों का ओबीसी समर्थन और दलितों की एकजुटता मिलकर योगी सरकार को मजबूत बनाएगी। विपक्ष को अब नई रणनीति सोचनी पड़ेगी।

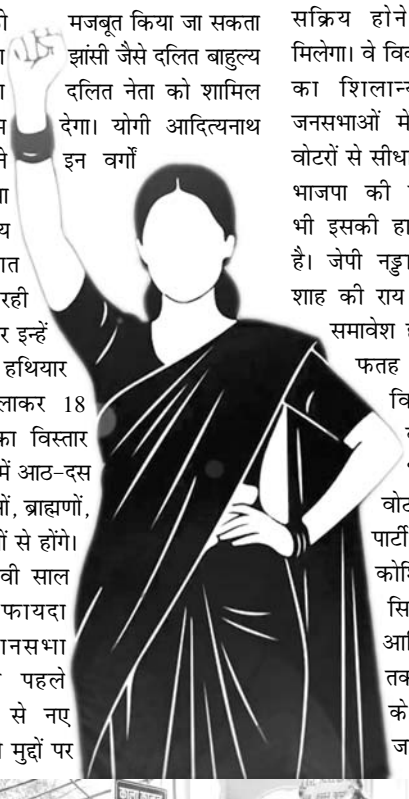

कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हैं। लखनऊ के सियासी गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल की बैठकें इसी मुद्दे पर केंद्रित हो रही हैं। जल्द ही औपचारिक घोषणा हो सकती है। इससे न केवल सरकार की छवि निखरेगी, बल्कि चुनावी वैतरणी पार करना आसान होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में यह कदम ऐतिहासिक साबित हो सकता है। महिलाओं को सशक्त बनाना और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना योगी मॉडल की पहचान बनेगा। विपक्षी दलों को अब सोचना होगा कि वे कैसे जवाब दें। कुल मिलाकर, यह विस्तार सत्ताधारी दल की दूरदर्शिता का प्रमाण होगा।●

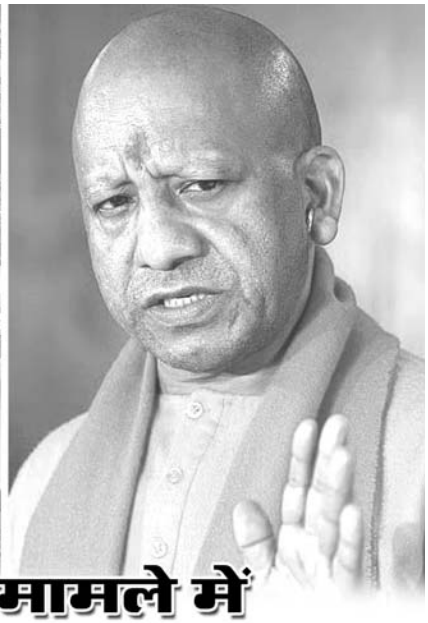

महिलाओं के सम्मान के मामले में योगी से काफी पीछे खड़े हैं अखिलेश

● अजय कुमार (वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ)

भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ वाले महिला वोट बैंक पर अब समाजवादी पार्टी की नजर लग गई है. पीडीए-पीडीए करते-करते सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रदेश की उन महिलाओं को लुभाने में लग गए हैं, जो अखिलेश यादव के शासनकाल में सबसे ज्यादा डरी सहमी रहती थी. इसी को मुद्दा बनाकर 2017 में बीजेपी ने यूपी में सत्ता हासिल की थी. इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है कि योगीराज में महिलाएं अपने आप को समाजवादी सरकार के समय से ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं. इस बात का प्रमाण है भाजपा को मिलने वाला महिलाओं का वोट. महिला वोटर खुलकर भाजपा के पक्ष में मतदान करते हैं, इसकी सबसे बड़ी समाजवादी सरकार के समय महिलाओं के साथ हुआ अत्याचार. खैर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते. अब अखिलेश यादव को महिलाओं के सम्मान की चिंता सताने लगी है. लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर जब महिलाओं का सम्मान समारोह शुरू हुआ तो माहौल एकदम अलग था। अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाली सैकड़ों महिलाओं को माला पहनाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश ने साफ कहा कि अगर 2027 में सपा की सरकार बनी तो 'नारी समृद्धि सम्मान योजना' शुरू होगी और इसके तहत गरीब परिवार की हर महिला को सालाना 40 हजार रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। साथ ही पुरानी समाजवादी पेंशन योजना को भी नई रूप में बहाल किया जाएगा। यह घोषणा महज कोई वादा नहीं बल्कि सपा की नई चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है जिससे आधी आबादी यानी महिला वोट बैंक को लक्ष्य बनाया गया है। वैसे बता दे इस तरह के दावे सपा प्रमुख अखिलेश यादव पिछले विधानसभा चुनाव में भी कर चुके हैं लेकिन महिला मतदाताओं ने उन पर विश्वास नहीं किया. दरअसल, अखिलेश यादव पिछले कई सालों से सत्ता वापसी की कोशिश में लगे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए भाजपा को काफी नुकसान पहुंचाया था। अब 2027 के लिए उन्होंने उस फॉर्मूले में एक और अक्षर जोड़ दिया है। वह है 'ए' यानी आधी आबादी। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि पीडीए के साथ 'ए' को जोड़कर महिला सशक्तिकरण को चुनावी एजेंडा बनाया जाएगा। कार्यक्रम में उन्होंने अपनी पुरानी योजनाओं का भी जिक्र किया। 1090 हेल्पलाइन हो या मुलायम सिंह यादव कन्या विद्याधन योजना और रानी लक्ष्मीबाई योजना, इन सबको याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि सपा हमेशा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने यह भी कहा कि

किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की स्थिति से तय होती है। अगर स्त्रियों की स्थिति की जानकारी हो जाए तो पूरे समाज की तस्वीर साफ हो जाती है।

कार्यक्रम का नाम रखा गया था मूर्ति देवी मालती देवी महिला सम्मान समारोह। मूर्ति देवी अखिलेश यादव की दादी और मुलायम सिंह यादव की मां थीं जिन्होंने मुलायम सिंह को सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने का संस्कार दिया। वहीं मालती देवी मुलायम सिंह की पत्नी और अखिलेश की मां थीं जिन्होंने घर संभालकर पति को राजनीति के लिए पूरी आजादी दी। अखिलेश ने इन दोनों विभूतियों को याद करते हुए कहा कि इन्हीं संस्कारों के चलते वह आज इस मुकाम पर हैं, लेकिन सवाल यह है कि महिलाओं का सम्मान करने के लिए उन्हें ऐसी कोई वीरांगना या सामाजिक आंदोलन चलाने वाली क्यों नहीं देखी जो उसके परिवार से इतर हो. सपा सांसद डिंपल यादव ने भी इस मौके पर कहा कि देश को आगे बढ़ना है तो महिलाओं को आगे आना होगा। उन्होंने चिंता जताई कि नई पीढ़ी की बेटियां कुछ पीछे छूटती जा रही हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। अगर वे अपनी

जिम्मेदारी निभाएं तो सत्ता परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। उन्होंने डायल 100 की पुरानी व्यवस्था का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने जान बूझकर वहां महिलाओं को रखा था क्योंकि वे दुख और तकलीफ को बेहतर समझती हैं। आने वाले समय में रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर नई योजना लाकर महिलाओं को और सम्मान दिया जाएगा।

बहरहाल इस सच्चाई को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा निर्णायक भूमिका निभाती रही हैं। 2017 के चुनाव में भाजपा ने अखिलेश सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को बड़ा मुद्दा बनाया था। तब एंटी रोमियो स्क्वायड जैसी पहल के साथ योगी सरकार ने इस वर्ग का विश्वास जीता। पिछले सालों में एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर जैसी नीतियों ने अपराधियों पर लगाम लगाई और महिलाओं को भयमुक्त माहौल देने का दावा किया गया। लेकिन अखिलेश अब कह रहे हैं कि मौजूदा समय में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं और पुलिस का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने लखनऊ के ग्रीन कॉरिडोर और दूसरे जिलों में घट रही घटनाओं का भी जिक्र किया जहां पुलिस पर दबाव का आरोप लगाया। उनका तर्क है कि आर्थिक मदद के साथ सुरक्षा का माहौल भी जरूरी है और यही कमी पूरी करने के लिए नारी समृद्धि योजना लाई जा रही है।

इस घोषणा का असर देखने के लिए बिहार का उदाहरण सामने है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं को 10 हजार रुपये का कारोबार शुरू करने के लिए मदद देने का ऐलान किया। राशि सीधे खातों में पहुंची और महिला वोट बैंक ने एनडीए को बड़ा समर्थन दिया। यूपी में भी योगी सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं लेकिन अखिलेश ने सीधे नकद 40 हजार रुपये सालाना देने का वादा कर बड़ा दांव खेला है। सपा प्रवक्ता दीपक रंजन ने कहा कि सपा शासन में महिलाएं सुरक्षित रहीं और अब आर्थिक मजबूती से वे और मजबूत होंगी। उनका दावा है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए महिलाएं सपा के साथ तेजी से जुड़ रही हैं। दूसरी ओर भाजपा ने तुरंत पलटवार किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा का मतलब ही महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालना है। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 से लेकर 2022 तक हर चुनाव में

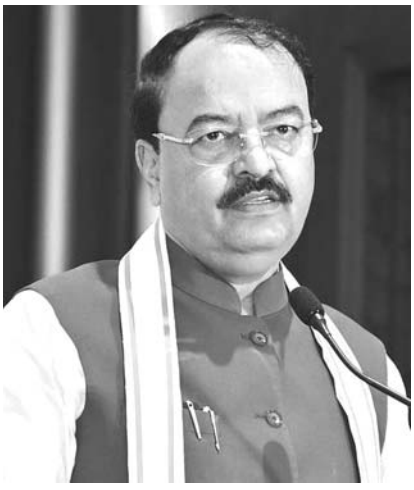

आधी आबादी ने सपा को उखाड़ फेंका। 2024 में कुछ सीटें ज्यादा जीतने का श्रेय धोखे को दिया और कहा कि 2027 में सपा का पूरा सफाया होगा। मौर्य ने आगे कहा कि कोई अपना सुहाग संतान या राखी खतरे में नहीं डालेगा। सपा के पास गुंडे, माफिया, अपराधी और भ्रष्टाचारियों की पूरी फौज है। इसलिए सपा उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा है। दूसरे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने और तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा का हाल वही है जो सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उनके शासन में बहन बेटियां सहमी हुई थीं और नारा लगता था देख सपाई बिटिया घबराई। बहू बेटियों की आबरू लूटी जाती थी और निकलना दूभर था। वे मुंबई से डांस करने वालियां बुलाते थे और अब महिला सम्मान की बात करते हैं। पाठक ने कहा कि प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी।

यह विवाद यूपी की राजनीति को और तेज कर रहा है। महिला वोट बैंक हमेशा निर्णायक रहा है लेकिन सिर्फ आर्थिक वादा काफी नहीं होता। उनके प्रति नेताओं का व्यवहार भी अहम होता है। सपा को अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलने के लिए और मेहनत करनी होगी। वहीं भाजपा अपनी कानून व्यवस्था और विकास की कहानी को और मजबूत करके पेश कर रही है। अखिलेश की यह योजना अगर लागू होती है तो लाखों गरीब महिलाओं को सीधा फायदा पहुंचेगा। लेकिन बजट का सवाल भी उठेगा। यूपी में करोड़ों महिलाएं हैं और गरीब परिवारों को टारगेट करने पर भी खर्च बड़ा होगा। फिर भी राजनीतिक तौर पर यह दांव सपा को नया जोश दे सकता है। अखिलेश यादव ने कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगे भी बेहतर योजनाएं लाई जाएंगी। हर बच्ची युवती और नारी को सामाजिक आर्थिक रूप से सम्मान देने के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाई जाएगी। उन्होंने सपा के संकल्प को दोहराया कि प्रदेश की संपूर्ण उन्नति तभी संभव है जब महिलाएं मजबूत हों। इस बीच ओम प्रकाश राजभर जैसे सहयोगी दलों ने भी कटाक्ष किया है कि 'ना नौ मन गेहूं होई ना राधा नाचेगी'। लेकिन सपा का फोकस साफ है। वह महिला वोट को जोड़कर 2027 में वापसी का सपना देख रही है।

अब सवाल यह है कि यह वादा जमीनी स्तर पर कितना असरदार साबित होगा। महिलाएं न सिर्फ आर्थिक मदद चाहती हैं बल्कि सुरक्षा सम्मान और बेटियों की बेहतर शिक्षा भी चाहती हैं। सपा ने इन सबको जोड़ने की कोशिश की है। भाजपा की ओर से भी महिलाओं के लिए योजनाएं जारी हैं लेकिन सपा का यह सीधा नकद हस्तांतरण वाला मॉडल नया है। बिहार में कामयाब रहा तो यूपी में भी असर दिख सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा हमेशा भारी पड़ता है। 2017 में यही मुद्दा सपा की हार का बड़ा कारण बना था। अब 2027 में दोनों पार्टियां इस मोर्चे पर आमने सामने हैं। कार्यक्रम में सम्मानित महिलाओं में खेल शिक्षा चिकित्सा पर्यावरण और किसान क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं शामिल थीं। यह दिखाता है कि सपा हर क्षेत्र की महिलाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश ने कहा कि अगर सत्ता आई तो पहले से बेहतर काम करेंगे। उनकी पार्टी का दावा है कि महिलाएं अब बदलाव चाहती हैं और वोट के जरिए वह बदलाव लाएंगी। दूसरी तरफ भाजपा का तर्क है कि सपा का राजनीतिक सूर्य अस्त हो चुका है और 2047 तक भी उम्मीद नहीं। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश की सियासत अब पूरी तरह महिला केंद्रित हो गई है। अखिलेश यादव का यह दांव 2027 के चुनावी मैदान को और रोचक बना रहा है। देखना होगा कि महिला वोट बैंक किसके पक्ष में झुकता है। क्या 40 हजार रुपये का वादा पुरानी यादों को मिटा पाएगा या कानून व्यवस्था की बात फिर भारी पड़ेगी। फिलहाल राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है और दोनों पक्ष अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। यूपी की महिलाएं इस बार तय करेंगी कि किसकी बात पर भरोसा किया जाए।●

● **शशि रंजन सिंह/राजीव कुमार शुक्ला**

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कुछ मासूम बच्चों की मौत हुई। उनके शरीर में जहर था–डाइइथिलीन ग्लाइकोल (DEG)। वही जहर जो 2022 में गाम्बिया में 70 से अधिक बच्चों की जान ले चुका था। दोषी थी एक कफ सिरप 'COLDRIF' और उत्पाद बनाने वाली कंपनी का CDSCO केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था ने पिछले दस वर्षों में एक भी निरीक्षण नहीं किया था। जबकि कानून (GSR 1337, दिनांक 27/10/2017) के तहत संयुक्त निरीक्षण अनिवार्य था। World Health Organization ने 9 अक्टूबर 2025 को एक मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जारी किया, जिसमें तीन भारतीय दवाओं-COLDRIF, Respifresh TR और ReLife को विषाक्त घोषित किया गया। WHO की रिपोर्ट के अनुसार COLDRIF में DEG की मात्रा 48.6% तक पाई गई, जबकि अनुमेय सीमा मात्र 0.1% है। कम-से-कम 17 बच्चों की मौत इस दूषित सिरप से जुड़ी बताई गई। यह एक उत्पाद-विफलता नहीं थी। यह उस नियामकीय तंत्र की घोर असफलता थी, जिसका काम ही इसे रोकना था।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक देश है–मात्रा की दृष्टि से। देश में लाखों MSME फार्मा इकाइयाँ हैं जो न केवल करोड़ों भारतीयों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराती हैं, बल्कि अरबों डॉलर का निर्यात भी करती हैं। इस विशाल उद्योग का नियामक संरक्षक है CDSCO (Central Drugs Standard Control Organisation) और उसका शीर्ष पद है DCGI। यह कोई साधारण नौकरशाही पद नहीं है। यह Drugs and Cosmetics Act, 1940 की धारा 21 के तहत स्थापित एक statutory regulatory post है जो 140 करोड़ भारतीयों के स्वास्थ्य की रक्षा करती है। नई दवा अनुमोदन, रिकॉल आदेश, GMP निरीक्षण, आयात-निर्यात मंजूरी; सब कुछ इसी पद के इर्द-गिर्द केंद्रित है। इस असाधारण शक्ति का अर्थ है कि इस पद पर बैठे व्यक्ति की निष्पक्षता, योग्यता और ईमानदारी पर पूरे देश का स्वास्थ्य निर्भर करता है।

वर्ष 2022 से इस पद पर आसीन डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी को लेकर एक अभूतपूर्व विवाद उत्पन्न हुआ है जो आरोपों, न्यायिक याचिकाओं, संसदीय रिपोर्टों और व्हिसलब्लोअर बयानों के रूप में सामने आया है।

CDSCO की आधिकारिक Risk-Based Inspection (RBI) नीति एक तार्किक और आधुनिक सिद्धांत पर आधारित है। निरीक्षण उन्हीं स्थानों पर केंद्रित हों जहाँ जोखिम अधिक हो। सिद्धांत सही है, किंतु प्रश्न यह है कि क्या इसका अनुप्रयोग निष्पक्ष रहा? 20 से अधिक MSME प्रतिनिधि संगठनों ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि उच्च विनिर्माण मानकों और अनुपालन समय सीमाओं के "अचानक" क्रियान्वयन से 4,000 से 5,000 ईकाइयाँ बंद हो सकती हैं। उनका आरोप है कि RBI निरीक्षण "चयनात्मक" ढंग से MSME पर केंद्रित किए जा रहे हैं, जबकि बड़ी बहुराष्ट्रीय

कंपनियों, जिनके उत्पाद सरकारी प्रयोगशालाओं ने NSQ (Not of Standard Quality) घोषित किए, को बख्शा जाता रहा। व्हिसलब्लोअर शिकायतपत्रों में तर्क दिया गया है कि "जिन बड़ी कंपनियों के उत्पादों पर अमेरिकी FDA और यूरोपीय एजेंसियों ने Import Alert लगाया है, उन पर CDSCO कोई कार्रवाई नहीं करती। यही मानदंड MSME पर लागू करें तो बड़ी कंपनियाँ भी बंद हो जाएंगी।" संसदीय समिति की रिपोर्ट संख्या 163 (मार्च 2025) ने किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से दोषी ठहराए बिना CDSCO की लाइसेंसिंग प्रक्रिया में विलंब, अपारदर्शिता और मनमाने निर्णयों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। समिति ने स्पष्ट कहा कि CDSCO की "Licence Raj" जैसी कठोर और देरी से भरी प्रक्रिया के कारण चिकित्सा उपकरण निर्माता वियतनाम और मलेशिया का रुख कर रहे हैं।

❖ **IGI एयरपोर्ट और पनवेल : बंदरगाहों पर कथित भ्रष्टाचार :-** 2 अप्रैल 2024 को मुम्बई के पनवेल स्थित CDSCO कार्यालय में CBI, विजिलेंस और DG विजिलेंस ने संयुक्त छापा मारा। भारी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पकड़ी गई और CDSCO अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। यह ठोस और सत्यापित तथ्य है। इसके बाद एक शिकायतकर्ता 'मनीष कुमार' ने DCGI को ही पत्र लिखकर बताया कि IGI एयरपोर्ट कार्यालय में भ्रष्टाचार का स्तर पनवेल से "सौ गुना अधिक" है। उनके अनुसार ADC श्री धरमवीर सिंह और Drug Inspector श्री दिनेश कुमार जानबूझकर शिपमेंट में देरी करते हैं, डेमरेज चार्जेज बढ़वाते हैं, नियम से अधिक सैंपलिंग करते हैं और आयातकों को रिश्वत देने पर मजबूर करते हैं। शिकायत में एक अत्यंत गंभीर आरोप यह भी है कि एक अधिकारी स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा का नाम लेकर पैसे माँगते थे। उल्लेखनीय है कि यह शिकायत अज्ञात नहीं, नामधारी व्यक्ति की है और DCGI को ही संबोधित है, जो संस्थागत समस्या की गहराई को उजागर

ice::gate
e COMMERCE Portal Central Board of Excise and Customs
Last Updated : Sep 5, 2025
Home > Tracking At ICES > Bill of Entry
BILL OF ENTRY

LOCATION	BILL OF ENTRY NO	BILL OF ENTRY DATE
DELHI AIR CARGO ACC (INDEL4)	3827136	11/08/2025

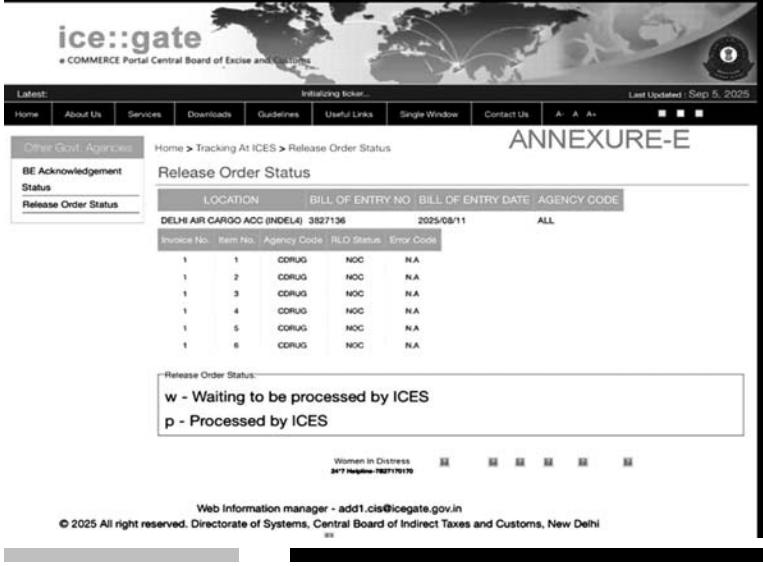

BE Details

IEC	TOT VAL	TYP	CHA Number	FIRST CHECK	PRIOR BE	SEC48
AEKPB5589D	405856.25	H	AACFA7048JCH001	N	N	N

APPRAISING GROUP	TOTAL ASSESSABLE VALUE	TOTAL PACKAGE	GROSS WEIGHT (Kg)	TOTAL DUTY (INR)	FINE PENALTY (INR)	WBE No.
28	409956	N.A.	N.A.	99702	N.A.	N.A.

Current Status

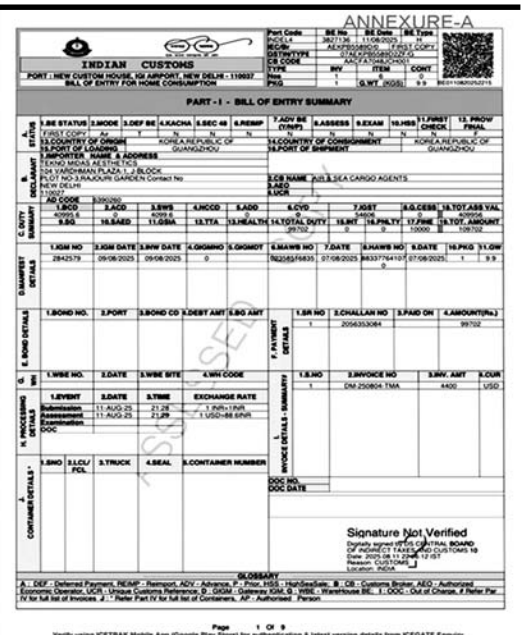

APPRAISEMENT	CURRENT QUEUE	NO OF QUERY RAISED	NO OF QUERY REPLIED	REPLY DATE	REPLY STATUS	APPR DATE	ASSESS DATE	PAYMENT DATE	EXAM DATE	OOC DATE
Processed	N.A.	1	1	2025-8-30 11.11.13.0	YES	2025-8-11 21.29.36.0	2025-8-11 21.29.36.0	2025-8-30 13.28.1.0	N.A.	2025-8-30 13.33.59.0

Payment Details

CHALLAN No.	DUTY AMOUNT (INR)	FINE AMOUNT (INR)	INTEREST AMOUNT (INR)	PENAL AMOUNT (INR)	TOTAL DUTY (INR)	DUTY PAID (INR)	MODE OF PAYMENT
2056353084	99702	10000	779	0	110481.0	110481.0	EPAYMENT

Other Govt. Agencies Status
Document status is available at CDRUG. Item wise details are available in Other Government Agencies tab.
eDocument Validity
BE Amendment Details
Web Information manager - add1.cis@icegate.gov.in
© 2025 All right reserved. Directorate of Systems, Central Board of Indirect Taxes and Customs, New Delhi

ANNEXURE-A
INDIAN CUSTOMS
PORT : NEW CUSTOM HOUSE, IGI AIRPORT, NEW DELHI - 110037
BILL OF ENTRY FOR HOME CONSUMPTION
PART - I - BILL OF ENTRY SUMMARY
TEKNO MIDAS AESTHETICS
KOREA,REPUBLIC OF
AIR & SEA CARGO AGENTS
Signature Not Verified
Page 1 of 9

ice::gate
e COMMERCE Portal Central Board of Excise and Customs
Last Updated : Sep 5, 2025
ANNEXURE-E
Home > Tracking At ICES > Release Order Status
Release Order Status

LOCATION	BILL OF ENTRY NO	BILL OF ENTRY DATE	AGENCY CODE
DELHI AIR CARGO ACC (INDEL4)	3827136	2025/08/11	ALL

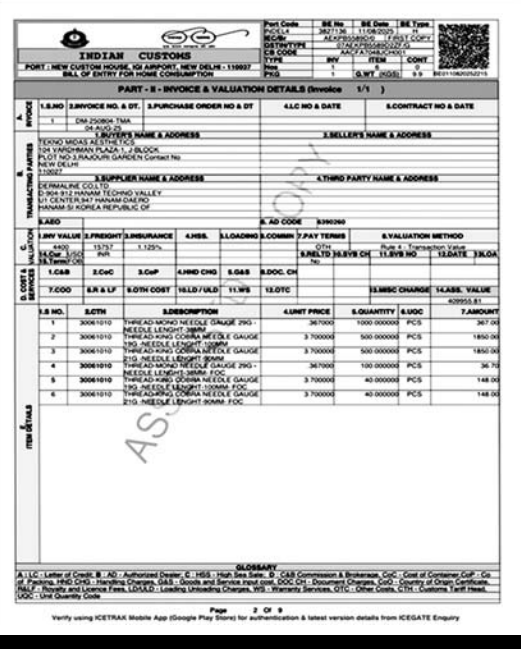

Invoice No.	Item No.	Agency Code	RLO Status	Error Code
1	1	CDRUG	NOC	N.A.
1	2	CDRUG	NOC	N.A.
1	3	CDRUG	NOC	N.A.
1	4	CDRUG	NOC	N.A.
1	5	CDRUG	NOC	N.A.
1	6	CDRUG	NOC	N.A.

Release Order Status:
w - Waiting to be processed by ICES
p - Processed by ICES
Web Information manager - add1.cis@icegate.gov.in
© 2025 All right reserved. Directorate of Systems, Central Board of Indirect Taxes and Customs, New Delhi

INDIAN CUSTOMS
PORT : NEW CUSTOM HOUSE, IGI AIRPORT, NEW DELHI - 110037
BILL OF ENTRY FOR HOME CONSUMPTION
PART - II - INVOICE & VALUATION DETAILS (Invoice 1/1)
TEKNO MIDAS AESTHETICS
DERMALINE CO.,LTD
Page 2 of 9

ITEM NO.32 COURT NO.1 SECTION PIL-W

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Writ Petition(s)(Civil) No(s).106/2026

KAUSHLESH KUMAR Petitioner(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. Respondent(s)

I.A. Nos.80790/2026 - APPLICATION FOR INTERVENTION/IMPLEADMENT,
I.A. Nos.80877/2026 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS

Date : 16-03-2026 This petition was called on for hearing today.

CORAM : HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE JOYMALYA BAGCHI

For Petitioner(s) :Mr. Sahil Raveen, AOR
Mr. Hruday Bajentri, Adv.

For Respondent(s) :

For applicant : Mr. S.S. Khanduza, Adv.
Dr. Pratyush Nandan, Adv.
Dr. Prabhat Kumar, Adv.
Ms. Maheravish Rein, Adv.
Mr. Aldanish Rein, AOR

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

1. Applications (I.A. Nos.80790/2026 & 80877/2026) for intervention/impleadment and appropriate orders/directions are dismissed.

2. Counter affidavit, if any, be filed within three weeks. Rejoinder, if any, be filed two weeks' thereafter.

3. Post the matter on 27.04.2026.

Validity unknown

UN BISHT) (PREETHI T.C.)
T. REGISTRAR-cum-PS ASSISTANT REGISTRAR

भारतीय भेषज संहिता आयोग
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
सैक्टर - २३, राज नगर,
गाज़ियाबाद - २०१ ००२, उत्तर प्रदेश, भारत

IPC

INDIAN PHARMACOPOEIA COMMISSION
Ministry of Health & Family Welfare, Government of India
Sector - 23, Raj Nagar
Ghaziabad-201 002 (U.P.), INDIA

डा. वी. कलईसेलवण
सचिव-सह-वैज्ञानिक निदेशक

Dr. V. Kalaiselvan
Secretary-cum-Scientific Director

F. No. T.11015/01/2020-AR&D Date: October 10, 2025

Subject: Amendment List 09 to IP 2022

The 9th Edition of Indian Pharmacopoeia (IP) 2022 has become effective from 1st December, 2022. Based on the scientific inputs, some monographs of the IP 2022 need amendments for their effective implementation. Accordingly, Amendment List 09 to IP 2022 is being issued containing such amendments and this shall become official with immediate effect.

All concerned are requested to bring it to the notice of all authorities under their control for compliance with the IP 2022.

(Dr. V. Kalaiselvan)

Encl. Amendment List 09 to IP 2022

To,
1. The Drugs Controller General (India)
2. All State Drug Controllers
3. CDSCO Zonal Offices
4. Members of the Scientific Body of the IPC
5. Directors of the Drugs Testing Laboratories
6. IDMA/OPPI/BDMA/FOPE/FSSAI/Small Scale Industry Associations

INDIAN PHARMACOPOEIA (IP) Official Book of Drug Standards in India | IP REFERENCE SUBSTANCES (IPRS) AND IMPURITIES Official Physical Standards for Assessing the Quality of Drugs | NATIONAL FORMULARY OF INDIA (NFI) Reference Book to Promote Rational Use of Generic Medicines | PHARMACOVIGILANCE PROGRAMME OF INDIA (PvPI) WHO Collaborating Centre for Pharmacovigilance in Public Health Programmes and Regulatory Services

Tel No: +91-120-2783392, 2783400, 2800401 E-mail: lab.ipc@gov.in Website: www.ipc.gov.in

AMENDMENT LIST-09 TO IP 2022

Oral Liquids. Page 1335

Tests

Insert before **Uniformity of content**

Diethylene glycol and Ethylene glycol. Determine by gas chromatography (2.4.13).

Not more than 0.10 per cent, each of, Diethylene glycol and Ethylene glycol.

करती है।

❖ **IPC गाजियाबाद : भर्ती घोटाले का आरोप :-** फरवरी 2025 में स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव सुश्री पुण्य सलिला श्रीवास्तव को एक वरिष्ठ CDSCO अधिकारी खुसी लाल यादव ने विस्तृत पत्र लिखा। इसकी प्रतियाँ प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, CVC, CBI और DRI को भी भेजी गई। इस पत्र में गंभीर आरोप लगाए गए:-

डॉ. रघुवंशी ने फरवरी 2022 में Indian Pharmacopoeia Commission (IPC), गाजियाबाद का पद छोड़ा, किंतु अगले 22 महीनों तक उसी पद का अतिरिक्त प्रभार बनाए रखा। इस दौरान, आरोप है कि UPSC और DOPT नियमों की अनदेखी करते हुए मंत्रालय अधिकारियों के सगे-संबंधियों को IPC में नियुक्त किया गया।

डॉ. पूनम रघुवंशी

❖ **hatsApp वार्तालाप : भ्रष्टाचार का कथित जीता-जागता सबूत :-** दस्तावेजों में CDSCO की एक DDC 'स्वाति मैम' और एक दवा कंपनी प्रतिनिधि के बीच का WhatsApp वार्तालाप भी शामिल है। इसमें दवा अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी के बदले "एक छोटा जेस्चर" माँगने और एक जूनियर अधिकारी से संपर्क करने का निर्देश देने जैसे संवाद दर्ज हैं। यह वार्तालाप यदि प्रामाणिक है तो संस्थागत स्तर पर रिश्वत की माँग का स्पष्ट संकेत देता है।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि डॉ. रघुवंशी की पत्नी डॉ. पूनम रघुवंशी 'ipEssentia' नाम की एक IPR कंसल्टिंग फर्म चलाती हैं और फार्मा कंपनियाँ इस फर्म को भारी फीस देकर CDSCO में अपनी फाइलें तेजी से क्लियर करवाती हैं। यह गंभीर आरोप है, किंतु इसका स्वतंत्र सत्यापन अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं हुआ।

❖ **WHO का NRA रेटिंग विवाद :-** डॉ. रघुवंशी ने दावा किया कि उनके प्रयासों से WHO ने CDSCO को Maturity Level 3 की Functional NRA का दर्जा दिया, किंतु खुसी लाल यादव के पत्र में दावा किया गया कि 19 सितम्बर 2024 की प्री-एग्जिट मीटिंग में WHO ने CDSCO को ML-2 दिया था और उसे ML-3 में बदलवाने के लिए असाधारण प्रयास हुए।

❖ **यह तथ्य ध्यान देने योग्य है :-** CDSCO वर्ष 2000 से WHO की Functional NRA सूची में है। 2004, 2007, 2009, 2012 और 2017 के ऑडिट में उसका प्रदर्शन संतोषजनक रहा। यदि 2024 का मूल्यांकन वास्तव में ML-2 था, तो यह स्वयं में एक गंभीर संस्थागत गिरावट का संकेत है।

❖ **भाग चार : संविदा पुनर्नियुक्ति, कानूनी विवाद सर्वोच्च न्यायालय तक :-** इस पूरे विवाद का सबसे ठोस और न्यायिक रूप से

F. No. A.11020/04/2024-DR-Part(I)
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
Department of Health and Family Welfare
(Drugs Regulation Section)

Nirman Bhawan, New Delhi-110011
Dated 28th February, 2025

OFFICE ORDER

In pursuance of the approval of Appointments Committee of the Cabinet as contained in their communication no. 5/3/2023-EO(SM-II) dated 20.02.2025, Dr. Rajeev Singh Raghuvanshi is re-employed as the Drugs Controller (India), Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) on contract basis for a period of one year w.e.f. 01.03.2025, i.e. beyond his attaining the age of superannuation, or till the appointment of regular incumbent to the post, or until further orders, whichever is the earliest, by keeping the Recruitment Rules of the post in abeyance.

28/2/25
(Dr. Kiran Kumar Karlapu)
Director
Tel No.:011-23062928

Copy to:

1. Dr Rajeev Singh Raghuvanshi, Drugs Controller (India)
2. Sh. Ramesh Chandra Jha, Under Secretary (EO-SM.II) with reference to communication no. 5/3/2023-EO(SM-II) dated 20.02.2025
3. Pay and Accounts Officer, Ministry of Health and Family Welfare, Nirman Bhavan, New Delhi.
4. Pay and Accounts Officer, Dte GHS, Nirman Bhavan, New Delhi.
5. PS to Hon'ble HFM/MoS(AP)/MoS(PJ)
6. PSO to Secretary (HFW)/DGHS/PPS to Adviser(Cost)
7. Director (Admin.) CDSCO/Director(Admin-Hqrs) DGHS/Director(A&V)/A&V Section
8. O/o Secretary-cum-Scientific Director, Indian Pharmacopoeia Commission
9. Guard File

Immediate

No.5/3/2023-EO(SM-II)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training
Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet
*****

Kartavya Bhavan-3, New Delhi
28.02.2026

The Appointments Committee of the Cabinet has approved the proposal of the Department of Health and Family Welfare for the re-employment of Dr. Rajeev Singh Raghuvanshi as Drugs Controller (India), Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) on a contract basis for a further period of one year w.e.f. 01.03.2026, or till the appointment of a regular incumbent to the post, or until further orders, whichever is the earliest, by keeping the Recruitment Rules (RRs) for the post in abeyance.

28/02/26
(Subir Kumar)
Under Secretary (EO-SM.II)
Tel: 2401 0487

Ministry of Health and Family Welfare,
(Ms. Punya Salila Srivastava, Secretary),
Kartavya Bhavan-1, New Delhi.

Copy forwarded for information to:

1. Prime Minister's Office (Ms. Manmeet Kaur, Director).
2. Cabinet Secretariat (Ms. Kavita Singh, Joint Secretary)
3. Guard File.

28/02/26
(Subir Kumar)
Under Secretary (EO-SM.II)
Tel: 2401 0487

सत्यापित पहलू है DCGI की संविदा पुनर्नियुक्ति का मामला। डॉ. रघुवंशी 28 फरवरी 2025 को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए। कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने उन्हें 1 मार्च 2025 से एक वर्ष के संविदा आधार पर पुनर्नियुक्त किया। फिर 28 फरवरी 2026 को यह अवधि एक और वर्ष के लिए बढ़ा दी गई।

इसके समानांतर, अगस्त 2024 में DCGI पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। 18 आवेदन आए, जिनमें डॉ. V.G. Somani और Dr. Jay Prakash जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। 21 अक्टूबर 2025 को इस विज्ञापन को "प्रशासनिक कारणों" से वापस ले लिया गया। 6 फरवरी 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने Writ Petition (Civil) No-106/2026 (Kaushlesh Kumar cuke Union of India) में नोटिस जारी किया। माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ ने यह मामला 16 मार्च 2026 की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

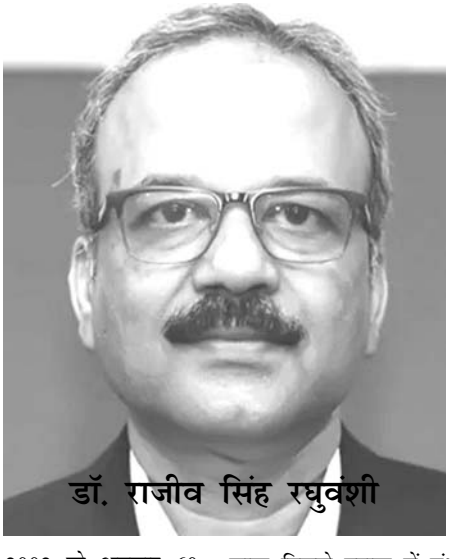
डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी

❖ **याचिकाकर्ता के प्रमुख तर्क हैं :-**

☞ DoPT के दिशानिर्देश (OM No-26012/6/2002-Estt(A), दिनांक 9 दिसम्बर 2002 के अनुसार 60 वर्ष की आयु के बाद किसी को भी केंद्र सरकार में संविदा आधार पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि 18 फरवरी 2003 को लोकसभा में (Unstarred Question 58) सरकार ने स्वयं कहा था कि 60 के बाद पुनर्नियोजन का कोई प्रावधान नहीं।

☞ DCGI एक वैधानिक नियामक पद है, जो Drugs and Cosmetics Act, 1940 की धारा 21 के तहत संप्रभु शक्तियाँ निरीक्षण, सैंपलिंग, अभियोजन धारण करता है। संविदाकर्मी को कानूनी रूप से यह अधिकार देने की वैधानिकता संदिग्ध है।

☞ जब पद के लिए विज्ञापन था और योग्य उम्मीदवार उपलब्ध थे, तो उस विज्ञापन को वापस लेकर उसी व्यक्ति को पुनर्नियुक्त करना मनमाना कार्य है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करना, एक महत्वपूर्ण संकेत है कि न्यायालय इस याचिका को विचारणीय मानता है। यहाँ एक तथ्य जोड़ना आवश्यक है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने 25 नवम्बर 2025 को अपने फैसले में पहले के विस्तार आदेश को वैध माना था, यह कहते हुए कि भर्ती नियमों की समीक्षा चल रही थी और पद अत्यंत महत्वपूर्ण था। किंतु न्यायिक वैधता और नैतिक-राजनीतिक वैधता दो अलग प्रश्न हैं। अदालत ने मुख्यतः प्रक्रियागत पहलू देखा; उन व्यापक संस्थागत सवालों पर अंतिम मुहर नहीं लगाई।

भारतीय फार्मा उद्योग की अंतरराष्ट्रीय साख पिछले दशक में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई है। 2022 में गाम्बिया और उजबेकिस्तान में भारतीय कफ सिरप से बच्चों की मौतों ने GMP अनुपालन की जांच की अनिवार्यता सिद्ध की। Risk-Based Inspections इसी दिशा में एक कदम था। RBI की अवधारणा 2016 में ही शुरू हुई थी और MSME ईकाइयों में गुणवत्ता की समस्याएं वास्तविक

Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
(Department of Health and Family Welfare)
Nirman Bhawan, New Delhi-110011

Dated 09th October, 2024

Advertisement No.
A-12025/01/2024-DR

CIRCULAR

In continuation of the advertisement which appeared in the Employment News dated 10 - 16 August, 2024, it is brought to the notice of all concerned that the last date for receipt of applications from eligible candidates for appointment to the post of Drugs Controller (India) Group 'A' Pay Level 14 in Central Drugs Standard and Control Organisation, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, by deputation (including short term contract) has been extended.

2. The last date of submission of application, as per the earlier advertisement, was within 60 days from date of its publication in Employment News dated 10 - 16 August, 2024 i.e. 09th October 2024. The last date has been extended and the candidates may apply and send their applications complete in all respects, in accordance with the procedure specified in earlier advertisement, so as to reach the undersigned [Bikash R Mahato, Under Secretary (Drugs Regulation), Ministry of Health & Family Welfare, Room No.434, C Wing, Nirman Bhawan, New Delhi-110011] by 23rd November, 2024.

3. Those who have already applied for this post in response to the earlier advertisement need not to apply again.

(Bikash R. Mahato)
Under Secretary to the Government of India

हैं। Viatris के बोर्ड सदस्य राजीव मलिक ने रघुवंशी को "एक सीधे और पारदर्शी पेशेवर" बताया है। कुछ उद्योग विशेषज्ञ भी मानते हैं कि Schedule M अनुपालन अपरिहार्य है। हर निरीक्षण कार्रवाई भ्रष्टाचार नहीं होती। किंतु इन तर्कों के साथ एक विरोधाभास यह भी है कि यदि RBI का उद्देश्य वास्तव में गुणवत्ता सुधार था, तो छिंदवाड़ा में उस कंपनी का 10 वर्षों में एक भी निरीक्षण क्यों नहीं हुआ, जिसके सिरप ने बच्चों की जान ली? और यदि RBI ने MSME को असमान रूप से निशाना बनाया, तो इसका डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं है?

कुछ शिकायत पत्रों में एक और आरोप है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को छूता है। यह आरोप है कि चीन से सस्ती और अवैध Active Pharmaceutical Ingredients (API) CDSCO के Port Offices के माध्यम से Dual Use Licenses के दुरुपयोग से भारत में आ रही हैं। यह आरोप गंभीर है, पर इसके लिए स्वतंत्र खुफिया और सांख्यिकीय सत्यापन आवश्यक है, जो इन दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं।

संदर्भ में यह जरूर महत्वपूर्ण है, भारत की API आपूर्ति श्रृंखला में चीन पर अत्यधिक निर्भरता एक सुस्थापित तथ्य है। COVID-19 महामारी ने यह कमजोरी उजागर की थी। यदि CDSCO का बंदरगाह तंत्र कमजोर हो, तो यह न केवल भ्रष्टाचार, बल्कि दवा-संप्रभुता का प्रश्न

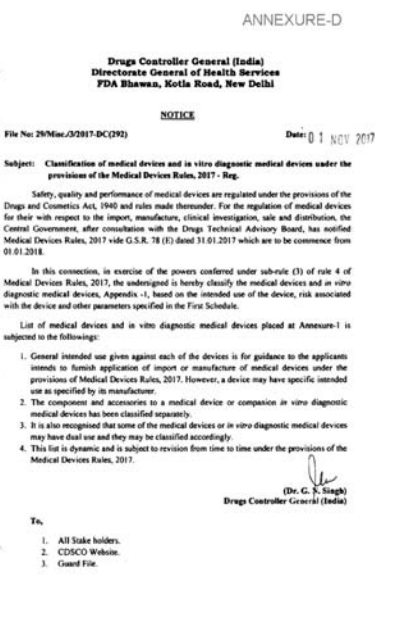

MOST SERIOUS COMPLAINT (GRAVEST GRIEVANCE)

DATED: 26.09.2025

To,
Hon'ble Shri Jagat Prakash Nadda Ji
Union Health Minister of India,
Room No. 342, 3rd Floor, Nirman Bhavan, New Delhi-110001

Subject: Complaint about unlawful clearance (smuggling) of the illegal/contraband imported unregulated medical devices (Class C -High Risk Medical Devices) consignments by the Corrupted officers named Sh. Dharamvir Singh, Assistant Drug's Controller (ADC) and Sh. Dinesh Kumar, Drug's Inspector (DI) posted at ADC Office, CDSCO, IGI Air Cargo, New Delhi-reg.

Respected Sir,

Despite having sent the said complaint vide letter no. F.No. Complaint/ACI/CVO/2025/01 dated 08.09.2025 along with several reminders to the **CVO (Ms. Ankita Mishra Bundela (IAS), Joint Secretary, Chief Vigilance Officer)** through email dated 08.09.2025, however no action has been taken yet. Hence therefore, I am compelled to bring to your kind attention a grave matter of corruption and misconduct involving unlawful clearance **(smuggling)** of the illegal/contraband imported unregulated medical devices (Class C -High Risk Medical Devices) consignments by the Corrupted officers of CDSCO i.e. **Sh. Dharamvir Singh, Assistant Drug's Controller (ADC) and Sh. Dinesh Kumar, Drug's Inspector (DI)** posted at ADC Office, CDSCO, IGI Air Cargo, New Delhi-110037.

It has come to my knowledge that on multiple occasions, the above said officers have *released consignments without the mandatory licenses required under Drugs & Cosmetics Act and Medical Devices Rules 2017 there under and sometimes fabricating the documents illegally for releasing the favoured consignments by taking heavy bribery amount.* In this context, respectfully it is to inform you that one such consignment without having the MD-15 (mandatory license for importing medical devices into India) has been imported by the firm named **M/s Tekno Midas Aesthetics**, Rajouri Garden, New Delhi-110027 and same has been released by the above said corrupted officers of CDSCO..

In this regard, please find the details (in tabular format) of unlawful import clearance **(smuggling)** of the illegal/contraband unregulated medical device consignment:-

S.N.	Bill of Entry No. & Date	Name of Product/Medical Device being imported/smuggled	Quantity being imported/smuggled
1.	**3827136 Dated 11.08.2025** (Copy enclosed as **Annexure-A**)	Sterilized absorbable PDO (Polydioxanone) Suture with Needles (Brand Name – DERMA V LINE Lifting Threads)	**2180 Pieces**

MOST SERIOUS COMPLAINT (GRAVEST GRIEVANCE)

Labels of Product/Medical Device	Copy of Labels of Product/Medical Device being imported is enclosed as **Annexure-B** for your ready reference.
Name of Importer and Address	**Tekno Midas Aesthetics**, Vardhman Plaza-1, J-Block Commercial Centre, Shop No. 104, First Floor, Plot No. 3, West Delhi, Rajouri Garden, New Delhi-110027
Country of Origin	Republic of Korea (Copy of Certificate of Origin enclosed as **Annexure-C** for your ready reference)
Name of Supplier/Manufacturer	**Dermaline Co. Ltd.**, D-905,906,914,915, Hanam Techno Valley, U1 Centre, 947, Hanam Daero, Hanam-SI, Gyeonggi-do, 12982, Republic of Korea
Regulated/Classification of Medical Device as per MDR-2017	• Regulated and Classified as **Class C (High Risk Medical Devices)** • Mentioned on Item no. 342 on notice/notification issued by the Drugs Controller General (India) vide File No: 29/Misc./3/2017-DC (292) dated 01.11.2017 regarding the classification of medical devices under the provisions of Medical Devices Rules, 2017 (Copy of same is enclosed as **Annexure-D** for your ready reference)
Whether, firm have mandatory requirement i.e. MD-15 (Import License)	**NO, Importer do not have MD-15.**
Date of NOC issued by ADC on ICEGATE & Out of Charge Date	**Shipment NOC Date** – 28 August 2025 **Shipment Out of Charge Date** – 01 September 2025 **(Copy enclosed as Annexure-E)**
Total Revenue Losses to the Exchequer/Country	3000 USD (Government Fee for One Site Registration) + 1500 USD (Government Fee for One Medical Device Unit) = 4500 USD **(Approx 04 Lakhs INR)**

Note : It has been came to the knowledge that said corrupted officials have taken undertaking for Research Use for the release of above said goods after taking huge amount of bribe – Therefore, it is to clarify that said medical device attracts the definition as per S.O.648(E) dated 11.02.2020 and as per the FAQs (Doc No.: CDSCO/FAQ/MD/01/2024) released by the CDSCO, it is clearly mentioned on point no. 58 that the devices which attracts the definition as per the S.O.648(E) dated 11.02.2020 are regulated under Medical Devices Rules 2017 and a license is required/mandatory under the said rule. Hence therefore, said corrupted officers also have no option to release said goods based on taking undertaking of Research Use from the said importer.

MOST SERIOUS COMPLAINT (GRAVEST GRIEVANCE)

Such actions not only constitute a clear violation of the law/medical devices rules but also **causing substantial revenue losses to the government of India by evading the statutory fees payable for obtaining licenses** and poses a grave threat to the public health and safety and endangering the lives of 1.4 billion citizens of India by allowing or smuggling the unregulated medical devices (Class C -High Risk Medical Devices) into the country. They are not only responsible for result in revenue losses to the exchequer but also undermine the integrity of the healthcare system of India.

Corrupt officers-whether in law enforcement, military, or government institutions-can indeed be considered a **NATIONAL THREAT**.

Hence, therefore, keeping in view of above you are requested to take strict disciplinary action i.e. **Immediate Suspension & High-Level Enquiry (at CBI/CVO, MoH&FW Level) of Sh. Dharamvir Singh, Assistant Drug's Controller (ADC) and Sh. Dinesh Kumar, Drug's Inspector (DI), ADC Office, IGI Air Cargo, New Delhi-110037.**

Thank you for your kind attention. I am very much confident that this afore mentioned matter will receive your immediate consideration in the interest of public at large.

Yours Sincerely,

Pankaj Gupta,
RHB Colony, Near Central Market,
Bhiwadi, Tehsil-Tijara, Dist. Alwar, Rajasthan-301019

बन जाता है।

इस पूरे विवाद की जड़ में कुछ ऐसी संरचनागत समस्याएं हैं जो किसी एक अधिकारी की नियुक्ति या हटाने से हल नहीं होंगी। ये समस्याएं इस प्रकार हैं :-

☞ DCGI पद में असाधारण रूप से केंद्रीकृत शक्ति है। जब एक ही पद पर इतना कुछ निर्भर हो, तो मनमाने निर्णयों और भ्रष्टाचार का अवसर स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। संसदीय समिति ने यही चिंता व्यक्त की है।

☞ अपारदर्शी निरीक्षण और लाइसेंसिंग प्रणाली। CDSCO की अपनी RBI guidance में स्पष्ट criteria हैं-compliance history, NSQ history, product risk, किंतु इन criteria के अनुप्रयोग का सार्वजनिक ऑडिटेबल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

☞ व्हिसलब्लोअर सुरक्षा का अभाव। इस विवाद में अधिकांश गंभीर आरोप अज्ञात स्रोतों से आए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि सूचना देने वालों को अपनी पहचान उजागर करने में डर लगता है।

☞ DCGI पद की नियुक्ति प्रक्रिया में अस्पष्टता। 2022 से विज्ञापित पद, 18 आवेदन, अक्टूबर 2025 में विज्ञापन वापसी। यह पूरी प्रक्रिया UPSC परामर्श और Recruitment Rules की अनिवार्यता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है, जैसा कि एक शिकायतपत्र में कहा गया, **"जब नियामक की नियुक्ति प्रक्रिया ही अपारदर्शी हो, तो उसके द्वारा उद्योग पर थोपी गई पारदर्शिता की माँग नैतिक रूप से खोखली लगती है।"**

इस संकट का समाधान व्यक्तिगत जवाबदेही और संस्थागत सुधार, दोनों को एक साथ माँगता है। सबसे पहले आवश्यक है कि DCGI पद पर UPSC की उचित प्रक्रिया के माध्यम से एक नियमित, योग्य और स्वतंत्र अधिकारी की नियुक्ति हो। संविदा पुनर्नियुक्ति की व्यवस्था इस महत्वपूर्ण वैधानिक पद की स्वायत्तता को कमजोर करती है। सभी निरीक्षणों, शो-कॉज नोटिस, रिकॉल, NSQ इतिहास और लाइसेंसिंग टाइमलाइन का एक सार्वजनिक डैशबोर्ड बने, ताकि RBI कार्रवाइयों की निष्पक्षता जाँची जा सके। संसदीय समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए। Independent Industry Advisory Board की स्थापना, पूर्ण डिजिटलीकरण, 45 दिनों में conditional approvals, single-query policy AMSME के लिए compliance support और staggered transition की व्यवस्था हो, ताकि गुणवत्ता सुधार का बोझ केवल दंडात्मक न हो। IGI एयरपोर्ट कार्यालय में कथित भ्रष्टाचार, IPC में कथित अवैध भर्तियों और पनवेल के बाद उठे सवालों की CBI या CVC द्वारा निष्पक्ष जांच हो।

डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी अपराधी हैं या नहीं, यह निर्णय न्यायालयों और जांच एजेंसियों का है। यह आलेख उस निर्णय पर नहीं पहुँचता। किंतु जो तथ्य सार्वजनिक अभिलेखों में दर्ज हैं, वे कुछ निश्चित प्रश्न खड़े करते हैं, जिनसे मुँह नहीं फेरा जा सकता। CDSCO में पारदर्शिता और जवाबदेही की भारी कमी है, जो भ्रष्टाचार के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है। MSME फार्मा ईकाइयाँ नियामकीय प्रक्रियाओं से असमान रूप से प्रभावित हो रही हैं। DCGI की संविदा पुनर्नियुक्ति ने इस वैधानिक पद की स्वायत्तता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाया है और सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा, इन सभी विवादों से ऊपर है।

भारत "फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड" कहलाना चाहता है। पर यह

Admin-12011(12)/3/2025-eoffice
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
Department of Health and Family Welfare
(Drugs Regulation Section)
*****

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 17 November,2025

PUBLIC NOTICE

This Ministry is examining a proposal for Amendment in Recruitment Rules for the post of Drugs Controller (India) in Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO), Directorate General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare. In this regard, draft Recruitment Rules have been prepared, a copy of which is attached.

2. Before finalizing the same, comments, if any, are invited from all stakeholders in the matter within a period of thirty days from the date of this notification on the website of the Ministry of Health and Family Welfare. The comments/objections/suggestions received from the stakeholders within the specified period shall be considered by the Ministry as per rules/requirement before finalizing the Recruitment Rules.

3. The comments may be furnished to undersigned Room No.407, 'A' Wing, Nirman Bhawan, New Delhi-110011 or may kindly be sent to **drugsdiv-mohfw@gov.in**.

Enclosure: As above.

(डॉ. किरण कुमार कर्लापु)
(Dr. Kiran Kumar Karlapu)
निदेशक/Director
Tele:- 011-23062928

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB - SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17/11/2025.

G.S.R……- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Drugs Standard Control Organisation [Drugs Controller (India)] (Amendment) Recruitment Rules, 2018 and Central Drugs Standard Control Organisation [Drugs Controller (India)] Recruitment Rules, 2011, in the Directorate General of Health Services, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Drugs Controller (India), in the Central Drugs Standard Control Organisation, Directorate General of Health Services under the Ministry of Health and Family Welfare, namely: -

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Drugs Standard Control Organisation, Drugs Controller (India) (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Central officials did not carry out drug inspections in T.N. for 6 years: Health Minister

Responding to allegations against the T.N. govt. in the cough syrup case, he says two senior drug inspectors from the State have been placed under suspension for failing to conduct yearly checks

The Hindu Bureau
CHENNAI

In a sharp rebuttal to accusations that Tamil Nadu fell short in drug inspections, Health Minister Ma. Subramanian stated that the Central Drugs Standard Control Organisation's (CDSCO) officials had not carried out any inspections in the State for six years.

"It is mandatory to conduct inspections of all drug manufacturing units every year. We have already placed two senior drug inspectors under suspension for failing to conduct these inspections. The Central drug inspectors [of CDSCO functioning under the Union Health Ministry] are required to conduct inspections of such drug manufacturing facilities across India once every three years. However, no inspections were carried out by them in Tamil Nadu over the past six years. Where can we place the blame? We have raised this as well," he told reporters in Chennai on Friday.

He was asked about news reports referring to the 2024 Comptroller and Auditor General of India's "Performance Audit on Public Health Infrastructure and Management of Health Services". The report flagged shortfalls in achievement of targets for inspection and lifting of samples from 2016-21 – ranging from 34% to 40% every year. In reply, Mr. Subramanian said former Chief Minister Edappadi K. Palaniswami should answer as the CAG report pertained to the AIADMK regime between 2016-21. "The police in the State where the incident occurred are responsible for taking action," he said, responding to Mr. Palaniswami's criticism that the Tamil Nadu government was negligent and that it took the Madhya Pradesh police to arrest the company's owner in Tamil Nadu.

This is a national and global public health issue. It is inappropriate to politicise such an issue and turn it into a public discourse. The Leader of the Opposition should understand this
MA. SUBRAMANIAN
T.N. Health Minister

The State Drugs Control Department, on receiving information from Madhya Pradesh on October 1, inspected the facility and took samples of the Coldrif syrup batch for testing. Testing detected the presence of diethylene glycol. The findings were promptly communicated to the Madhya Pradesh government and Union Health Ministry. But both initially said nothing was wrong with the syrup. The State went ahead and issued a 'stop production' order and issued a show cause notice to the manufacturer, Sresan Pharmaceuticals in Sunguvarchatiram in Kancheepuram district. Due to the efforts taken by Tamil Nadu, untoward incidents in many other States have been prevented, he added.

"This is a crucial issue. It concerns the export of drugs from the State. Every year, pharmaceutical products worth ₹12,000 to ₹15,000 crore are exported from Tamil Nadu to nearly 100 countries. There are 397 manufacturing units in the State, and this significant volume of trade comes from around 100 of them. This is a national and global public health issue. It is inappropriate to politicise such an issue and turn it into a public discourse. The Leader of the Opposition should understand this," he said.

On Madhya Pradesh's charge that Tamil Nadu was not cooperating, the Minister said the arrest of the company's owner was made possible only because of the State's efforts in conducting an inspection and detecting contamination in the cough syrup. Commissioner of Food Safety and Drug Administration R. Lalvena is conducting a meeting with drug inspectors to ensure regular inspections, he added.

सीडीएससीओ को नहीं थी जहरीला कफ सीरप 'कोल्ड्रिफ' बनाने वाली फैक्ट्री की जानकारी

नीतू रंजन • जागरण

नई दिल्ली: जहरीले कफ सीरप के चलते मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगभग 29 बच्चों की मौत के मामले में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की हालिया रिपोर्ट ने दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी में गंभीर खामियों को उजागर किया है। विडंबना देखिए, भारत में दवा और चिकित्सा उपकरणों के लिए राष्ट्रीय नियामक सीडीएससीओ को जहरीले कफ सीरप 'कोल्ड्रिफ' और इसे बनाने वाली तमिलनाडु की फैक्टरी श्रीसन फार्मा के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। खुद सीडीएससीओ ने इसे स्वीकार किया है जबकि यह संगठन ही सुनिश्चित करता है कि देश में बेचे जाने वाली सभी दवा और चिकित्सा उपकरण सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण हों। इस बीच बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार कोल्ड्रिफ कफ सीरप के बारे में सीडीएससीओ ने अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी दी है।

नियमों के अनुसार, सभी दवा निर्माताओं को अपने उत्पादों की जानकारी सुगम पोर्टल पर उपलब्ध

राष्ट्रीय नियामक ने 29 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार जहरीले कफ सीरप पर स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट

कोल्ड्रिफ कफ सीरप • रायटर

कराना अनिवार्य है, लेकिन कोल्ड्रिफ के संबंध में ऐसा कुछ नहीं किया गया। इससे यह सवाल उठता है कि और कितनी दवा ऐसी हैं जिनका लाइसेंस तो राज्य सरकारों ने जारी किया है, लेकिन सीडीएससीओ को उनकी जानकारी नहीं दी गई है। जाहिर है देश में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र की जरूरत है।

रिपोर्ट के अनुसार 2011 में तमिलनाडु के खाद्य व औषधि विभाग से लाइसेंस लेकर कोल्ड्रिफ बनाने वाली कांचीपुरम की श्रीसन फार्मा के बारे में सीडीएससीओ को कोई जानकारी नहीं दी गई थी।।

तमिलनाडु के अधिकारी भी बनाए जा सकते हैं आरोपित

राब्यू, नईदुनिया, भोपाल: जहरीले कफ सीरप मामले में तमिलनाडु के अधिकारी भी आरोपित बनाए जा सकते हैं। कांचीपुरम स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल की अनियमितताओं पर तमिलनाडु के औषधि प्रशासन विभाग ने समय रहते ध्यान नहीं दिया। 39 गंभीर अनियमितताओं के बाद भी कंपनी चलती रही।

पिछले 14 वर्षों में सीडीएससीओ ने इस कंपनी का एक बार भी आडिट नहीं किया और उसके डाटाबेस में इसका जिक्र तक नहीं है। दवा निर्माता कंपनियों पर बेहतर निगरानी के लिए सीडीएससीओ ने अक्टूबर 2023 में सभी राज्यों को पत्र भेजकर अपने-अपने यहां चलने वाली सभी इकाइयों की जानकारी देने का अनुरोध किया था। इसके लिए राज्यों को गूगल फार्म भी भेजा गया। सीडीएससीओ के अनुसार, इसके बाद सभी बैठकों में राज्यों को इसकी याद दिलाई गई, फिर भी श्रीसन फार्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली।

और कितने बच्चे मरने पर जागेगा देश

तमिलनाडु स्थित कंपनी श्रीसन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के दूषित कफ सीरप 'कोल्ड्रिफ' के सेवन के बाद मध्य प्रदेश में कम से कम 21 बच्चों की मौत त्रासद है। प्रयोगशाला परीक्षणों में पुष्टि हुई है कि जिस जानलेवा औद्योगिक रसायन डायथिलीन ग्लायकाल (डीईजी) को दवाओं में प्रयोग नहीं करना चाहिए, वही पाया गया है। दुखद यह है कि यह अकेली घटना नहीं है। 2020 में जम्मू-कश्मीर में 12 बच्चे डीईजी से दूषित कफ सीरप के कारण मरे थे। अगस्त 2022 में, उज्बेकिस्तान में 65 बच्चों की जान इसी तरह की त्रासदी में चली गई। इसके कुछ ही महीनों बाद, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गांबिया में भारतीय कफ सीरप से जुड़ी 66 और मौतों की सूचना दी। इन लगातार हो रहे भयावह हादसों के बावजूद, भारत के प्राधिकारी हमारे सबसे दुर्बल और लाचार वर्ग, बच्चों को सुरक्षा देने में लगातार विफल हो रहे हैं। डीईजी विषाक्तता का इतिहास इससे भी पहले 1937 तक जाता है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके कारण 105 मौतें हुई थीं। इसके चलते 1938 में फेडरल फूड, ड्रग, और कास्मेटिक्स एक्ट लागू किया गया था, जिसमें निर्माताओं के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया कि किसी भी दवा को विषाक्तता परीक्षण के बिना बाजार में नहीं लाया जा सकता। बेचने से पूर्व ही निर्माताओं को हर दवा की सुरक्षा स्थापित करनी होगी। तब से अमेरिका में डीईजी विषाक्तता से बड़े पैमाने पर मौतें नहीं हुई हैं। लगभग एक सदी बाद, भारत में इसी तरह की त्रासदियां लगातार हो रही हैं, जो हमारे नियामक ढांचे में गंभीर कमियों को उजागर करती हैं। कोई भी यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि और कितने बच्चों को मरना होगा, तब जाकर

संजय कुंडू
पूर्व पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश

दवा निर्माताओं को भारतीय न्याय संहिता में प्रासंगिक दंडात्मक प्रविधान से जोड़कर पूरी तरह से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। प्रत्येक बैच के लिए प्रमाणित प्रयोगशालाओं में परीक्षण अनिवार्य हो। इसके अलावा नियामक ढांचा और उन्नत बनाया जाए तभी दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।

सबक सीखा जाएगा। आखिर डीईजी जैसे जहरीले रसायन दवाओं में क्यों पाए जाते हैं? उत्तर दुखद किंतु सरल है। लालच और मुनाफा। प्रोपीलीन ग्लायकाल या ग्लिसरीन जैसे फार्मास्यूटिकल-ग्रेड एक्सिपिएंट्स का कफ सीरप में उपयोग अपेक्षित है। इनकी लागत लगभग 160 रुपये प्रति किलोग्राम है। डीईजी ब्रेक फ्लूइड, एंटीफ्रीज, रेजिन और रंगों में इस्तेमाल होने वाला एक घातक औद्योगिक विकल्प है। इसकी लागत केवल 90 रुपये प्रति किलोग्राम है। कुछ निर्माता, कुछ रुपये बचाने के लिए बच्चों की दवाओं की सुरक्षा से समझौता करते हैं। चंद रुपयों के लिए यह लापरवाह और जानलेवा अपराध जारी है। समस्या केवल कुछ खराब कंपनियों तक सीमित नहीं, व्यवस्थागत है। अधिसंख्य दवा निर्माता ड्रग कंट्रोलर जनरल आफ इंडिया द्वारा जारी 2002 के गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिस दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं। यह लगभग असंभव लगता है कि वे 2026 के इन्हीं मानकों को पूरा कर पाएंगे, जिसमें यूरोपीय संघ के मानकों का पालन करना आवश्यक है। कारण स्पष्ट हैं। फार्मा सेक्टर एक कुटीर उद्योग बनता जा रहा है, जिसमें कई प्लांट दो या तीन कमरों से चल रहे हैं। वहां न परिष्कृत सुरक्षा प्रोटोकाल है, न उचित परीक्षण के लिए संसाधन। कफ सीरप, पैरासिटामोल सस्पेंशन और इसी तरह की बच्चों की दवाएं प्रायः इन छोटे ढांचों में तैयार की जाती हैं। कई निर्माता सामग्री और परीक्षण के संबंध में आवश्यक कानूनी मानकों-इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया या यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया का पालन नहीं कर सकते हैं, जिससे इनकी अवहेलना एक व्यवस्थागत समस्या बन जाती है जबकि दवा उद्योग में सुरक्षा से समझौता होना ही नहीं चाहिए।

निर्माताओं के लिए जरूरी है कि वह दवा निर्माण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का हर चरण का रिकार्ड रखें। कई निर्माता जानबूझकर ऐसा करने से बचते हैं। राज्यों के दवा नियंत्रक लाइसेंस जारी करने, निरीक्षण करने और गुणवत्ता की जांच करते समय अक्सर उचित सावधानी नहीं बरतते। कई के पास नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कर्मचारियों, प्रशिक्षण और संसाधनों की कमी है। अधिकारी अक्सर व्यवस्थागत सुधारों के बजाय चिकित्सकों को गिरफ्तार करने, उद्योगों को बंद करने जैसे तात्कालिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

उपाधि केवल उत्पादन-क्षमता से नहीं, एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और विश्वसनीय नियामक तंत्र से मिलती है। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित Writ Petition 106/2026 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किंतु न्यायिक हस्तक्षेप अकेले पर्याप्त नहीं। लोकतांत्रिक जवाबदेही, संसदीय निगरानी और एक सजग नागरिक समाज मिलकर ही उस व्यवस्था को बदल सकते हैं, जो इस तरह के संकटों को जन्म देती है।

"जब तक भारत का दवा नियामक तंत्र संरचनागत रूप से मजबूत, स्वतंत्र और पारदर्शी नहीं होगा, तब तक न MSME सुरक्षित रहेंगे, न जनता और न ही वैश्विक मंच पर भारत की फार्मा साख।" ●

आशा जी की मधुर और सुरमयी आवाज सदा दिलों में अमर रहेगी

● डॉ. ब्रह्मानंद राजपूत

आशा भोंसले जी का नाम भारतीय संगीत इतिहास में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने अपने करियर में आठ दशकों से भी अधिक समय तक संगीत जगत में अमूल्य योगदान दिया है और लगभग 12 हजार से अधिक गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाया है। आशा भोंसले जी, जो भारत की महानतम और दिग्गज गायिकाओं में से एक थीं। आशा जी का नाम संगीत जगत में सदैव एक सिरमौर के रूप में लिया जाएगा। दिनांक 12 अप्रैल 2026 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 92 साल की उम्र में उनका दुखद निधन हो गया। उनके दुखद निधन का समाचार पूरे विश्व के संगीत प्रेमियों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। यह क्षति न केवल भारतीय संगीत जगत के लिए, बल्कि वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी अपूरणीय है। आशा भोंसले जी के जीवन के बारे में बात की जाये तो उनका जन्म 8 सितम्बर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में एक समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक एवं रंगमंच कलाकार थे, जिनसे उन्हें संगीत की प्रारंभिक शिक्षा मिली। बचपन से ही संगीत के वातावरण में पली-बढ़ीं आशा जी ने बहुत कम उम्र में ही गायन प्रारंभ कर दिया। पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उन्होंने किशोरावस्था में ही फिल्मों में गाना शुरू कर दिया और कठिन परिस्थितियों और संघर्षों के बावजूद अपने करियर की मजबूत नींव रखी। उनकी बड़ी बहन सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर विश्व प्रसिद्ध गायिका रहीं, जबकि उनकी अन्य बहनें मीना मंगेशकर और उषा मंगेशकर ने भी संगीत जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार मंगेशकर परिवार ने सामूहिक रूप से भारतीय संगीत को समृद्ध किया और एक अमूल्य सांगीतिक विरासत स्थापित की, जिसका प्रभाव आज भी भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

अपने शुरुआती दौर में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी अदम्य इच्छाशक्ति, मेहनत और प्रतिभा के बल पर उन्होंने धीरे-धीरे संगीत जगत में एक विशिष्ट स्थान बना लिया। उन्होंने ओ. पी. नैयर, आर. डी. बर्मन और खय्याम जैसे महान संगीतकारों के साथ काम करते हुए अनेक अमर गीतों को जन्म दिया। विशेष रूप से आर. डी. बर्मन के साथ उनकी जोड़ी ने हिंदी फिल्म संगीत को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया और कई सदाबहार गीत दिए। आशा जी ने अपने दीर्घ और गौरवशाली संगीत जीवन में भारतीय शास्त्रीय संगीत से लेकर फिल्मी गीतों, गजलों, भजनों और लोकगीतों तक हर शैली में अपनी अद्वितीय छाप छोड़ी। उनकी आवाज की मधुरता, लचीलापन और भावनात्मक अभिव्यक्ति ने उन्हें अन्य गायिकाओं से अलग पहचान दिलाई। उन्होंने हिंदी, मराठी,

बांग्ला, तमिल, गुजराती सहित अनेक भाषाओं में हजारों गीत गाकर विश्वभर में भारतीय संगीत का परचम लहराया। आशा भोंसले जी की असाधारण उपलब्धियों के लिए उन्हें अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्हें पद्म विभूषण, दादासाहेब फाल्के पुरस्कार, तथा कई बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया, जहाँ उन्हें विश्व की सर्वाधिक रिकॉर्डिंग करने वाली गायिकाओं में शामिल किया गया, जो उनके अद्वितीय और विशाल संगीत योगदान का प्रमाण है।

आशा जी और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी का संबंध भारतीय संगीत इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रहा है। दोनों बहनों ने अपने-अपने विशिष्ट अंदाज और आवाज के माध्यम से संगीत जगत में अलग-अलग पहचान बनाई, फिर भी उनके बीच गहरा पारिवारिक और सांगीतिक जुड़ाव बना रहा। जहाँ लता जी को उनकी मधुर और शुद्ध आवाज के लिए जाना जाता था, वहीं आशा जी अपनी बहुआयामी और प्रयोगधर्मी शैली के लिए प्रसिद्ध रहीं। इन दोनों बहनों ने मिलकर भारतीय फिल्म संगीत को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य विरासत छोड़ी। आशा जी के व्यक्तिगत जीवन की बात करें, तो उनका जीवन भी अनेक उतार-चढ़ाव से भरा रहा। 16 साल की उम्र में उन्होंने गणपतराव भोसले से विवाह किया, जो अधिक समय तक सफल नहीं रहा। इसके बाद उन्होंने अपने साहस और आत्मविश्वास के बल पर अपने बच्चों का पालन-पोषण किया। बाद में उनका विवाह महान संगीतकार आर. डी. बर्मन से हुआ, जिनके साथ उनका संबंध न केवल वैवाहिक बल्कि सांगीतिक रूप से भी अत्यंत सफल और प्रेरणादायक रहा। उनके परिवार में उनके बच्चे और पोते-पोतियाँ शामिल हैं, जिनके साथ उनका गहरा स्नेहपूर्ण संबंध रहा। उनकी आवाज केवल गीत नहीं थी, बल्कि भावनाओं का अथाह सागर थी- खुशी, दर्द, प्रेम और जीवन के हर रंग को उन्होंने अपने सुरों में अद्भुत संवेदनशीलता के साथ पिरोया। दशकों तक उन्होंने संगीत जगत पर अपनी अमिट छाप बनाए रखी और हमें अनगिनत यादगार गीतों की अमूल्य धरोहर दी, जो सदैव हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। उन्होंने अपनी मधुर और भावपूर्ण आवाज से कई पीढ़ियों के हृदय को स्पर्श किया तथा भारतीय संगीत को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया। उनके गीत न केवल मनोरंजन का माध्यम रहे, बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त स्वर भी बने, जो उन्हें सदैव हमारे बीच जीवित रखेंगे। आज का दिन हर भारतीय, विशेषकर संगीत प्रेमियों के लिए अत्यंत दुखद है। आशा जी ने न केवल अपनी सुरमयी आवाज से एक विशिष्ट पहचान बनाई, बल्कि अपने सुरों के माध्यम से भारतीय संगीत को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया। हर तरह के संगीत में ढल जाने की उनकी अनोखी प्रतिभा ने उन्हें युगों-युगों तक अमर बना दिया है। उनके गाए हुए गीत आज भी हर दिल में जीवित हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। आशा जी भले ही आज हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन उनका संगीत सदैव अमर रहेगा और उनके सुर हमेशा हमारे दिलों में गूंजते रहेंगे।●

1857 की क्रांति की अनसुनी आवाज

वीरांगना अवंतीबाई लोधी

● डॉ. ब्रह्मानंद राजपूत

आज भी भारत की पवित्र भूमि ऐसे वीर-वीरांगनाओं की कहानियों से भरी पड़ी है जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश के आजाद होने तक भिन्न- भिन्न रूप में अपना अहम योगदान दिया। लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने हमेशा से उन्हें नजरअंदाज किया है। देश में सरकारों या प्रमुख सामाजिक संगठनों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों के जो कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके अहम योगदान को न तो सरकारें याद करती हैं न ही समाज याद करता है। लेकिन उनका योगदान भी देश के अग्रणी श्रेणी में गिने जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से कम नहीं है। जितना योगदान स्वतंत्रता संग्राम में देश के अग्रणी श्रेणी में गिने जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का था, उतना ही उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान है जिनको हमेशा से इतिहासकारों ने अपनी कलम से वंचित और अछूत रखा है। भारत की पूर्वाग्रही लेखनी ने देश के बहुत से त्यागी, बलिदानियों, शहीदों और देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर-वीरांगनाओं को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की पुस्तकों में उचित सम्मानपूर्ण स्थान नहीं दिया है। परन्तु आज भी इन वीर-वीरांगनाओं की शौर्यपूर्ण गाथाएं भारत की पवित्र भूमि पर गूंजती हैं और उनका शौर्यपूर्ण जीवन प्रत्येक भारतीय के जीवन को मार्गदर्शित करता है।

ऐसी ही 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक वीरांगना हैं रानी अवंतीबाई लोधी जिनके योगदान को हमेशा से इतिहासकारों ने कोई अहम स्थान न देकर नाइंसाफी की है। आज देश में बहुत से लोग हैं जो इनके बारे में जानते भी नहीं है। लेकिन उनका योगदान भी 1857 के स्वाधीनता संग्राम की अग्रणी नेता वीरांगना झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई जी से कम नहीं हैं। लेकिन इतिहासकारों की पिछड़ा और दलित विरोधी मानसिकता ने हमेशा से इनके बलिदान और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को नजरअंदाज किया है। परन्तु वीरांगना

अवंतीबाई लोधी आज भी लोककाव्यों की नायिका के रूप में हमें राष्ट्र के निर्माण, शौर्य, बलिदान व देशभक्ति की प्रेरणा प्रदान कर रही हैं। लेकिन हमारे देश की सरकारों ने चाहे केंद्र की जितनी सरकारे रही हैं या राज्यों की जितनी सरकारें रही हैं उनके द्वारा हमेशा से वीरांगना अवंतीबाई लोधी की उपेक्षा होती रही है। वीरांगना अवंतीबाई जितने सम्मान की हकदार थीं वास्तव में उनको उतना सम्मान नहीं मिला। वीरांगना अवंतीबाई लोधी का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष एवं बलिदान से सम्बन्धित ऐतिहासिक जानकारी समकालीन सरकारी पत्राचार, कागजातों व जिला गजेटियरों में बिखरी पड़ी है। इन ऐतिहासिक समकालीन सरकारी पत्राचार, कागजातों व जिला गजेटियरों का संकलन और ऐतिहासिक विवेचन समय की माँग है। देश की केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को इस ऐतिहासिक जानकारी और सामग्री का संकलन करना चाहिए और उसकी व्याख्या आज के इतिहासकारों से करानी चाहिए।

वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी का जन्म पिछड़े वर्ग के लोधी राजपूत समुदाय में 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनकेहणी, जिला सिवनी के जमींदार राव जुझार सिंह के यहां हुआ था। वीरांगना अवंतीबाई लोधी की शिक्षा दीक्षा मनकेहणी ग्राम में ही हुई। अपने बचपन में ही इस कन्या ने तलवारबाजी और घुड़सवारी करना सीख लिया था। लोग इस बाल कन्या की तलवारबाजी और घुड़सवारी को देखकर आश्चर्यचकित होते थे। वीरांगना अवंतीबाई बाल्यकाल से ही बड़ी वीर और साहसी थी। जैसे-जैसे वीरांगना अवंतीबाई बड़ी होती गयीं वैसे-वैसे उनकी वीरता के किस्से आसपास के क्षेत्र में फैलने लगे।

पिता जुझार सिंह ने अपनी कन्या अवंतीबाई लोधी का सजातीय लोधी राजपूतों की रामगढ़ रियासत, जिला मण्डला के राजकुमार से करने का निश्चय किया। जुझार सिंह की इस साहसी बेटी का रिश्ता रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह ने अपने पुत्र राजकुमार राजकुमार विक्रमादित्य सिंह के लिए स्वीकार कर लिया। इसके बाद जुझार सिंह की यह साहसी कन्या रामगढ़ रियासत की कुलवधू बनी। सन् 1850 में रामगढ़ रियासत के राजा और वीरांगना अवंतीबाई लोधी के ससुर लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई और राजकुमार विक्रमादित्य सिंह का रामगढ़ रियासत के राजा के रूप में राजतिलक किया गया। लेकिन कुछ सालों बाद राजा विक्रमादित्य सिंह अस्वस्थ्य रहने लगे। उनके दोनों पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह अभी छोटे थे, अतः राज्य का सारा भार रानी अवंतीबाई लोधी के कन्धों पर आ गया। वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने वीरांगना झाँसी की रानी की तरह ही अपने पति विक्रमादित्य के अस्वस्थ होने पर ऐसी दशा में राज्य कार्य संभाल कर अपनी सुयोग्यता का परिचय दिया और अंग्रेजों की चूलें हिला कर रख दीं।

इस समय लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डलहौजी का प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था। उसके काल मे राज्य विस्तार का काम अपने चरम पर था। भारत में लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियों और उसकी राज्य हड़प नीति की वजह से देश की रियासतों में हल्ला मचा हुआ था। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प

नीति के अन्तर्गत जिस रियासत का कोई स्वाभाविक बालिग उत्तराधिकारी नहीं होता था ब्रिटिश सरकार उसे अपने अधीन कर रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में उसका विलय कर लेती थी। इसके अलावा इस हड़प नीति के अंतर्गत डलहौजी ने यह निर्णय लिया कि जिन भारतीय शासकों ने कंपनी के साथ मित्रता की है अथवा जिन शासकों के राज्य ब्रिटिश सरकार के अधीन है और उन शासकों के यदि कोई पुत्र नहीं है तो वह बिना अंग्रेजी हुकूमत कि आज्ञा के किसी को गोद नहीं ले सकता। अपनी राज्य हड़प नीति के तहत डलहौजी कानपुर, झाँसी, नागपुर, सतारा, जैतपुर, सम्बलपुर, उदयपुर, करौली इत्यादि रियासतों को हड़प चुका था। रामगढ़ की इस राजनैतिक स्थिति का पता जब अंग्रेजी सरकार को लगा तो उन्होंने रामगढ़ रियासत को 'कोर्ट ऑफ वार्डस' के अधीन कर लिया और शासन प्रबन्ध के लिए एक तहसीलदार को नियुक्त कर दिया। रामगढ़ के राज परिवार को पेन्शन दे दी गई। इस घटना से रानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी काफी दुखी हुई, परन्तु वह अपमान का घूँट पीकर रह गई। रानी उचित अवसर की तलाश करने लगी। मई 1857 में अस्वस्थता के कारण राजा विक्रमादित्य सिंह का स्वर्गवास हो गया। सन 1857 में जब देश में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तो क्रान्तिकारियों का सन्देश रामगढ़ भी पहुंचा। रानी तो अंग्रेजों से पहले से ही जली भुनी बैठी थीं क्योंकि उनका राज्य भी झाँसी और अन्य राज्यों की तरह कोर्ट कर लिया गया था और अंग्रेज रेजिमेंट उनके समस्त कार्यों पर निगाह रखे हुई थी। रानी ने अपनी ओर से क्रान्ति का सन्देश देने के लिए अपने आसपास के सभी राजाओं और प्रमुख जमींदारों को चिट्ठी के साथ कांच की चूड़ियां भिजवाई उस चिट्ठी में लिखा था- ''देश की रक्षा करने के लिए या तो कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो तुम्हें धर्म ईमान की सौगंध जो इस कागज का सही पता बैरी को दो।''

सभी देश भक्त राजाओं और जमींदारों ने रानी के साहस और शौर्य की बड़ी सराहना की और उनकी योजनानुसार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। जगह-जगह गुप्त सभाएं कर देश में सर्वत्र क्रान्ति की ज्वाला फैला दी। इस बीच कुछ विश्वासघाती लोगों की वजह से रानी के प्रमुख सहयोगी नेताओं को अंग्रेजों द्वारा मत्यु-दंड दे दिया गया। रानी इससे काफी दुखी हुई। रानी ने अंग्रेजी शासन के विरुध्द विद्रोह कर दिया और रानी ने अपने राज्य से कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधिकारियों को भगा दिया और राज्य एवं क्रान्ति की बागडोर अपने हाथों में ले ली। ऐसे में वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी मध्य भारत की क्रान्ति की प्रमुख नेता के रूप में उभरी। रानी के विद्रोह की खबर जबलपुर के कमिश्नर को दी गई तो वह आग बबूला हो उठा। उसने रानी को आदेश दिया कि वह मण्डला के डिप्टी कलेक्टर से भेट कर ले। अंग्रेज पदाधिकारियो से मिलने की बजाय रानी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उसने रामगढ़ के किले की मरम्मत करा कर उसे और मजबूत एवं सुदृढ़ बनवाया। मध्य भारत के विद्रोही नेता रानी के नेतृत्व में एकजुट होने लगे। अंग्रेज रानी और मध्य भारत के इस विद्रोह से चिंतित हो उठे। वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने अपने साथियों के सहयोग से हमला बोल कर घुघरी, रामनगर, बिछिया इत्यादि क्षेत्रों से अंग्रेजी राज का सफाया कर दिया। इसके पश्चात् रानी ने मण्डला पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इस युध्द में वारांगना अवंतीबाई लोधी की मजबूत क्रान्तिकारी सेना और अंग्रेजी सेना में जोरदार मुठभेड़ें हुई। इस युध्द में रानी और मण्डला के डिप्टी कमिशनर वाडिंगटन के बीच सीधा युध्द हुआ जिसमे वाडिंगटन का घोडा बुरी तरह घायल हो गया उसका घोडा गिरने ही वाला था तब तक वाडिंगटन घोड़े से कूद गया और वीरांगना अपने घोड़े को तेज भगाते हुए उस पर टूट पड़ी। बीच में तलवार लेकर एक सिपाही उसे बचाने के लिए आ कूदा। उसने रानी के वार को रोक लिया अन्यथा वाडिंगटन वहीं समाप्त हो गया होता। मण्डला का डिप्टी कमिशनर वाडिंगटन भयभीत होकर भाग चुका था और मैदान रानी अवंतीबाई लोधी के नाम रहा। इसके बाद मंडला भी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के अधिकार में आ गया और रानी ने कई महीनों तक मंडला पर शासन किया।

मण्डला का डिप्टी कमिशनर वाडिंगटन लम्बे समय से रानी से अपने अपमान का बदला लेने को आतुर था और वह हर हाल में अपनी पराजय का बदला चुकाना चाहता था। इसके बाद वाडिंगटन ने अपनी सेना को पुनर्गठित कर रामगढ़ के किले पर हमला बोल दिया। जिसमे रीवा नरेश की सेना भी अंग्रेजों का साथ दे रही थी। रानी अवंतीबाई की सेना अंग्रेजों की सेना के मुकाबले कमजोर थी, लेकिन फिर भी वीर सैनिकों ने साहसी वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का जमकर मुकाबला किया। लेकिन ब्रिटिश सेना संख्या बल एवं युद्ध सामग्री की तुलना में रानी की सेना से कई गुना बलशाली थी अत: स्थिति को भांपते हुए रानी ने किले के बाहर निकल कर देवहारगढ़ की पहाडियों की तरफ प्रस्थान किया। रानी के रामगढ़ छोड़ देने के बाद अंग्रेजी सेना ने रामगढ़ के किले बुरी तरह ध्वस्त कर दिया और खूब लूटपाट की। इसके बाद अंग्रेजी सेना रानी का पता लगाती हुई देवहार गढ़ की पहाडियों के निकट पहुंची, यहाँ पर रानी ने अपने सैनिकों के साथ पहले से ही मोर्चा जमा रखा था। अंग्रेजो ने रानी के पास आत्मसमर्पण का सन्देश भिजवाया, लेकिन रानी ने सन्देश को अस्वीकार करते हुए सन्देश भिजवाया कि लड़ते-लड़ते बेशक मरना पड़े लेकिन अंग्रेजों के भार से दबूंगी नहीं। इसके बाद वडिंगटन ने चारों तरफ से रानी की सेना पर धावा बोला। कई दिनों तक रानी की सेना और अंग्रेजी सेना में युद्ध चलता रहा जिसमे रीवा नरेश की सेना अंग्रेजों का पहले से ही साथ दे रही थी। रानी की सेना बेशक थोड़ी सी थी लेकिन युध्द में अंग्रेजी सेना की चूलें हिला के रख दी थी। इस युध्द में रानी की सेना के कई सैनिक हतायत हुए और रानी को खुद बाएं हाथ में गोली लगी, और बन्दूक छूटकर गिर गयी। अपने आप को चारों ओर से घिरता देख वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने रानी दुर्गावती का अनुकरण करते हुए अपने अंगरक्षक से तलवार छीनकर स्वयं तलवार भोंक कर देश के लिए बलिदान दे दिया। उन्होंने अपने सीने में तलवार भोंकते वक्त कहा कि ''हमारी दुर्गावती ने जीते जी वैरी के हाथ से अंग न छुए जाने का प्रण लिया था। इसे न भूलना।'' उनकी यह बात भी भविष्य के लिए अनुकरणीय बन गयी। वीरांगना अवंतीबाई का अनुकरण करते हुए उनकी दासी ने भी तलवार भोंक कर 20 मार्च 1858 को वीरांगना अवंतीबाई लोधी के साथ अपना बलिदान दे दिया और भारत के इतिहास में इस वीरांगना अवंतीबाई ने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिख दिया।

जब रानी वीरांगना अवंतीबाई अपनी मृत्युशैया पर थीं तो इस वीरांगना ने अंग्रेज अफसर को अपना बयान देते हुए कहा कि ''ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मैंने ही विद्रोह के लिए उकसाया, भड़काया था उनकी प्रजा बिलकुल निर्दोष है।'' ऐसा कर वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने हजारों लोगों को फांसी और अंग्रेजों के अमानवीय व्यवहार से बचा लिया। मरते-मरते ऐसा कर वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने अपनी वीरता की एक और मिसाल पेश की। नि:संदेह वीरांगना अवंतीबाई का व्यक्तिगत जीवन जितना पवित्र, संघर्षशील तथा निष्कलंक था, उनकी मृत्यु (बलिदान) भी उतनी ही वीरोचित थी। धन्य है वह वीरांगना जिसने एक अद्वितीय उदहारण प्रस्तुत कर 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में 20 मार्च 1858 को अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसी वीरांगना का देश की सभी नारियों और पुरुषों को अनुकरण करना चाहिए और उनसे सीख लेकर नारियों को विपरीत परिस्थितियों में जज्बे के साथ खड़ा रहना चाहिए और जरूरत पड़े तो अपनी आत्मरक्षा अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वीरांगना का रूप भी धारण करना चाहिए। 20 मार्च 2026 को ऐसी आर्य वीरांगना के 168वें बलिदान दिवस पर उनको शत-शत् नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ●

(स्वतंत्र लेखक का आलेख)

समस्तीपुर का प्रकाश पुंज

मिट्टी की सोंधी खुशबू से बिहार के क्षितिज तक आदित्य का सफर

● **मिथिलेश कुमार**

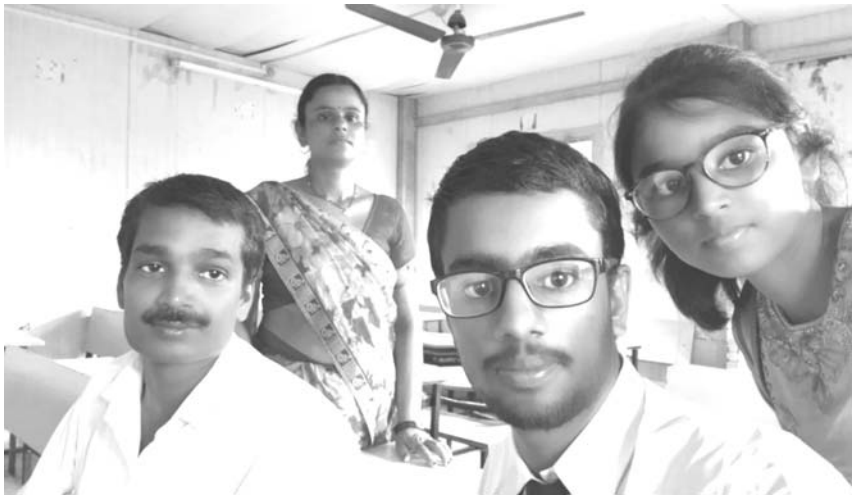

जब गांव की मिट्टी की सोंधी खुशबू दिल में उतरती है, तो एक अजीब सा सुकून मिलता है। लेकिन जब उसी माटी से निकली प्रतिभा शहरों की चकाचौंध को मात देकर 'दिव्य प्रकाश' बन जाए, तो उसकी लौ की दिव्यता देखते ही बनती है। गांव की पगडंडियों और तंग गलियों से लंबी कुलांचे भरकर सपनों को ऊंची उड़ान देने वाले युवा आज न केवल बिहार, बल्कि देश के क्षितिज पर अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं बिहार के समस्तीपुर जिले की, जिसकी उर्वर धरती ने एक बार फिर अपनी मेधा का परचम लहराया है। दलसिंहसराय प्रखंड के मुख्तियारपुर सलखनी गांव के होनहार छात्र आदित्य प्रकाश अमन ने इंटर साइंस परीक्षा में पूरे बिहार में प्रथम स्थान हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार, बल्कि समस्तीपुर के गौरव को हिमालय जैसी ऊंचाई दी है। परिणाम घोषित होते ही गांव से शहर तक खुशी की लहर दौड़ गई; हर ओर जश्न का माहौल है और लोग इस 'माटी के लाल' की सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं।

☞ **परंपरा बनी मिसाल :-** पिछले तीन वर्षों से समस्तीपुर के छात्र मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में निरंतर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आदित्य ने इस बार 'बिहार टॉपर' बनकर इस परंपरा को और भी सुदृढ़ कर दिया है। उनकी सफलता यह प्रमाणित करती है कि छोटे शहरों और गांवों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस सही मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत की। साधारण परिवार से आने वाले आदित्य की यह उपलब्धि वास्तव में असाधारण है।

☞ **साधारण परिवेश, असाधारण संस्कार :-** आदित्य प्रकाश अमन एक अत्यंत साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके दादा-दादी किसान रहे, जिन्होंने मिट्टी से जुड़कर मेहनत करना सिखाया। कुशवाहा समाज से आने वाले आदित्य के पिता हरेंद्र कुमार एक सरकारी शिक्षक हैं, जिन्होंने अपने पिता के किसान होने के संघर्ष को समझा और शिक्षा को अपना हथियार बनाया। आज हरेंद्र कुमार ने अपने पुत्र को उस मुकाम पर पहुँचा दिया है, जिससे उनके पिता (आदित्य के दादा) का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। माता एक कुशल गृहिणी हैं, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद घर में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

आदित्य अपनी इस ऐतिहासिक सफलता का संपूर्ण श्रेय अपने माता-पिता को देते हैं। उनका कहना है कि मेरे पिता ही मेरे सबसे बड़े गुरु और मार्गदर्शक हैं। उनका अनुशासन और पढ़ाई के प्रति समर्पण ही मेरी प्रेरणा बना। परिवार का अटूट विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत रही।

☞ **सफलता का त्रिकोण :-** मेहनत, लेखन शैली और आत्मविश्वास। अपनी तैयारी की रणनीति पर चर्चा करते हुए आदित्य बताते हैं कि उन्होंने नियमित रूप से 8 से 10 घंटे पढ़ाई की। उन्होंने विशेष रूप से अपनी 'राइटिंग स्किल' (लेखन शैली) पर ध्यान केंद्रित किया। उनका मानना है कि परीक्षा में सफलता के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि उत्तर को प्रभावी और सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है। आदित्य को परीक्षा के बाद यह तो आभास था कि वे 'टॉप टेन' में स्थान बनाएंगे, लेकिन बिहार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना उनके लिए एक सुखद विस्मय रहा। वेरिफिकेशन कॉल के समय उन्हें क्षणिक संदेह भी हुआ, लेकिन जब परिणाम की पुष्टि हुई, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर विजय की मुस्कान थी।

☞ **सिमुलतला : वह पाठशाला जिसने गढ़ी सफलता की इबारत :-** आदित्य की सफलता की नींव जमुई स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय में पड़ी, जहां उन्होंने कक्षा 6 से 10 तक शिक्षा प्राप्त की। विद्यालय के पूर्व अतिथि शिक्षक डॉ. नयन तिवारी के अनुसार, आदित्य में बाल्यकाल से ही धैर्य, अनुशासन, ईमानदारी और प्रबल जिज्ञासा जैसे गुण विद्यमान थे। मैट्रिक में 'टॉप टेन' से मामूली अंतर से चूक जाने वाले आदित्य ने इंटर साइंस में 'टॉपर' बनकर यह सिद्ध कर दिया कि यदि प्रयास निरंतर और दिशा सही हो, तो सफलता का मिलना सुनिश्चित है। आदित्य प्रकाश अमन की यह उपलब्धि पूरे बिहार के छात्रों के लिए एक मशाल की तरह है। यह स्पष्ट संदेश देती है कि मेहनत, लगन और सही दिशा में किया गया सार्थक प्रयास किसी भी दुर्गम लक्ष्य को हासिल करने की एकमात्र कुंजी है।●

चूहे-बिल्ली का खेल समाप्त करें : न्यायाधीश

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

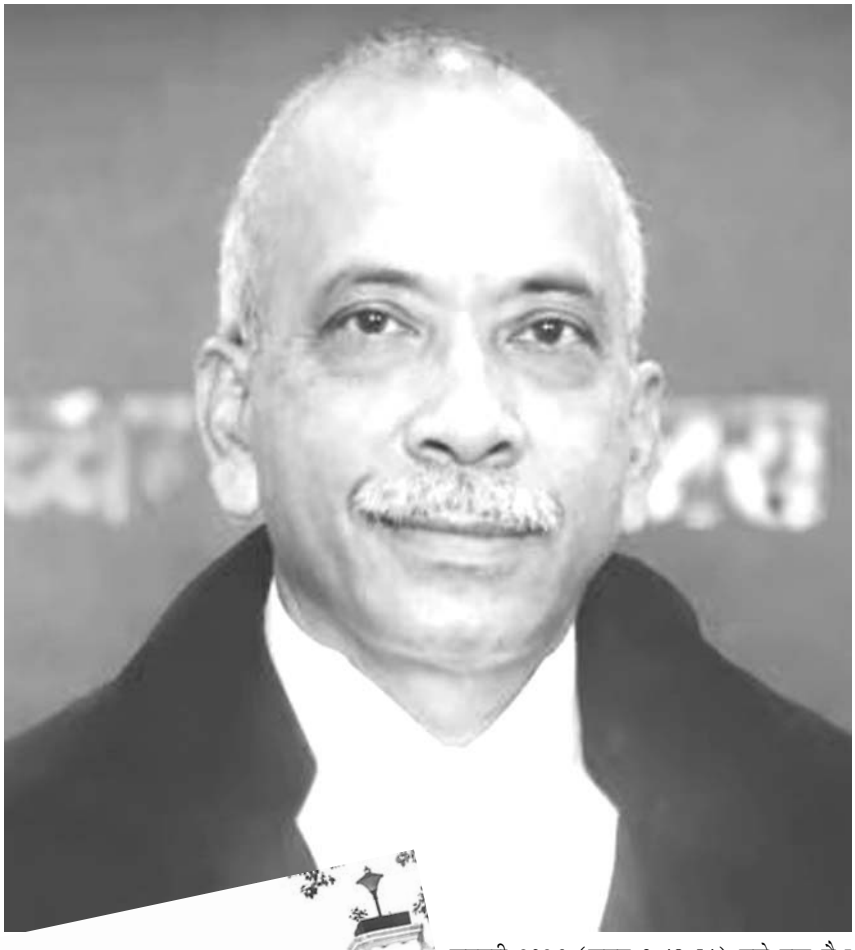

पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव रॉय ने सख्त निर्देश दिया है कि वाहन रोकने से जब्ती प्रक्रिया तक की वीडियोग्राफी करें अफसर। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए दूरगामी प्रभाव डालने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि खनन अधिकारियों द्वारा वाहनों की कि जाने वाली सभी जब्तियों की पूरी वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। कोर्ट ने सरकार तथा वाहन मालिकों के बीच चल रहे चूहे बिल्ली के खेल को समाप्त करने का निर्देश दिया है। खनन अधिकारियों द्वारा वाहन को रोककर जब्त किए जाने के मामले में वाहन मालिक द्वारा दायर कोर्ट ने सुनवाई करते याचिका पर कोर्ट ने निर्देश दिया। जस्टिस राजीव रॉय की एकलपीठ ने टिप्पणी की कि प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक युग में जब हर चीज पल भर में उपलब्ध है, तो ऐसे अभियानों को अंजाम देने वाले अधिकारियों से कम से कम यह अपेक्षा की जाती है कि वे वाहन को रोकने से लेकर जब्त करने तक की पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी करें, जैसा कि पश्चिमी देशों में किया जाता है। कोर्ट ने अपने फैसले मे कहा कि, इस लुका-छिपी के खेल को समाप्त करने के लिए यह कोर्ट बिहार के खान एवं खनिज विभाग को निर्देश देता है कि वे अपने सभी जमीनी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें कि पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी किया जाए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि इन उपायों को अपनाने से कोर्ट के समक्ष राज्य की सफलता दर में भी सुधार होगा। यदि वे वीडियो फुटेज के माध्यम से यह साबित करने में सक्षम होते हैं कि जब्ती की गई है। यह मामला मनोज कुमार मेहता द्वारा दायर एक दीवानी क्षेत्राधिकार मामले से उत्पन्न हुआ है, जिसका

ट्रक 11 जनवरी को नवादा में खनन अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि वाहन झारखंड से पूर्वी चंपारण तक पत्थर के टुकड़े ले जा रहा था और जब्ती की रात लगभग वैध चालान भी था। हालांकि, खनन विभाग के वरिष्ठ विशेष वकील नरेश दीक्षित ने दावा किया कि वाहन को रात करीब 10 बजे बिना किसी दस्तावेज के रोका गया था। दीक्षित ने कोर्ट को बताया कि अदालत में पेश किया गया चालान जब्ती होने के बाद ही प्राप्त किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता शंभू नारायण सिंह ने बताया कि एक उचित प्राधिकारी ने 11 जनवरी 2026 को रात 8:45:54 बजे चालान जारी किया था, जो 13 जनवरी 2026 (सुबह 3:48:54) बजे तक वैध था। नरेश दीक्षित ने बताया कि वाहन बिना किसी चालान के पाया गया।

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि उसके सामने अक्सर ऐसे मामले आते हैं। जहां वाहन मालिक, खनन अधिकारी का एक ही रुख होता है। जहां उनका तर्क है कि वैध चालान प्रस्तुत किया गया था, फिर भी वाहन को जब्त कर लिया गया जबकि प्रतिवादियों का कहना है कि मांगने कोई कागज चालान प्रस्तुत नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक युग में अधिकारियों से न्यूनतम अपेक्षा यही की जाती है कि वे पूरी जब्ती प्रक्रिया की विडियोग्राफी कराए। अगर ऐसा किया जाता है तो किसी भी पक्ष को दस्तावेजों की जब्ती, अंतग्रहण, मांग, जब्ती के संबंध में कोई शिकायत या बचाव का रास्ता नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी उन आरोपों से भी मुक्त रहेगा, जो आमतौर पर पीड़ित पक्षों द्वारा लगाए जाते हैं।●

नाराज कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री का फूंका पुतला

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई कथित टिप्पणी से मसौढ़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश दिखा। बीते दिनो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान विरोध मार्च निकालते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। मसौढ़ी एवं धनरूआ प्रखंड कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस विरोध कार्यक्रम का नेतृत्व बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस कमिटी के प्रदेश महासचिव मो० अरफराज साहिल ने किया। कार्यकताओं ने मेन रोड से कर्पूरी चौक तक आक्रोश मार्च निकाला और नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। इस मौके पर धनरूआ प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष मृत्युंजय पांडेय, मृत्युंजय पेरियार, अमित कुमार, धुरी यादव, शिवपूजन सिंह, इंद्रमणि देवी, सोहन चंद्रवंशी, रवीन्द्रधारी

बिंद आदि मौजूद रहे और अपनी आवाजों को विरोध प्रदर्शन में बुलंद किए।●

● श्रीकांत कुमार श्रीवास्तव

पटना सहित पूरे बिहार में बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। पटना हाइकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय पुलिस प्रशासन पर कड़ी नाराजगी जतायी है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बोर्ड प्रदूषण को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रहा है। कोर्ट ने इस मामले में पटना के छः थानाध्यक्षों को अगली सुनवाई में तलब किया है। जस्टिस राजीव रॉय की एकलपीठ ने सुरेन्द्र प्रसाद द्वारा इस गंभीर मामले को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शहर में शोर-शराबे (ध्वनि प्रदूषण) की खतरनाक स्थिति पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि शादी समारोहों और जुलूसों में डीजे और लाउडस्पीकर का बेधड़क इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ अधिवक्ता शिवेंद्र किशोर ने कोर्ट को बताया कि मैरेज हॉलों को नोटिस जारी किये गये हैं। निर्माण सामग्री ढ़ोने के लिए 'ग्रीन नेट' का नियम बनाया गया है। इस मामले में सहयोग करने के लिए न्यायमित्र अधिवक्ता अजय ने कोर्ट को बताया कि स्थानीय निकायों के साथ

समन्वय का कोई पुख्ता रिकॉर्ड बोर्ड के पास नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने राजधानी पटना के छः थानों द्वारा जमा की गयी रिपोर्ट पर भी असंतोष व्यक्त करते हुए कदमकुआं, पीरबहोर, आलमगंज, रूपसपुर, गांधी मैदान, और बुद्ध कॉलोनी के थाना प्रभारियों को इस मामले में की गयी कार्रवाइयों की रिपोर्ट के साथ 19 जून को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है। कोर्ट ने इसके अलावा राजीव नगर और छपरा सदर के थानाध्यक्षों को भी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। पुलिस की निष्क्रियता पर कोर्ट ने एक सुझाव देते हुए कि अक्सर बारात या धार्मिक जुलूस के बीच में कार्रवाई करने से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए पुलिस को चाहिए कि नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे और लाउडस्पीकर की पहले वीडियोग्राफी कर ली जाये। जैसे ही जुलूस या कार्यक्रम समाप्त हो, उस वीडियो साक्ष्य के आधार पर संबंधित पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। सुनवाई के दौरान वकीलों ने कोर्ट का ध्यान पटना सिटी, भूतनाथ रोड और अन्य इलाकों में चलने वाले टेंपो और इ. रिक्शा की ओर भी खीचा। कोर्ट को बताया गया कि इन वाहनों में चालक तेज आवाज मे अश्लील गाने बजाते हैं, जिससे महिला और बुजुर्गों को भारी असुविधा होती है।●

पटेल का नाम सुनते ही क्यों भड़कती है भाजपा?

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

बिहार की राजनीति इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ नारे और सच्चाई के बीच की दूरी साफ दिखाई देने लगी है। मंचों से "जीरो टॉलरेंस" का ढोल पीटा जाता है, लेकिन जमीन पर भ्रष्टाचार और अपराध की खबरें लगातार जनता को झकझोर रही हैं। भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की राजनीति में झूठे नारों की भरमार है, लेकिन सच्चाई स्वीकार करने वाले लोग गिने-चुने ही दिखाई देते हैं। डॉ० पटेल ने कहा कि बिहार भाजपा का हाल ऐसा हो गया है कि "पटेल" नाम सुनते ही कुछ नेताओं का चेहरा वैसे ही तमतमा उठता है जैसे लाल कपड़ा देखकर भैंसा भड़क जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जहाँ पटेल समाज को धीरे-धीरे किनारे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झूठे "जीरो टॉलरेंस" के नारे लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बिहार को अपराध की नगरी और भ्रष्टाचार का साम्राज्य बनने से रोकने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। समाज में बेटियों के साथ हो रही शर्मनाक घटनाएँ हर संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देती हैं, पर सत्ता के गलियारों में बयानबाजी का शोर सच्चाई को दबाने की कोशिश करता दिखाई देता है। डॉ पटेल ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के शिल्पकार भारत के लौहपुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल का नाम आज केवल भाषणों में लिया जाता है। उनके आदर्शों को अपनाने की बजाय उन्हें राजनीतिक नारों और प्रतीकों तक सीमित कर दिया गया है। (नरेगा)

: मजदूरों के नाम पर पैसा निकलता है, लेकिन गरीब मजदूर आज भी काम के लिए भटकता है। गरीब के घर का सपना दलालों और कमीशनखोरी के जाल में फँसता दिखाई देता है। बेरोजगारों युवाओं को रोजगार का सपना दिखाने वाली मुंद्रा योजना आखिर किस कब्र में दफन हो गई, यह सवाल बेरोजगार युवाओं के मन में गूंज रहा है।

☞ **"पटेल संस्कार बनाम सत्ता का अहंकार"** :- डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में पटेल समाज के संस्कार देखे हैंख्अन्याय के सामने झुकना नहीं, सत्य के लिए लड़ना और समाज के सम्मान के लिए खड़ा होना। उन्होंने कहा कि अगर समाज में बेटियों की अस्मिता सुरक्षित नहीं है, गरीब को उसका अधिकार नहीं मिल रहा और बेरोजगार युवक दर-दर भटक रहा है, तो केवल "जीरो टॉलरेंस" का नारा लगाना जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार की जनता अब सब कुछ समझने लगी है। जनता अब केवल भाषण नहीं, परिणाम चाहती है। अगर राजनीति सचमुच सरदार पटेल की विरासत का सम्मान करना चाहती है तो उसे उनके सिद्धांतों, साहस, ईमानदारी और राष्ट्रहितख्पर चलना होगा। बिहार की राजनीति के सामने आज सबसे बड़ा सवाल यही है-क्या "जीरो टॉलरेंस" केवल मंचों का नारा रहेगा या वास्तव में भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी? डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल का यह बयान न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर रहा है बल्कि यह भी याद दिला रहा है कि जब सत्ता और व्यवस्था सच्चाई से मुंह मोड़ लेती है, तब समाज के भीतर से ही आवाज उठती है और वही आवाज आज पूछ रही है। क्या बिहार में सच बोलना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया है?●

ऐसा भ्रष्टाचार शायद दुनिया में अजूबा, गर्लफ्रेंड के लिए महल

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भ्रष्टाचार के खिलाफ "जीरो टॉलरेंस" का नारा आज की राजनीति का सबसे बड़ा और आकर्षक वादा बन चुका है। मंचों से लेकर सभाओं तक यह दावा किया जाता है कि अब व्यवस्था में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जब वही व्यवस्था बार-बार ऐसे मामलों से घिर जाती है जहाँ सत्ता और पद का इस्तेमाल कर अकूत संपत्ति खड़ी होने के आरोप सामने आते हैं, तो यह नारा खुद ही सवालों के घेरे में आ जाता है। हाल की छापेमारी में सामने आई संपत्तियों और दस्तावेजों ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर "जीरो टॉलरेंस" की असली तस्वीर क्या है। आरोप यह है कि पद और प्रभाव का उपयोग कर संपत्ति केवल अपने नाम पर ही नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड के नाम पर भी खड़ी की जाती रही। यह स्थिति केवल कानून या नियमों का उल्लंघन भर नहीं है, बल्कि उस भरोसे पर भी चोट है जो आम जनता व्यवस्था से करती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब व्यवस्था के भीतर ही ऐसे मामले सामने आते हैं तो ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। जिन लोगों ने पूरी सेवा ईमानदारी से निभाई, उनके लिए ऐसे मामले शर्मिंदगी और पीड़ा का कारण बनते हैं। भ्रष्टाचार का हर नया खुलासा इस सच्चाई को उजागर करता है कि व्यवस्था को केवल नारों से नहीं बल्कि कठोर और निष्पक्ष कार्रवाई से साफ किया जा सकता है। आज जरूरत केवल दोषियों को पकड़ने की नहीं, बल्कि उस तंत्र को मजबूत करने की है जो भ्रष्टाचार को पनपने ही न दे। जब तक जवाबदेही स्पष्ट नहीं होगी और पारदर्शिता व्यवस्था का मूल आधार नहीं बनेगी, तब तक "जीरो टॉलरेंस" जैसे नारे जनता के बीच भरोसे के बजाय व्यंग्य का विषय बनते रहेंगे। जनता अब केवल वादों और नारों से संतुष्ट नहीं है।●

जीरो टॉलरेंसर का नारा या सत्ता की लाज छिपाने का हथकंडा?

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

आज का समय विरोधाभासों का समय है। मंचों पर नैतिकता की बातें होती हैं, सभाओं में ईमानदारी के नारे गूंजते हैं और सत्ता के गलियारों में "जीरो टॉलरेंस" का डंका पीटा जाता है। लेकिन जब जमीनी हकीकत देखी जाती है तो अपराध, भ्रष्टाचार और सत्ता का अहंकार पहले से ज्यादा बेलगाम दिखाई देता है। तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या यह "जीरो टॉलरेंस" वास्तव में व्यवस्था को शुद्ध करने का संकल्प है, या सिर्फ सत्ता की लाज छिपाने का एक राजनीतिक आवरण?

इतिहास और महाभारत हमें चेतावनी देते हैं कि जब शासन व्यवस्था पर कीतपजंतीजतं जैसी मानसिकता हावी हो जाती है, तब सच बोलने वालों की आवाज दबा दी जाती है। आंखों के सामने अन्याय होता है, मगर सत्ता उसे देखना नहीं चाहती। आज भी कई बार लगता है कि व्यवस्था उसी अंधेपन से ग्रस्त है जहाँ अपराध दिखता है, पर स्वीकार नहीं किया जाता; भ्रष्टाचार सामने है, मगर कार्रवाई की इच्छा नहीं दिखाई देती। सबसे बड़ा संकट तब पैदा होता है जब समाज की कलम दरबारों में गिरवी रख दी जाती है। पत्रकारिता और लेखनी का धर्म सत्ता की चापलूसी करना नहीं, बल्कि जनता के दर्द और सच्चाई को सामने लाना है। दुर्भाग्य से आज कुछ कलमें दरबारों में बिक चुकी हैं। वे सवाल पूछने के बजाय सत्ता के गीत गाने में लगी हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि सच्ची कलम कभी झुकती नहीं। सच बोलने वाली कलम ही लोकतंत्र की असली प्रहरी होती है। वह अपराध को अपराध कहती है, भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार कहती है और डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखती है। क्योंकि जब कलम डर जाती है, तब लोकतंत्र कमजोर हो जाता है।

भारत के इतिहास में ऐसे अनेक व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने सत्ता से ऊपर राष्ट्रहित को रखा। उनमें सबसे प्रेरणादायक नाम है भारत के लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल का। उन्होंने अपने कठोर संकल्प, स्पष्ट नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति से यह सिद्ध किया कि देशहित के सामने कोई भी सत्ता या स्वार्थ बड़ा नहीं हो सकता। आज जब हर तरफ नारों की राजनीति चल रही है, तब यह जरूरी है कि सच बोलने की परंपरा को जीवित रखा जाए। लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। सच बोलने वाली आवाजें देर-सवेर व्यवस्था को आईना दिखाती ही हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं वह कलम नहीं हूँ जो दरबारों में बिक जाए। मैं सच का राजदूत हूँ, झुकना मुझे आता नहीं। देश जले और मैं चुप रहूँ, इतनी सस्ती मेरी कलम नहीं। मैं डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखता हूँ, क्योंकि यह कलम सत्ता की नहीं, जनता की पहरेदार है और यह भी स्पष्ट कर दूँ, मैं सिर्फ "पटेल" लिखता नहीं हूँ। मैं स्वयं को भारत के लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की विरासत से जुड़ा मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं डॉ. लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल हूँ और मेरी कलम सत्ता से नहीं, सत्य से समझौता करती है। जब तक समाज में अन्याय रहेगा, तब तक यह कलम सवाल पूछती रहेगी। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं, बल्कि सच लिखने वाली कलम होती है।●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/8340360961

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।